प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

धर्म के बाद खेल ही नैतिकता का सबसे महान शिक्षक है।
-हर्बर्ट हूवर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अमेजन के भारत में निवेश पर सवाल उठाने के बहाने छोटे व्यापारियों के हितों से जुड़ी जो चिंताएं जाहिर की हैं, वे सहज ही हैं। लेकिन ई-कॉमर्स सेवाएं आज जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में, जरूरी है कि बाजार के तौर-तरीके इस तरह निर्धारित हों कि हितों का टकराव ही न हो।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सवाल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की भारत में एक अरब डॉलर के निवेश की घोषणा पर सवाल उठाने के बहाने देश के करोड़ों छोटे विक्रेताओं के हित में जो चिंताएं जाहिर की हैं, वे सहज ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ई-कॉमर्स कंपनियां हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा क्यों बनी हुई हैं। आज छोटी-छोटी जगहों, जहां कोई ढंग का स्टोर भी नहीं है, के लोग विश्वस्तरीय ब्रांड के कपड़े व अन्य वस्तुएं मंगा रहे हैं। किताबों की दुकानें बेशक सीमित हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे विज्ञापनों को देखकर लोग मनचाही पुस्तकें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो इसका श्रेय ई-कॉमर्स कंपनियों को जाता है। शुरुआत में कहा जाता था कि भारत में ई-कॉमर्स कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय हाथ से छूकर वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अब कपड़ों से लेकर भोजन और किराने के सामान तक हर चीज के लिए लोग ई-कॉमर्स कंपनियों को वरीयता दे रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। शहरीकरण ने इसे और बढ़ावा दिया है। अब तो कई खुदरा व्यवसायी तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में ई-कॉमर्स जैसी सेवाएं दे रहे हैं। जाहिर है कि ई-कॉमर्स क्रांति ने जीने के तरीकों को बदल दिया है। दूसरी तरफ, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की चिंता दरअसल इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में छोटे खुदरा विक्रेताओं और किराना दुकानदारों की एक बड़ी संख्या है, जो पारंपरिक रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन इनके पास संसाधन सीमित हैं, जिससे वे ई-कॉमर्स दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। एक चिंता यह भी है कि जो लोग डिजिटल क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकते, उनके पिछड़ने से समाज में असमानता और संघर्ष की स्थिति बन सकती है। केंद्रीय मंत्री का यह कहना भी गंभीर है कि अमेजन भारत में जो निवेश कर रहा है, वह उस घाटे की भरपाई के लिए है, जो उसे बाजार पर आधिपत्य

जमाने के लिए कम कीमत पर वस्तुओं को बेचने से हुआ है। किसी भी किस्म का एकाधिकार नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में, यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्वस्थ बाजार वही है, जो सामूहिक शक्ति दे, जिसमें लाभ उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता, तीनों में बराबर बंटें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। ई-कॉमर्स को जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन इसकी वृद्धि को इस ढंग से नियंत्रित व विनियमित किए जाने की जरूरत है, ताकि डिजिटल व पारंपरिक व्यापारियों के बीच संतुलन बना रहे।

दो मांओं से सबक लें राजनेता

जहां राजनेता और कूटनीतिज्ञ विफल हो गए, वहीं रजिया परवीन और सरोज देवी सफल हुईं। वास्तव में इस खेल कूटनीति को बचाकर रखा जाना चाहिए। विभाजन के बाद भी अब जब भारत और पाकिस्तान दो पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं, हमारे ऐतिहासिक संबंध हमें अब भी बांधे हुए हैं।

वास्तव में जब भी पेरिस ओलंपिक, 2024 को भारत और पाकिस्तान में याद किया जाएगा, तो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की मांओं के प्यार और बड़े दिल के कारण उसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। पेरिस ओलंपिक को इन दोनों मांओं की सहज भावनाओं के जरिये सभी खेल कूटनीति के लिए भी याद किया जाएगा, जिसने उन्हें भारत और पाकिस्तान, दोनों प्रतिद्वंद्वी पड़ोसियों में बहुत सम्मान दिलाया। असलियत तो यह है कि इन दो मांओं ने जो किया, उसे देखकर आश्चर्य होता है कि दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रालय क्या करने में विफल रहे हैं।

दिल्ली और इस्लामाबाद, दोनों जगहों पर उच्चायोग होने के बावजूद इन दो साधारण ग्रामीण महिलाओं ने जिस तरह दोनों तरफ नफरत और असहिष्णुता की दीवारें गिराकर प्यार और विश्वास का माहौल बनाया, वह दोनों मुल्कों के राजनयिक नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, दोनों ही पंजाबी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल पाकिस्तान में मीडिया हमेशा अरशद नदीम से मैदान पर उनके भारतीय प्रतिद्वंद्वी नीरज चोपड़ा के साथ उनकी दोस्ती के बारे में पूछता रहता था और यह भी कि वे दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। अपने-अपने मुल्कों के झंडों को अपने कंधों पर लपेटे हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे यह संदेश मिलता है कि भले ही आप दो अलग-अलग मुल्कों से हों, फिर भी आप दोस्ती का आनंद ले सकते हैं। क्या नीरज और अरशद के वर्षों से अच्छे मित्र बने रहने का कारण यह है कि वे दोनों पंजाबी हैं और अपनी मातृभाषा में बात करने से उनकी दोस्ती मजबूत हुई?

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर, जिन्हें पाकिस्तान में उनके लेखन और टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ने इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि दोनों माताओं के बीच अपने बेटे के प्रतिद्वंद्वी के प्रति इतना प्यार इसलिए

दिखा, क्योंकि वे दोनों पंजाबी हैं और यह जातीयता उन्हें एक साथ ले आई। उन्होंने बेहद खूबसूरत लफ्जों में कहा कि 'वे अपने बेटे के प्रतिद्वंद्वी को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखती हैं, क्योंकि उन्हें 'पंजाबी' जुड़ाव महसूस होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उनके बोलने के तरीके में उल्लेखनीय समानता को स्पष्ट करता है। अरशद की मां रजिया परवीन ने कहा, 'मैं भी नीरज के लिए प्रार्थना करती हूं, वह भी हमारे बेटे जैसा है।' नीरज की मां सरोज देवी ने भी लगभग यही बात कही, 'जिसने स्वर्ण पदक जीता, वह भी हमारा बच्चा है और जिसने रजत पदक जीता, वह भी हमारा बच्चा है।'

किसी ओलंपिक में दशकों बाद पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद पाकिस्तान अब भी जश्न मना रहा है। जैवलिन एथलीट अरशद नदीम का अब भी पाकिस्तान में स्वागत किया जा रहा है। बहुत से लोग उन्हें पैसे, घर, कार और जमीनों से नवाज रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राजकीय भोज में उनके परिवार को शामिल करने के लिए एक विशेष विमान उनके पंजाबी गांव मियां चन्नू भेजा। राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों समेत सभी प्रमुख व्यक्तियों ने उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। लेकिन इन सब पर भारी रजिया परवीन और सरोज देवी रहीं, जो वहां सफल हुईं, जहां राजनेता और कूटनीतिज्ञ विफल हो गए। वास्तव में इस खेल कूटनीति को बचाकर रखा जाना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए।

उल्लेखनीय है कि विभाजन के बाद भी अब जब भारत और पाकिस्तान दो पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हैं, फिर भी हमारे ऐतिहासिक संबंध, जो हमें अब भी बांधे हुए हैं, कभी-कभी सामने आ जाते हैं। इस संबंध में हाल ही में *द न्यूज इंटरनेशनल* में जनरल एल एड्रोस के पोते की एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है, जिसने पुरानी यादें ताजा कर दीं। हो सकता है, *अमर उजाला* के बुजुर्ग पाठकों को स्वर्गीय मेजर जनरल सैयद अहमद अल एड्रोस याद हों, जिनका जुलाई 1962 में बंगलूरू में निधन हो गया था। उनका संबंध भारत के उस प्रांत से है, जो बिरयानी के लिए मशहूर है। जी हां, वर्ष 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के समय वह हैदराबाद राज्य बल के कमांडर-इन-चीफ थे। लेकिन 13 सितंबर, 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया। और भारतीय सेना को हैदराबाद के निजाम के राज को खत्म करने में सिर्फ चार दिन लगे थे। 17 सितंबर को निजाम की सेना के कमांडर मेजर जनरल सैयद अहमद एल एड्रोस ने हार स्वीकार कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल अल एड्रोस ने भारत में ही रहने का फैसला किया, जबकि उनके तीन बच्चों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, और दिलचस्प बात यह है कि वे मेरे परिवार के बहुत करीबी दोस्त बन गए। वास्तव में जनरल अल एड्रोस की एक पोती और मैं एक साथ बड़ी हुई और हम सबसे अच्छे दोस्त थे।

अपने पत्र में अल एड्रोस की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते ने लिखा है, 'कई वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई है। इसलिए रिश्तों में जमी इस बर्फ को पिघलाने और खेल भावना को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार को भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को पाकिस्तान आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस यात्रा कार्यक्रम में अरशद नदीम के गांव मियां चन्नू को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि दोनों के माता-पिता एक-दूसरे से मिल सकें और एक-दूसरे का अभिवादन कर सकें। हमें नीरज चोपड़ा की मां की सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम से अपने बेटे की हार के बाद भी कहा था कि वह नीरज के रजत पदक जीतने से खुश हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाला अरशद नदीम भी हमारे बेटे जैसा ही है और ओलंपिक में पहुंचने वाले सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है।'

भारत और पाकिस्तान, दोनों सरकारों को इन दोनों खिलाड़ियों और उनके परिवारों को राजकीय अतिथि के रूप में अपने-अपने देशों में आमंत्रित करना चाहिए। मैं अपने भारतीय पाठकों को आश्वस्त कर सकती हूं कि नीरज चोपड़ा का पाकिस्तानियों द्वारा एक नायक के रूप में स्वागत किया जाएगा और दोनों माताएं इतिहास रचेंगी। इंशाल्लाह!

edit@amarujala.com

जीवन धारा

दलाई लामा

दुख का अंत करने के लिए जरूरी है कि हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर नहीं भागें। अपितु हमें रुक कर खुद से पूछना चाहिए कि यह इच्छा क्यों है? इच्छाओं का आतंरिक कारण क्या है?

हमारी इच्छाओं में ही छिपा है दुखों का कारण

धरती पर शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा, जिसके जीवन में दुख न हो। दुख तो जीवन का हिस्सा ही है। जहां जीवन है, वहां सुख और दुख, दोनों विद्यमान हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में दुख है, तो उसका कारण क्या है। दुख आया है, तो क्यों? अगर हम दुखों का कारण खोज लेते हैं, तो सुख के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दुख से मुक्ति की दिशा में पहला प्रयास यही होना चाहिए कि कभी भी उसे हम अपने पर हावी न होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई रास्ता, तो अवश्य होता ही है। इसलिए जब तक हम दुख के कारणों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हम सुख से वंचित रहते हैं। अगर हम दुख में भी अपने को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो दुख अपने आप ही कम पड़ने लगता है। दुख का शाब्दिक अर्थ है जीवन अपर्याप्त है। यह एक ऐसा चक्र है, जो निरंतर घूमता रहता है और व्यक्ति को सुख-दुख में घुमाता रहता है। व्यक्ति सुख के क्षणों में रह कर उसका ऐसा आदी होने लगता है कि वह दुख से दूर भागने लगता है। और इस प्रकार वह भूल जाता है कि दुख भी उसके जीवन का हिस्सा है। ऐसे में जीवन में जब दुख की घड़ियां आती हैं, तो हम डरने लग जाते हैं। उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, खुशी की ओर लौटने को व्याकुल हो उठते हैं। लेकिन इसमें सबको को तो सफलता नहीं मिल पाती। यही कारण है कि हम अपने को और ज्यादा दुख की ओर धकेल देते हैं।

मनुष्य के जीवन में तीन तरह के दुख प्रमुख हैं। पहला तो है शारीरिक कष्टों से उपजी पीड़ा, जो अपरिहार्य है। इसे टाला नहीं जा सकता। इसमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आते हैं। दूसरा होता है मानसिक दुख या पीड़ा, जिसमें ईर्ष्या, जलन, उदासी, विषाद, क्रोध, निर्दयता, हिंसा जैसी भावनाएं और अनुभूतियां हमारे भीतर जन्म लेती हैं और पीड़ित करती रहती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं और उनकी ही देन होती हैं। इस तरह का दुख हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। जो बात किसी के लिए दुख का कारण बन सकती है, हो सकता है वह किसी और के लिए सुख का कारण बन जाती हो। और तीसरे प्रकार का दुख जरा जटिल और गूढ़ है, जो मनुष्य के जीवित रहने की कठिनाई, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में फंसे रहने और ब्रह्मांड की समग्रता से अलग-थलग होने से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुसार, दुख का अंत केवल दो तरीकों से हो सकता है। पहला तो यही कि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करे, हालांकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकतीं, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। और दूसरा तरीका है कि हम अपनी इन इच्छाओं की प्रकृति को समझें। हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागने के बजाय हमें रुक कर खुद से पूछना चाहिए कि हमें यह इच्छा क्यों है? हमारी इच्छाओं का आतंरिक कारण क्या है?

मध्य मार्ग अपनाएं

सूत्र

इच्छाएं और दुख वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इच्छाएं आसक्ति पैदा करती हैं और आसक्ति से दुख पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा की सम्मोहक शक्ति से मुक्त हो जाता है, तो वह व्यावहारिक रूप से सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यही बिंदु निर्वाण कहलाता है। इसलिए मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

दूसरा पहलू

पटना में गंगा किनारे 1917 में मिली लगभग दो हजार साल पुरानी प्रतिमा के रहस्य अब भी अनसुलझे हैं।

कौन है वह अप्रतिम सुंदरी यक्षिणी या गणिका

वह साल 1917 था, जब पटना के पास दीदारगंज में गंगा किनारे नारी सौंदर्य की प्रतिमान लगभग पांच फुट ऊंची प्रतिमा मिली थी। इसे नाम दिया गया दीदारगंज की यक्षी। अप्रतिम सौंदर्य वाली नारी की यह मूर्ति फिलहाल पटना के राजकीय संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। इतिहासकारों में बहस है कि यह प्रतिमा किसी यक्षिणी की है या गणिका की। ज्यादातर इतिहासकारों की राय में यह उर्वरता की प्रतीक यक्षी है, तो कुछ इसे गणिका यानी शाही दरबार की परिचारिका की प्रतिमा मानते हैं। इसकी वजह प्रतिमा के हाथ में चंवर का होना है। एक और बहस इसके काल को लेकर है। कुछ इतिहासकार इसे मौर्य काल की नायाब कारीगरी का नमूना मानते हैं, तो कुछ की नजर में यह कुषाण काल की है।

भूपेंद्र कुमार

इतिहासकारों में पांच फुट ऊंची नारी की सुंदर प्रतिमा को लेकर आज तक बहस जारी है कि यह किसी यक्षिणी की है या फिर गणिका की।

आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है, जो इसे खास बनाता है। यह प्रतिमा चुनार की हल्की लाल आभा लिए एक ही पत्थर से बनी है। लगभग दो हजार साल बाद भी इसकी चमक बेमिसाल है। मूर्ति कैसे मिली, इसकी भी दो दास्तान हैं। दीदारगंज में 18 अक्तूबर, 1917 को मौलवी काजी सैयद अजीमुल गंगा के तट पर चक्की के पाट के लिए पत्थर खोज रहे थे, तभी यह मूर्ति बाहर निकल आई। कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने देवी मानकर इसकी पूजा करने के लिए कामचलाऊ मंदिर बना दिया। इसकी जानकारी इतिहासकार प्रो. जेएस समद्दार को मिली, तो उन्होंने मूर्ति को मंगवाया, साफ कराया। उन्होंने पटना म्यूजियम कमेटी के अध्यक्ष ईएचसी वेल्श और ख्यातिनाम पुरातत्ववेत्ता डॉ. डीबी स्पूनर से मूर्ति के महत्व पर चर्चा की। इसके बाद इसे संग्रहालय में स्थापित किया।

प्रतिमा के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1986 में इंडिया फेस्टिवल के दौरान इसे न्यूयॉर्क भेजा गया था।

दूसरी कहानी है कि एक धोबी गंगा किनारे पत्थर पर कपड़े धो रहा था। पत्थर के नीचे एक सांप घुस गया। उसने लोगों की मदद से पत्थर को सीधा किया, तो यक्षिणी की प्रतिमा का पता चला। प्रतिमा के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1986 में इंडिया फेस्टिवल के दौरान जब इसे न्यूयॉर्क भेजा गया, तो यह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिमा की नाक टूट गई, जो फिर ठीक नहीं हो पाई। तब इसे कहीं भी नहीं भेजने का फैसला भारत सरकार ने किया। मूर्ति के काल को लेकर बहस दिलचस्प है। शुरू में इसे मौर्य काल (322 से 185 ईसा पूर्व) का माना गया। इतिहासकारों के अनुसार इतनी विकसित कला सम्राट अशोक के काल में ही संभव थी। बाद में कुछ इतिहासकारों ने इसे पहली शताब्दी में कुषाण काल की बताया। इसकी वजह मूर्ति का केश विन्यास है। घुंघराले बालों को जिस तरह से बांधा गया है, ऐसा मध्य एशिया की महिलाएं करती थीं।

आंकड़े

घटते पीसीओ

एक समय था, जब पीसीओ बूथों के बाहर फोन करने वालों की कतार लगी होती थी, लेकिन मोबाइल के आने से भारत में इनकी संख्या घट रही है।

2006	53.02
2008	50.98
2012	14.11
2016	4.91
2024	0.21

पीसीओ के आंकड़े लाख में हैं। | स्रोत : TRAI

श्रीराम काल से वार्ता कर रहे थे और किसी का भी अंदर जाना निषेध था। लेकिन पूरे कुल को शाप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि को श्रीराम से मिलवा दिया।

लक्ष्मण ने नहीं की प्राणों की परवाह

लक्ष्मण कुल से क्षत्रिय और शेष जी के अवतार थे। बालपन से ही सदा भगवान राम के साथ रहते थे और छाया की भांति उनका अनुसरण करते थे। उनके लिए श्रीराम ही माता-पिता, गुरु, स्वामी, बड़े भाई और इष्टदेव सब कुछ थे। वह श्रीराम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे, *'गुरु पितु मातु न जानौं काहू।'* संसार में प्रेम के जितने संबंध हैं, उन सबको वह श्रीराम के अंदर ही देखते थे।

एक बार साक्षात काल तापस का रूप धारणकर श्रीराम से मिलने अयोध्या आए, लेकिन इस शर्त पर वार्ता के लिए तैयार हुए कि यदि हम दोनों की बातचीत के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो उसे प्राणदंड दिया जाए। लक्ष्मण जी द्वारपाल थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। उन्होंने श्रीराम से मिलने की इच्छा प्रकट की और लक्ष्मण के निषेध करने पर बोले कि यदि इसी क्षण मुझे श्रीराम से नहीं मिलने दोगे, तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को शाप देकर नष्ट कर दूंगा। परिवार को शाप न मिले, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह न कर दुर्वासा को श्रीराम से मिलवा दिया। भगवान राम ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वशिष्ठ आदि ऋषियों की अनुमति से लक्ष्मण का वध न करके उनका परित्याग कर दिया, क्योंकि राम से दूर रहना लक्ष्मण के लिए मृत्युदंड से भी बढ़कर था। इस प्रकार लक्ष्मण ने आजन्म भगवान राम की सेवा कर अंत में उन्हीं के लिए उनका वियोग भी स्वीकार किया।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 24 अक्तूबर, 1957

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सीरिया ने कहा-मध्यस्थता स्वीकार नहीं

मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहस के बाद सीरिया द्वारा तुर्किये के विरुद्ध की गई शिकायत पर विचार करना स्थगित कर दिया। सीरिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर प्रहार करते हुए कहा कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे।

दुनिया की भूख मिटाने को तैयार भारत

भारत ने कृषि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और पिछले 10 वर्षों से दुनिया के खाद्य कटोरे के रूप में रेखांकित हो रहा है।

जयंतीलाल भंडारी

बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है और वह वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 65 वर्ष पूर्व जब यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था, उस समय भारत की खाद्य सुरक्षा विश्व के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन अब वैश्विक खाद्य संकट की चुनौतियों के बीच भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को खाद्य पदार्थों के निर्यातक देश के रूप में रेखांकित हो रहा है। साथ ही कोरोना काल से लगातार 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में अनाज देने की भारत की पहल दुनिया भर में रेखांकित हो रही है। वर्ष 2023 में भारत ने करीब 50 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और दुनिया का आठवां बड़ा कृषि निर्यातक देश बन गया है।

इन दिनों वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रकाशित हो रहीं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत की नई अहमियत पता चल रही है। इस समय जब रूस-यूक्रेन युद्ध, इस्राइल-हमास युद्ध और अन्य भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक खाद्य संकट गहराता जा रहा है, तब दुनिया के अनेक देशों को खाद्य संकट से निपटने और उनकी खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत एक मददगार देश बना हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि कृषि व्यवस्था को बदलना समय की मांग है। देश के किसान भारत को विश्व की ऑर्गेनिक फूड बास्केट बना सकते हैं और विश्व के देशों के लिए भारत मददगार हो सकता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न वैश्विक संगठनों द्वारा भारत की खाद्य सुरक्षा की सराहना की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश ने कृषि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। खासतौर से पिछले 10 वर्षों में कृषि विकास के अभूतपूर्व प्रयासों से अब भारत दुनिया के खाद्य कटोरे के रूप में पहचान बना रहा है। कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। भारतीय कृषि में 90 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम जमीन है और ये छोटे किसान भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए फसलों की 1,900 नई जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराई गई हैं। भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने मोटे अनाज को श्रीअन्न का नाम देकर इसे एक लाभदायक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है।

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित नौ उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र भी शामिल है। बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए बजट में सरकार उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख फसलों का, जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख टन अनुमानित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में दूध, दालों और मसालों का नंबर एक उत्पादक है। इसके अलावा, देश खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऐसे में जब देश में खाद्यान्न उत्पादन ऊंचाई बना रहा है, तब खाद्यान्न भंडारण की अधिक क्षमता भी जरूरी है। अभी 12 से 14 फीसदी तक अन्न बर्बाद हो जाता है। देश में भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन की है, उसे 2,150 लाख टन किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ती हुई वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा जरूरतों के बीच देश में सरकार के द्वारा अधिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रणाली मॉडल पर केंद्रित जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, हरित और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वित्तपोषण, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए अधिक निवेश, समावेशी कृषि मूल्य शृंखलाएं, कृषि-खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए नई-उभरती डिजिटल तकनीकों की, भूमि के डिजिटलीकरण के लिए खेती में ड्रोन को बढ़ावा, कृषि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत साझेदारी और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों की डगर पर आगे बढ़ने की कारगर रणनीति अपनाई जाएगी।

सम्पादकीय

विकृति के विरुद्ध, कोलकाता के बाद महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की जरूरत

कोलकाता के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश उभरा है। वहां के एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर लोगों का रोष फट पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल गठित कर दिया, मगर प्रशासन के रवैए पर प्रश्नचिह्न बना हुआ है। घटना आठ-नौ दिन पहले की है। जब बच्चियों के परिजनों को पता चला कि स्कूल के ही एक कर्मचारी ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, तो उन्होंने पुलिस के पास संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाही। मगर पाक्सो अधिनियम का मामला होने के बावजूद उनकी शिकायत लिखने में टालमटोल की गई। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। यही रवैया कोलकाता मामले में भी देखा गया था। वहां भी प्राथमिकी देर से दर्ज कराई गई। पिछले करीब एक पखवाड़े से देश के विभिन्न हिस्सों से बलात्कार, यौन उत्पीड़न और नृशंस हत्या की घटनाएं रोज ही सामने आ रही हैं। बदलापुर के बाद अकोला में भी छह बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ऐसी घटनाओं से महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों और प्रशासनिक सतर्कता पर स्वाभाविक ही सवाल गहरे हुए हैं। बलात्कार, डरा-धमका कर किए जाने वाले यौन शोषण, राह चलते छेड़खानी आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर आपराधिक वृत्ति के लोगों में उनका खौफ इसलिए नहीं पैदा हो पा रहा कि उन कानूनों पर संजीदगी से अमल नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया प्रायः टालमटोल का ही देखा जाता है। अगर यौन उत्पीड़न का मामला समाज के निचले कहे जाने वाले वर्ग की महिला से जुड़ा हो, तो पुलिस का प्रयास अक्सर समझा-बुझा कर रफा-दफा करने का होता है।

निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को काफी सख्त बनाया गया था। बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े पाक्सो कानून में तो तत्काल गिरफ्तारी और जमानत तक न मिलने का प्रावधान है। मगर इन कानूनों का ठीक से पालन न हो पाने के कारण ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में बढ़ती यौन विकृति और हिंसक वृत्ति की अनेक वजहें हैं, जिनमें से इंटरनेट पर परोसी जाने वाली उत्तेजक और हिंसापूर्ण सामग्री का बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसी सामग्री पर रोक लगाने के उपाय करने की मांग उठती रही है। मगर, प्रशासनिक शिथिलता इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जा सकती है। हमारे देश में यौन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों में परिजन खुद चुप्पी साध जाते हैं। जो मामले पुलिस तक पहुंचते भी हैं, उनमें दोषियों को सजा दिलाने में तत्परता नहीं दिखाई जाती। जांच और गवाहियों में वर्षों लग जाते हैं। बहुत सारे मामलों में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण देखा जाता है। इसलिए चर्चित मामलों में भी न्याय मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। करीब बत्तीस वर्ष पहले हुए अजमेर के ऐसे ही यौन उत्पीड़न मामले में अब दोषियों को सजा सुनाई जा सकी है। उसमें डरा-धमका कर सौ महिलाओं का यौन शोषण किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें लोगों का गुस्सा फूटा, उन्हें लेकर खूब चर्चा हुई।

जम्मू-कश्मीर बना अब नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा लिए रण का मैदान

सूत्रों के मुताबिक, उमर पीडीपी से नाता जोड़ने के खिलाफ हैं। वह तर्क यह दे रहे हैं कि घाटी में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपील की है कि अगर महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आगे आती हैं, तो उस सूरत में उमर उन्हें सम्मानजनक सीटें देकर गठबंधन में शामिल कर लें।सूत्रों ने बताया कि तीनों दलों के गठबंधन को लेकर अभी बातचीत जारी है। अगर पीडीपी को साथ लाने पर बात नहीं बनी तो भी कांग्रेस महबूबा की बेटी इल्तिजा के खिलाफ उम्मीदवार न देने और कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फेंडली फाइट के पक्ष में है। हालांकि इसे अभी शुरुआती बातचीत ही कहा जा रहा है।

अशोक भाटिया

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुके है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव तो पांच साल बाद ही हो रहे हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों को दस साल बाद अपने राज्य की विधानसभा चुनने का अवसर मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण के बाद पहली बार वहां होने वाले इन विधानसभा चुनावों पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि इस अनुच्छेद को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पेश किया था जिसके माध्यम से सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था । जाहिर सी बात है कि आसन्न चुनावों के बाद गठित होने वाली विधानसभा का स्वरूप दस वर्ष पूर्व निर्वाचित विधान सभा से काफी अलग होगा। यह भी यहां विशेष उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब पांच वर्षों का होगा जबकि इसके 2014 के चुनावों तक यह 6 वर्षों का हुआ करता था। चूंकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इसलिए वहां वहां राज्यपाल की जगह अब उपराज्यपाल होंगे। वर्तमान में मनोज सिंहा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 2014 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटों के लिए मतदान हुआ था जिनमें जम्मू की 37, कश्मीर घाटी की 46 और लद्दाख की 4 सीटें शामिल थीं।परिसीमन के बाद हो रहे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों में अब 90 सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा। इनमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटें शामिल हैं। लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा। चुनावों कि घोषणा होते ही अब नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम दल जीत का परचम लहराने के लिए मुस्तैदी से जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू-कश्मीर में पर्दे के पीछे नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है।कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है, ताकि [illegible]। गठबंधन का स्वरूप बना रहे।

कांग्रेस इस समय कश्मीर के चुनावों को लेकर असंजस में भी है । सूबे की सियासत में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन गुलाम नबी आजाद के अलग होने के बाद पार्टी के पास घाटी में न कोई कद्दावर चेहरा बचा और न ही संगठन। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जम्मू-कश्मीर में जीरो पर सिमट जाने के चलते कांग्रेस के लिए इस विधानसभा चुनाव में चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं।कांग्रेस का सियासी आधार कश्मीर में लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसके चलते ही उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है। हालांकि कांग्रेस के लिए पीडीपी और एनसी के साथ दोस्ती तथा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरा कर चुके हैं। इस दौरान गठबंधन से लेकर सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने का टास्क उनके ऊपर है। कांग्रेस के बिना जम्मू-कश्मीर में गठबंधन की सियासी राह आसान नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में साल दर साल कमजोर होती जा रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े तस्दीक देते हैं, जो कांग्रेस पार्टी एक समय यहां पर निर्णायक भूमिका निभाती थी, अब वह स्थानीय पार्टी के रहमो करम पर खड़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 12 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसमें जम्मू संभाग में पांच, कश्मीर संभाग में चार और लद्दाख में तीन सीटें मिली थी। अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऐसे में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। गुलाम नबी आजाद ने अब कांग्रेस से आजाद हो चुके हैं और अपनी अलग पार्टी बना ली है। इस तरह कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके पास जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और परिसीमन के बाद सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। अब राज्य की सियासत में जम्मू का इलाका भी निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है, क्योंकि अब वहां पर सीटें बढ़ गई हैं। जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 विधानसभा सीटें है। कांग्रेस का सियासी आधार एक समय जम्मू इलाके में हुआ करता था, जिस पर अब भाजपा ने अपनी जड़ें जमा ली है। 2014 के बाद से जम्मू क्षेत्र में भाजपा काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भाजपा का अकेले चुनावी मुकाबला करना आसान नहीं रहा है। भाजपा अपनी जीत पक्की करने के लिए अपने पुराने खिलाडी को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी राम माधव बनाया है। उनके मैदान मई आते ही चुनावी फिजा का रंग बदल गया है । 60 साल के संघ परिवार के नेता फिर 2020 के बाद में फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। भाजपा ने दोबारा से आरएसएस के उस नेता पर भरोसा जताया है, जिसने पार्टी को जम्मू-कश्मीर में अपने पैर जमाने में मदद की थी। यहां पर पार्टी का ज्यादा असर नहीं होता था।

पार्टी ने अपने सबसे जरूरी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें फिर से जम्मू-कश्मीर में भेजा है। पार्टी के एक सूत्र ने यह भी कहा कि यह एक मुश्किल भरा काम है और माधव अपनी एबिलिटी को साबित कर सकते हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि भाजपा जम्मू में अपना ठीक-ठाक असर रखती है। यहां पर 90 में से 43 सीटें हैं। घाटी के अंदर सही से संबंध बनाए बिना पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। पार्टी के आलाकमान को इस बात का भरोसा है कि माधव इसके लिए बिल्कुल ही सटीक उम्मीदवार रहेंगे ।माधव ने ही साल 2015 में भाजपा और पीडीपी के बीच में समझौता करवाया था। इसी के बाद दोनों पार्टियों ने गठबंधन से सरकार बनाई थी। यह जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सत्ता का पहला और अकेला कार्यकाल था। बढ़ते तनाव की वजह से पार्टी का अलायंस 2019 में टूट गया और तब से ही जम्मू-कश्मीर केंद्र के शासन में है। सत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत के बाद सिक्योरिटी और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए माधव को वापस लाने और उन्हें जम्मू-कश्मीर चुनाव का प्रभार देने का फैसला किया है ।

शख्सियत

कुछ कर गुजरने का जज्बा ही हमें भीड़ से अलग बनाता है, हम कौन हैं, क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं ये परिचय हमारे कर्म देते है

शशांक झालानी
युवा समाजसेवी व उद्योगपति

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के सुपर डुपर हीरो हैं युवा समाजसेवी और उद्योगपति शशांक झालानी । 2014 में अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पिता बाबू झालानी द्वारा लगाए गए सीबा मसाला उद्योग रूपी वृक्ष को वटवृक्ष बनाने में बेहद महती भूमिका निभाते हुए जहां एक सफल उद्योगपति के रूप में नजर आए वही युवा समाजसेवी के रूप में भी समाज के युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं। उम्र भले ही कम है लेकिन काम करने का जोश, जज्बा,उमंग और उल्लास इतना है कि काम शुरू करने और उसे काम को अंतिम छोर तक ले जाने में पूरी उर्जा बनाए रखते हैं। रोटरी क्लब अलवर द्वारा आयोजित कार्यक्रम ट्रैफिक संस्कार में बड़ी महती भूमि का निभाते हुए आमजन को पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक नियमों की पालना कार्रवाई, जो सच में मील का पत्थर साबित हुई। रोज सुबह उठते ही स्कूल के बच्चों के समक्ष जाना उन्हें ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए प्रेरित करना उनके अतुलनीय प्रयास आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं । युवाओं का जब जिक्र होता है तो शशांक झालानी का नाम सबकी जुबां पर इसलिए आता है कि वास्तव में आज युवा किस दौर से गुजर रहे हैं, किस अंधी गलियों में भटक रहे हैं और ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसका अंजाम बेहद खराब और विचारहीन है परंतु इस युवा का जोश और जज्बा सामाजिक कार्य में ही लगता है। मुझे एक एपिसोड याद है जब शशांक झालानी के सामने एक व्यक्ति खुले पड़े हुए नाले में गिर गया और गंभीर घायल जो गया इस वाक्या को देखकर इनका मन काफी आहत हुआ और इन्होंने तुरंत अपने पैसों के खर्चों से नाले का जाल बनवाया और नाले पर रखवाया । नगर परिषद के तत्कालीन कमिश्नर कमलेश मीणा खुद मौके पर आए और शशांक झालानी को उनके इस प्रयास के लिए अप्रिशिएट किया। आम जनता का दर्द समझने वाले इस युवा का जज्बा बिल्कुल ही अलग है शहर में ऐसा कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन नहीं जिसके साथ जुड़कर शशांक ने काम ना किया हो। शशांक झालानी को युवाओं के आदर्श के रूप में देखा जाता है जीव जंतुओं की रक्षा हो या फिर पौधारोपण इसमें पूरी तन्मयता के साथ बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति शशांक झालानी हमेशा लोगों के दिलों में वास करते हैं कम उम्र में सामाजिक सेवाओं का जज्बा शशांक झालानी को सच मे शशांक बनाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान उनके उज्वल भविष्य की कामना करता है।

जय हिंद

आज का इतिहास

23 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग ने 1456 में आधुनिक ढंग के दुनिया के पहले छापाखाने से बाइबिल की पहली प्रति छापी जो गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- मेक्सिको ने 1821 में आजादी की घोषणा की।
- ब्रिटेन ने 1839 में चीन के साथ युद्ध में हांगकांग पर कब्जा किया।
- स्पेन के खिलाफ मोरक्को में 1922 को विद्रोह हुआ।
- तुर्की ने 1922 को एफ्योन में ग्रीक ताकतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले आरंभ कीए।
- तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के के बीच गैर-आक्राम्कता संधि पर 1939 को हस्ताक्षर किये गये।
- युनान के राष्ट्रपति दिमित्रियो मैक्सिमोज ने 1947 में त्यागपत्र दे दिया।
- वल्लभभाई पटेल 1947 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने।
- चीन में 1976 को भूकंप से हजारों लोगों की मौत।
- ईरान की सेना ने 1979 में कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोला।
- इराक के सरकारी टेलीविजन पर 1990 में सद्दाम हुसैन के पश्चिम बंदियों के साथ दिखाए जाने के कारण काफी बवाल हुआ।
- पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने 1990 में तीन अक्टूबर को एकजुट होने की घोषणा की।
- आर्मेनिया ने 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा की।
- सं.रा.अमेरिका के मिसीसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 1997 में चार साल पहले मिला हल्दी का पेटेन्ट रद्द।
- पूनिया हत्याकान्ड जिसमें भारतीय राजनेता रेलू राम पूनिया और उनके परिवार के सात सदस्यों की 2001 में सामूहिक हत्या हुई थी।
- संयुक्त राज्य अमरीका ने 2002 में मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका, इटली ने पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बन्द करने की धमकी दी।
- ब्राजील में एक अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपण से पूर्व ही विस्फोट हो जाने से कम से कम 21 लोग मारे गये, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने 2003 में घोषित किया कि पाकिस्तान न्यूनतम सुरक्षात्मक हथियार क़ायम रखेगा।
- अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 2004 में 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने। चिली के निकोलस मासु ने अमेरिका के मार्डी फ़िश को हराकर ओलम्पिक पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीत लिया।
- आस्ट्रिया की नताशा काम्पुश अपहरणकर्ता वोल्फगांग प्रिकलोपिल के बंधन से 2006 में आठ साल बाद भागने में सफल रही।
- यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर-2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ शामिल की गईं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ़ को स्वदेश वापसी की अनुमति दी।

विशेष आलेख

सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री पर हंगामा गलत

डॉ. आर.के. सिन्हा

केन्द्र सरकार के विभिन्नविभागों में अहम पदों को संभालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में लैटरल एंट्री या कहें कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक विज्ञापन अखबारों में निकलवाया था। इसी को लेकर देशभर में गैर-जरूरी हंगामा खड़ा हो गया या निहित स्वार्थ से भरे लोगों द्वारा खड़ा कर दिया गया था। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति न करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। बात बस इतनी सी थी कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ पदों पर काम करने के लिए प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों की तलाश है। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के शामिल हैं, जिनमें कुल 45 पदों पर भर्ती होनी है। इस विज्ञापन के छपने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबसे ज्यादा हंगामा काट रहे थे। कह रहे थे कि केन्द्र सरकार सरकारी विभागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को भर्ती करना चाहती है। हालांकि हमेशा की तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए किसी तरह के प्रमाण देने की जरूरत तक नहीं महसूस नहीं की। वे वैसे भी राहुल गाँधी जी हवाई बातें-दावे करने में माहिर हैं। काश, राहुल गांधी को यह पता तो होगा ही कि देश के दस सालों तक प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह को देश का वित्त सचिव तक लेटरल एंट्री के माध्यम से ही बनाया गया था। वह तो तब तक तो वे दिल्ली विश्व विद्लाय में पढ़ा रहे थे। इसी तरह से मंटेक सिंह आहलूवालिया को भी कांग्रेस सरकार ने ही योजना आयोग का चेयरमेन बना दिया था। उनकी नियुक्ति भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से डॉ मनमोहन सिंह की खुद की हुई थी। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि मौजूदा सरकार कुछ विभागों के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी देकर गलत कर रही है। न जाने क्यों यूपीएससी के इस कदम ने नौकरशाही में लैटरल एंट्री पर बहस छेड़ दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीएससी की भर्ती की यह प्रक्रिया पीछे के दरवाजे से भर्ती है। इसे अंग्रेजी में बैक एंट्री भी कहा जा रहा है। अब कांग्रेस के नेताओं से यह तो पूछा ही पूछा जाना चाहिए कि सैम पित्रोदा और रघुरामन राजन कौन थे ? उन्हें किस आधार पर सरकार में लैटरल एंट्री के तहत ऊंचे पदों पर नौकरी दी गई थी ? अब जान लेते हैं कि लैटरल एंट्री होता क्या है? दरअसल नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर के बाहर के व्यक्तियों को सरकारी विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर भर्ती करना। इससे पहले लैटरल एंट्री के जरिए 2018 में पहली बार रिक्तियों की घोषणा की गई थी। लैटरल एंट्री करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर तीन से पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन और सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार की संभावना होती है। इन व्यक्तियों से ऐसी विशेषज्ञता लाने की उम्मीद की जाती है जो शासन और नीति कार्यान्वयन में जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सके। यूपीएससी के हालिया विज्ञापन से साफ था कि उसे तीन स्तरों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश थीः संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। इन पदों पर तैनात अफसर अक्सर विभागों के भीतर विशिष्ट विंगों के प्रशासनिक प्रमुख या उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं। लैटरल एंट्री के पीछे सरकार का तर्क यह रहा है कि नई प्रतिभा लाना और प्रशासन में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना। आप गौर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलते हैं, वे तब सरकार को सदैव कोसते ही रहते हैं। लोकतंत्र में सदा स्वस्थ्य वाद-विवाद और सार्थक संवाद जारी रहना चाहिए। हमेशा ही बेवजह विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। खड़गे जी कह रहे हैं कि लैटरल एंट्री से सरकारी नौकरियों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नुकसान होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी लैटरेल एंट्री पर आपत्ति है। अब इन ज्ञानी नेताओं को कोई बताए कि लैटरल एंट्री का विचार तो सर्वप्रथम कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान ही विकसित किया गया था। लैटरल एंट्री पर महाभारत करने वालों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। इसलिए इस मसले पर विवाद खड़ा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसा करने वाले संवैधानिक संस्थानों पर आघात कर रहे हैं।

दरअसल यह तो कहना पड़ेगा देश में सियासत के संसार का माहौल बहुत विषाक्त हो चुका है। सरकार के हरेक कदम का विपक्ष माखौल उड़ाता रहता है या उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता रहता है। अगर यही रणनीति विपक्ष अपनाता रहा तो सरकार अपना कोई काम कर ही नहीं सकेगी। यकीन मानिए कि विपक्ष से यह कोई नहीं कह रहा है कि वह सरकार को उसकी किसी जन विरोधी नीतियों पर न घेरे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे कामों और जटिल मुद्दों को सुलझाने तथा सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्वाभाविकता हमें संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा।

वृष
परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा। वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है।

मिथुन
अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा। आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है।

कर्क
शारीरिक-मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। छाती में दर्द या किसी विकार से परिवार में अशांति होगी। महिलाओं के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है। सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुख होगा। मित्रों के साथ घूमना-फिरना होगा।

सिंह
कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा आपके दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे। मित्रों, स्नेहीजनों के साथ यात्रा करने का योग है।

कन्या
आज आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को धंधे में लाभ और सफलता मिलेगी। आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है। प्रवास आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है। स्वास्थ्य बना रहेगा। समय से भोजन नहीं मिलेगा।

तुला
अपनी कला को बाहर लाने के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी। शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। मनोरंजन की प्रवृत्ति में दोस्तों तथा परिजनों के साथ भाग लेंगे।

वृश्चिक
सुंदर भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। काम में सफलता का योग है। दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता रहेगी। आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

धनु
कोर्ट-कचहरी के मामलों में संभलकर कार्य करना उचित रहेगा। ऑफिस में स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है। ऑफिस तथा काम-काज की जगह अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा।

मकर
आज संतान और जीवनसाथी के संबंध में चिंता होगी। वाद-विवाद या चर्चाओं में गहरे न उतरना हित में रहेगा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मित्रों के लिए खर्च की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियों से तकलीफ होगी।

कुंभ
पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा। आज आपको बेचैनी, थकान का अनुभव होगा। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। इससे काम करने का उत्साह नहीं रहेगा।

मीन
आपका आज का दिन शुभ फलदायी साबित होगा। निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। ननिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे। बीमारी में राहत महसूस होगी। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा। आमोद-प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

कल्पमेधा

वर्तमान में हम जो कुछ हैं, अपने विचारों के ही कारण हैं और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे, वह भी इन्हीं के कारण बनेंगे।

- महात्मा बुद्ध

आंदोलन के समांतर

कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने सभी संवेदनशील लोगों के भीतर दुख और आक्रोश भर दिया है। यह बेवजह नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए एक कारगर व्यवस्था बनाने के लिए आवाज उठाई है। इसी के तहत कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी, जिससे वहां कामकाज बाधित हुआ। चिकित्सकों के दुख और गुस्से से किसी को भी असहमति नहीं हो सकती और इस मुद्दे पर उनकी मांग वाजिब है। विडंबना यह है कि हड़ताल से उन मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो मजबूरी में इलाज कराने वहां पहुंचते हैं। कोलकाता की घटना पर दुख के समांतर पिछले कुछ दिनों से यह सवाल भी चिंता की वजह बन रहा था कि चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है, उसका समाधान क्या हो।

शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के दौरान चिकित्सकों की सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की और कहा कि चिकित्सकों के काम से दूर रहने से समाज के उन वर्गों पर असर पड़ता है, जिन्हें चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। हड़ताल की वजह से खासतौर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को हो रही दिक्कतों का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। ऐसे तमाम लोग होते हैं, जो किसी बीमारी के इलाज के क्रम में अस्पतालों में दो-दो वर्ष पहले समय लेते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें किसी चिकित्सक से इलाज या आपरेशन कराने का मौका मिल पाता है। ऐसे में अगर सिर्फ हड़ताल की वजह से उन्हें यह कहा जाए कि आपका इलाज नहीं हो सकता, तो इसे कैसे देखा जाएगा। दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की वजह से अगर कोई मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों या क्लीनिकों में इलाज के लिए पहुंचता है तो वहां उसे आर्थिक खर्च की किस कसौटी को पूरा करना पड़ता है, यह छिपा नहीं है।

निश्चित रूप से एक बेहद तकलीफदेह घटना पर चिकित्सकों का आंदोलित होना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इस आंदोलन को समाज के सभी संवेदनशील लोगों का समर्थन मिला है। मगर इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों के कामकाज में जिस स्तर की मुश्किल पेश आई है, वह भी चिंताजनक है। यों सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली में एम्स और राममनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म करने और ड्यूटी पर जाने की घोषणा कर दी, मगर कुछ राज्यों में अभी भी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हैं। गौरतलब है कि चिकित्सकों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं सीबीआइ ने अपनी स्थिति रपट में जिस तरह की लापरवाहियों और सबूतों से छेड़छाड़ की ओर संकेत किया है, वह बंगाल पुलिस और राज्य सरकार के रुख को कठघरे में खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में इस मसले पर चिकित्सकों सहित सभी लोगों की चिंता समझी जा सकती है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी आंदोलन से व्यापक स्तर पर वैसे लोगों के जीवन के सामने संकट न पैदा हो, जो पहले ही बीमारी से घिरे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं!

दागी नुमाइंदे

महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध का कोई मामला जब तूल पकड़ते हैं, तब उसे लेकर सवाल उठाने वालों, विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने और उसमें हिस्सा लेने वालों में बहुत सारे नेता और खासतौर पर जनप्रतिनिधि भी मुखर रूप से शामिल होते हैं। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो जनप्रतिनिधि इस सवाल पर आक्रोशित जनता के साथ खड़े दिखते हैं, वे खुद अपने सहयोगियों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आरोपों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते। यह छिपा तथ्य नहीं है कि हर चुनाव में ऐसे लोग भी बतौर उम्मीदवार किसी सीट पर अपना दावा पेश करते हैं और उनमें से कई जीत कर जनप्रतिनिधि भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप है, तो उससे महिलाओं के हक में ईमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी होते हैं, वे कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कितने गंभीर हो सकते हैं?

यह बेवजह नहीं है कि चुनावी नैतिकता और शुचिता की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जगजाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार फिर एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें पिछले पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक सौ इक्यावन सांसदों-विधायकों को चिह्नित किया गया। इनमें सोलह पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बदला या साजिश बता कर खारिज नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि ऐसे मामलों में जांच, सुनवाई और फैसला लंबे समय तक टलता रहता है। चुनाव आयोग भी ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने और जीत कर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने को लेकर कोई स्पष्ट रुख तय नहीं कर पाता! ऐसे दागी नुमाइंदों को लेकर नरम रवैया क्या एक बड़ी वजह नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ कोई ठोस और नतीजा देने वाली व्यवस्था खड़ी नहीं हो पा रही?

साइबर ठगी का नया पैंतरा

ठग फोन करके बताते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक खाता आदि का उपयोग किसी गैर-कानूनी काम के लिए हुआ है। यहां से लोगों को डराने-धमकाने का खेल शुरू होता और फिर ठगी का लक्ष्य पूरा किया जाता है।

अमित बैजनाथ गर्ग

साइबर ठगों ने लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इन दिनों एक और नया तरीका अपनाया है, जिसका नाम है 'डिजिटल अरेस्ट'। इसमें ठगी करने वाले लोगों को फंसाने के लिए 'ब्लैकमेलिंग' या भयादोहन का खेल खेलते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। इसमें ठग पुलिस, सीबीआइ या आबकारी अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते और डराकर उन्हें घर पर ही बंधक बना लेते हैं। सबसे पहले, ठग फोन करके बताते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक खाता आदि का उपयोग किसी गैरकानूनी काम के लिए हुआ है। यहां से लोगों को डराने-धमकाने का खेल शुरू होता और फिर ठगी का लक्ष्य पूरा किया जाता है। ठग 'वीडियो काल' में अपनी तस्वीर के पीछे के दृश्य को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं, जिसे देखकर पीड़ित डर कर उनकी बातों में आ जाता है। ठग जमानत की बात कहकर लोगों से ठगी शुरू करते हैं। वे व्यक्ति को 'वीडियो काल' से न तो हटने देते हैं और न ही किसी को फोन करने देते हैं।

एक घटना की पीड़ित नोएडा में रहने वाली एक महिला का कहना था कि एक अंतरराष्ट्रीय कूरियर कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें फोन करके बताया कि उनके नाम से भेजे गए पार्सल में नशीला पदार्थ मिला है। महिला ने जब इस तरह के किसी भी पार्सल की जानकारी न होने की बात कही, तो फोन करने वाले ने बताया कि वह इसकी शिकायत मुंबई साइबर अपराध शाखा में दर्ज करवा रहा है। उसके बाद महिला के पास एक 'वीडियो काल' आया, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति के पीछे का दृश्य किसी पुलिस स्टेशन का था। पुलिस अफसर बनकर बात कर रहे व्यक्ति ने वीडियो काल पर महिला को रात भर सोने नहीं दिया और उसे डरा-धमका कर करीब 5.20 लाख रुपए अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए। महिला को चौबीस घंटे से अधिक समय तक 'डिजिटल अरेस्ट' रखा गया।

इसी तरह का एक और मामला बंगलुरु की एक उनतीस वर्षीय महिला वकील द्वारा हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति ने फोन करके उसे दो दिनों तक डिजिटल रूप से 'गिरफ्तार' कर रखा था। उसने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय कूरियर कंपनी का कार्यकारी अधिकारी बताया था। आनलाइन जालसाजों ने न केवल उससे 14.57 लाख रुपए ठग लिए, बल्कि मादक पदार्थ परीक्षण करने के बहाने उसे कैमरे के सामने नग्न होकर खड़े होने को भी कहा। बाद में उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने उन्हें दस लाख रुपए नहीं दिए तो वे उसके वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। वहीं, फरीदाबाद की तेईस वर्षीय महिला से साइबर ठगों ने फर्जी सीमा शुल्क अधिकारी बनकर ग्यारह लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने घटना के समय महिला को गिरफ्तारी का डर दिखाकर डराया और उसे लगभग आठ घंटे तक 'डिजिटल अरेस्ट' करके रखा।

इसी तरह जयपुर में रहने वाली एक महिला बैंक मैनेजर के पास साइबर ठग का फोन आया। उसने खुद को दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके आधार कार्ड पर ली गई एक सिम का उपयोग अवैध कार्यों के लिए किया जा रहा है। मैनेजर यह सुनकर हैरान रह गई। इसी दौरान एक दूसरे व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने महिला को वीडियो काल पर आने

> **कोई भी जांच एजंसी या पुलिस किसी को फोन करके धमकी नहीं देती है। हर जांच एजंसी के अधिकारी और पुलिसकर्मी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास डराने-धमकाने के लिए इस तरह के फोन आते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए या फिर 'राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता सेवा' (1930) पर फोन करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर 'साइबर पोस्ट' के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई संदेश या ई-मेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को देना चाहिए।**

को कहा। इस तरह करीब पांच घंटे तक उसे 'डिजिटल अरेस्ट' करके रखा गया। इस दौरान उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपए भेजने का कहा। डर के मारे मैनेजर ने अपनी एफडी तोड़कर 17 लाख रुपए ठग द्वारा बताए खाते में डाल दिए।

ऐसी अनेक घटनाएं देश के अलग-अलग शहरों में घटित हो चुकी हैं। आए दिन ऐसी खबरें अखबारों में छपती और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर प्रसारित होती रहती हैं। इसके बावजूद लोग साइबर ठगों के जाल में फंस जा रहे हैं। ये ठग इतने शातिर होते हैं कि लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल कर जैसा चाहते हैं, वैसा उनसे कराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि, इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार भी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सरकार ने तेजी से बढ़ रही 'डिजिटल अरेस्ट' और भयादोहन की घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हजार 'स्काइप' खातों को प्रतिबंधित किया है। बावजूद इसके, इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की एक रपट के मुताबिक वित्तवर्ष 2022-2023 में तीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी की शिकायतें देश में दर्ज की गई हैं। पिछले एक दशक में एक जून, 2014 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक भारतीय बैंकों में 65,017 ठगी के मामले सामने आए हैं, जिनमें 4.69 लाख करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। अभी तक साइबर अपराधी यूपीआई धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ओटीपी धोखाधड़ी, नौकरी के नाम पर ठगी, सामान आपूर्ति ठगी आदि के जरिए लोगों को चूना लगाते आ रहे हैं। अब 'डिजिटल हाउस अरेस्ट' भी साइबर अपराधियों का हथियार बन रहा है।

दरअसल, ये सब साइबर ठगों के लोगों को डराने-धमकाने के फर्जी तरीके हैं। कोई भी जांच एजंसी या पुलिस किसी को फोन करके धमकी नहीं देती है। हर जांच एजंसी के अधिकारी और पुलिसकर्मी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास डराने-धमकाने के लिए इस तरह के फोन आते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए या फिर 'राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता सेवा' (1930) पर फोन करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर 'साइबर पोस्ट' के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई संदेश या ई-मेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को देना चाहिए। अगर किसी कारण फोन उठा लिया गया और वीडियो काल पर कोई धमकी देने लगा, तो 'स्क्रीन रिकार्डिंग' के जरिए वीडियो काल को रिकार्ड करके शिकायत करानी चाहिए। किसी भी तरह डरना और पैसे नहीं भेजना चाहिए।

अगर कोई झांसे में लेने का प्रयास करे तो उसके नंबर को तत्काल 'ब्लाक' कर देना चाहिए। अगर कोई संशय हो तो पुलिस विभाग की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां और उसके अफसरों के नंबर रहते हैं, उनसे भी जानकारी ली जा सकती है। प्राथमिकी की धमकी देने वाले को नजरअंदाज करना चाहिए। इसके अलावा, किसी के साथ अपनी निजी जानकारियां जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अन्य बैंकिंग ब्योरे साझा न करनी चाहिए। कोई भी बैंक या सरकारी-गैर सरकारी संस्थान पिन, ओटीपी आदि की जानकारी नहीं पूछता है। ऐसे में, किसी से अपनी निजी जानकारियां गलती से भी साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट आदि के पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहना चाहिए, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके।

स्वीकार का साहस

नूरी खान

दुनिया मेरे आगे

समाज ने कठिन परिस्थितियों में कष्ट को कम करने की क्षमता तो विकसित कर ली, लेकिन ऐसा लगता है कि शेष रह गई पीड़ा से निपटने की क्षमता ज्यादातर लोगों ने खो दी है। वैज्ञानिकों के अध्ययन इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य समाज के अधिकांश लोग इस विश्वास में जीते हैं कि संसार रहने के लिए अच्छी जगह है, अधिकांश जीवन अच्छा है और यह कि वे स्वयं अच्छे लोग हैं और अच्छी चीजें पाने के अधिकारी हैं। ये विश्वास अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मगर कष्टों का होना चूंकि निश्चित है, इसलिए यह बात इस विश्वास को कमजोर कर देती है और खुशी पाना और अच्छे ढंग से जीना कठिन बना देता है। इस संदर्भ में जब इस दुनिया के न्याय और दया से व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है, तो छोटी-छोटी तकलीफ भी बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती है। इस कारण पीड़ा बहुत ज्यादा महसूस होती है।

कष्ट से सिर्फ अस्थायी तौर पर बचा जा सकता है, मगर किसी ऐसी बीमारी की तरह, जिसका उपचार न करवाया जाए तो बीमारी बढ़ती जाती है। दवाओं से कुछ देर का आराम तो मिल सकता है, लेकिन लगातार प्रयोग से शरीर को होने वाले नुकसान और जीवन में होने वाले सामाजिक नुकसान के कारण असंतोष या भावनात्मक दर्द से अधिक पीड़ा हो सकती है। पीड़ा को अस्वीकार करना या मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली कुछ समय के लिए हमें उस दर्द को सहन करने से बचा सकती है, लेकिन इससे हमारा कष्ट दूर नहीं होता।

कभी-कभी अपनी समस्याओं से बचने की हमारी अचेतन रणनीतियां बहुत गहराई लिए होती हैं। ये इतनी गहरी होती हैं कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और कई बार उन्हें बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर हर दूसरा व्यक्ति समस्याओं से बचने के लिए दूसरों को दोष देता है। ऐसे दोष जो वास्तव में खुद के ही होते हैं। यह समस्याओं के समाधान का प्रभावी तरीका नहीं है और यह स्वभाव लोगों को हमेशा दुखी रखता है।

> **कभी-कभी अपनी समस्याओं से बचने की हमारी अचेतन रणनीतियां बहुत गहराई लिए होती हैं। ये इतनी गहरी होती हैं कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और कई बार उन्हें बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर हर दूसरा व्यक्ति समस्याओं से बचने के लिए दूसरों को दोष देता है।**

ज्यादातर मामलों में दुविधा ही दुख का मुख्य कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए, किसी दंपती को गर्भस्थ शिशु में कोई गंभीर शारीरिक, मानसिक विकलांगता का पता चल जाए तो ज्यादा संभावना है कि वह दंपती दुविधा में फंस जाएगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। संभव है कि जिंदगी भर के कष्ट से बचाने के लिए शिशु के जन्म देने के फैसले पर विचार करना पड़ जाए, लेकिन महिला को उस क्षति और दुख की वजह से गंभीर पीड़ा महसूस होगी और हो सकता है अपने फैसले पर अमल करते हुए उसे अफसोस और ग्लानि भी हो। इससे अलग, यह भी हो सकता है कि प्रकृति अपना काम करे और बच्चे को जन्म लेने दिया जाए। मगर इससे उसके और बच्चे, दोनों के लिए जीवन भर की परेशानी और कष्ट की स्थिति बन सकती है।

हममें से किसी को भी इस तरह की दुविधाजनक परिस्थितियों का सामना कर पड़ सकता है और हम खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ऐसा करने से उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। बस इससे हमें मानसिक रूप से हालात से निपटने में मदद मिल सकती है, हमारा डर कुछ कम हो सकता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

पीड़ा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में इस बात की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा मूल नजरिया यह है कि कष्ट नकारात्मक है, इससे किसी भी रूप में बचना चाहिए और यह असफलता का प्रतीक है, तो इससे कठिन परिस्थितियों में चिंता और असहिष्णुता का विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अंश जुड़ जाएगा और यह हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर हम कष्ट को जीवन का स्वाभाविक अंग मानते हैं तो निश्चित रूप से यह नजरिया हमें जीवन की कठिनाइयों के प्रति अधिक सहनशील बना देगा। यों भी दुख किसी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जीवन में अलग-अलग वजहों से मिलने वाले दुख हमें जीवन के संघर्षों से परिचित कराते हैं और बेहतर रास्तों की तलाश के प्रति ज्यादा जुझारू बनाते हैं।

जीवन की दैनिक सच्चाइयों के संपर्क में रहने वाले लोग आसानी से इस बात को नकार नहीं सकते कि जीवन में कष्ट आते हैं और यही जीवन का स्वाभाविक रूप है। किसी न किसी को दोष देने और पीड़ित अनुभव करते रहने का खतरा हमारे कष्ट को बढ़ाता है और इससे कुंठा, क्रोध और रोष बढ़ता है। निश्चय ही, पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा हर एक मनुष्य का लक्ष्य होता है। यह खुश रहने की हमारी इच्छा का परिणाम है। यह पूरी तरह से उचित है कि हम अपने दुख के कारणों को खोजें और अपनी समस्याओं को कम करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वह करें। जब तक हम कष्ट को अस्वाभाविक असामान्य अवस्था मानते रहेंगे और उससे डरते रहेंगे, बचेंगे और उसे अस्वीकार करेंगे, तब तक हम कष्ट के कारणों को दूर कर कभी सुख से नहीं जी पाएंगे। समस्याओं से संघर्ष कर जीवन को एक नया आयाम देना चाहिए। जिन लोगों को प्रसन्न रहकर जीवन जीने की कला आती है, वे आनंद का मार्ग अपनाते हैं। एक ऐसा आनंद जो उन्हें हर परिस्थितियों से, हर समस्याओं से परे रखकर जीवन को सुखी बनाने में मददगार बनता है।

सख्ती की तकाजा

'बेलगाम अपराध' (संपादकीय, 20 अगस्त) के माध्यम से देश के समाज में फैलती एक अत्यंत गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सार्वजनिक और अपेक्षाकृत रूप से सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर इस प्रकार के जघन्य अपराध निश्चित रूप से पूरे देश और समूचे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। अपराध केवल अपराध होता है और प्रत्येक अपराध से निपटने के लिए देश का कानून और न्याय ही कसौटी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता और दूसरी स्वनिर्धारित कसौटियों के हिसाब से उन अपराधों की गंभीरता मापी या तय की जाने लगती है। देर सबेर हमें यह वास्तविकता स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। उनके लिए किसी स्थान का कोई महत्त्व नहीं होता। जहां भी उन्हें अवसर मिलता है, वे सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक अपराध से पूरी सख्ती और निष्पक्षता से निपटना जरूरी है। सभी प्रकार के अपराधियों के लिए कानून और न्याय प्रणाली का उपयोग समुचित बराबरी से किया जाना चाहिए, अन्यथा देश में अपराध और अपराधी इसी प्रकार बेलगाम होते रहेंगे।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

युद्ध रुके

दोनों पक्षों के बीच टकराव का यह नतीजा निकला है कि न केवल इजराइल, बल्कि फिलिस्तीनी इलाके के गाजा पट्टी में आम लोगों की जिंदगी दरहम-बरहम होकर रह गई है। इस बात के भी काफी प्रयास किए गए हैं कि इन दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके, पर दोनों इसे अपने आत्मसम्मान लड़ाई मानकर अब तक लगातार लड़ रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन समर्थक हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दिएफ हनियेह की हत्या कर दी गई। उससे भी तनाव को कम करने के प्रयासों में बड़ी भारी कमी आई। अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि हनियेह की मौत के बाद उपजे हालात में फिलिस्ती और हमास समर्थक इरान भी इजराइल पर हमला कर सकता है। मगर विश्व भर से आज भी यही मांग उठ रही है कि किसी न किसी तरह वहां कोई शांति समझौता हो और इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जाए।

- मनमोहन राजावत राज, शाजापुर, मप्र

उम्मीद के समांतर

जम्मू-कश्मीर में पांच साल से कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं हुई है। चुनाव आयोग का यह एक अच्छा कदम है कि वहां अब चुनाव होंगे। 'जम्हूरियत का जश्न' (संपादकीय, 17 अगस्त) में जरूरी विश्लेषण किया गया है। यह चुनाव इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि वहां लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वापसी का संकेत मिला है। यह चुनाव राज्य के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका देंगे, जो क्षेत्र में लोकतंत्र के बारे में कुछ चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियां बरकरार हैं। मसलन, चुनाव के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। साथ ही यह स्पष्ट नहीं है कि नई विधानसभा के पास वास्तव में कितनी शक्ति होगी। फिर ही यह चुनाव जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये कैसे आयोजित किए जाते हैं और नई विधानसभा के गठन के बाद क्या होता है।

- चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

जीवन अनमोल

अक्सर देखने में आता है कि कहीं परीक्षा में नंबर कम आने की वजह से या पढ़ाई का ज्यादा दबाव होने की वजह से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर फसल खराब होने की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं कोई व्यापारी कारोबार में नुकसान होने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। जीवन का हर दिन एक हीरे की तरह होता है, लेकिन हम निराश होकर इस अनमोल संपदा को पत्थर समझ कर फेंकते रहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने नाकामी का अंधकार छाया होता है। जीवन में क्या छिपा था, कौन-सा राज, आनंद, कौन-सी मुक्ति... उन सबका कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती की कोई आदमी निराश हो जाए। इसलिए चाहे वे छात्र हों, किसान हों या व्यापारी या फिर कोई भी ईसान, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

- चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 23 अगस्त 2024

लड़कियां फिर आगे

शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का विश्लेषण कई गंभीर मसलों की ओर ध्यान खींचता है, लेकिन इसका सबसे अहम पहलू है स्कूलों में लड़कियों की ओर से लिखी जा रही कामयाबी की सुनहरी कथाएं। यह लगातार दूसरा साल है जब शिक्षा मंत्रालय ने देश के 59 स्कूल बोर्डों के रिजल्ट्स का विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है।

AI Image

शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट

पूर्वाग्रह का वार | समाज में और परिवार के अंदर लड़कियों को जिस पूर्वाग्रह भरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण रिपोर्ट में इस तथ्य के रूप में उभरता है कि देश भर में प्राइवेट स्कूलों में लड़कों और सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। साफ है कि मां-बाप चाहते हैं बेटे ज्यादा अच्छी और महंगी शिक्षा पाएं। बेटियों को जैसे-तैसे पढ़ा देना काफी माना जाता है।

प्रदर्शन का जज्बा | दिलचस्प है कि यह पूर्वाग्रह लड़कियों के जज्बे को कमजोर करने के बजाय उसे और मजबूती दे रहा है। रिजल्ट्स का विश्लेषण बताता है कि बोर्डों, स्कूलों और विषयों के भेदों से ऊपर उठते हुए लड़कियां, लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में, चाहे स्टेट बोर्ड हो या नैशनल और चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज लड़कों से काफी ज्यादा है।

विषयों का चयन | जहां तक स्ट्रीम सिलेक्शन की बात है तो साइंस आज भी सबसे लोकप्रिय है। करीब 43% स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम में अपीयर हुए और 34% आर्ट्स स्ट्रीम में थे। खास बात यह कि साइंस में लड़कों की बहुलता थी जबकि आर्ट्स में लड़कियों की। लेकिन पासिंग पर्सेंटेज देखें तो लड़कियां न सिर्फ आर्ट्स में बल्कि साइंस में भी लड़कों से आगे नजर आती हैं।

अन्य क्षेत्रों का ट्रेंड | स्कूल स्तर पर यह जो ट्रेंड इस रिपोर्ट में दिख रहा है, वह अन्य तमाम क्षेत्रों में उभरते नए ट्रेंड से मेल खा रहा है। चाहे कॉलेजों की परीक्षाओं की बात हो या NEET और JEE जैसी प्रफेशनल कोर्स वाली परीक्षाओं की, हर जगह ट्रेंड यही दिखता है कि महिलाएं न सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा रही हैं बल्कि प्रदर्शन में भी लगातार सुधार दर्ज करा रही हैं।

वर्कप्लेस पर मिले हक | निश्चित रूप से यह एक हेल्दी ट्रेंड है। लड़कियों के आगे बढ़ने का मतलब उनके आत्मविश्वास का बढ़ना है, उनका ज्यादा असर्टिव होना है। ऐसी लड़कियां परिवार के अंदर या वर्कप्लेस पर अपनी सही जगह न सिर्फ चाहती हैं बल्कि उसे हासिल करती हैं। उम्मीद है कि अच्छी पढ़ाई के बाद जब ये लड़कियां पेशेवर जिंदगी शुरू करें तो वहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।

रोज़-ब-रोज़

मणिकर्णिका की चाय

शैलेंद्र पांडेय

काशी के मणिकर्णिका घाट से कोई शुद्ध लौटा है या अशुद्ध, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह गया किसलिए था। अगर जाना किसी शवयात्रा के साथ हुआ, तब तो गंगा में डुबकी भले न लगाएं, लेकिन पानी ऊपर छिड़कना पड़ेगा। घर में घुसने के पहले नहाना होगा और अगर ज्यादा कड़ाई हुई तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा। श्मशान से लौटने के बाद कोई खाना नहीं खाता। लेकिन, अगर जाना हुआ है घाट की सीढ़ियों-चौकियों पर बैठकर बहते पानी और चिताओं से उठते धुएं को देखकर चाय पीने के लिए, तो कोई फिकर नहीं। केवल प्रयोजन बदल जाने से बाकी के कर्मकांड बदल जाते हैं। आपको लग सकता है कि चाय पीने के लिए श्मशान घाट कौन जाता है? इस सवाल में कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि बात बनारस की हो रही है, इसलिए यह सवाल बनता ही नहीं। नींबू की काली, मसाले वाली चाय पी रहे लोगों के आसपास जीवन की अंतिम रस्म चल रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इससे ऊपर उठ चुके हैं। मानो जब तक चाय है, तब तक उन्हें जीवन-मौत की चिंता करने की जरूरत नहीं।

यही तलब है चाय की, यही ताप है। अग्नि सबको शुद्ध कर देती है और उस पर पकी चाय भी कुछ कम नहीं। बनारस में रास्तों पर जगह-जगह शव विश्राम स्थल हैं। घाट की ओर जाती शवयात्रा इन जगहों पर जरूर रुकती है। अर्थी को उस जगह कुछ देर के लिए रखा जाता है। चाहे किसी भी दिशा से दाखिल हों काशी में, घाट तक ऐसे पांच पड़ाव आते हैं कुल, जहां शवयात्रा विश्राम पाती है। ऐसा ही एक पड़ाव है पांडेयपुर में, चौराहे पर राम-जानकी मंदिर के ठीक पीछे। कुछ बरस पहले एक चबूतरा हुआ करता था, मंदिर की पिछली दीवार से बिल्कुल सटा हुआ। इसी चबूतरे के बगल में एक दुकान थी चाय की। सूरज उगने के पहले से ही दुकान की भट्ठी में कोयला सुलग उठता और आधी रात तक जलता रहता। इस दौरान शायद ही कोई वक्त होता हो, जब आंच खाली रहे, वरना हमेशा उस पर चाय उबलती रहती। लोग चबूतरे पर बिछे बोरे पर बैठकर अखबार के साथ चाय सुड़कते। वही अर्थी वाला चबूतरा। और इस दौरान जब कोई शवयात्रा आती, तो लोग उठ जाते। दुकानदार इत्मिनान से बोरा हटाता, अखबार समेटता। अर्थी के रुकने के लिए जगह बन जाती। कभी-कभार अर्थी के कुछ फूल उसी चबूतरे पर रह जाते। इत्र और अगरबत्ती की महक तो हमेशा ही पीछे छूट जाती, इससे चाय के कारोबार पर कभी फर्क नहीं पड़ा कोई, और न कभी कोई चाय प्रेमी उस चबूतरे पर बैठकर अशुद्ध हुआ। अब वहां लोहे का स्टैंड है, चबूतरा नहीं है, लेकिन चाय है और हमेशा रहेगी।

एकदा

हुनर का महत्व

बात 1898 की है। बनारस के क्वीन्स कॉलेज में मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट्स अगली कक्षा (11वीं) में दाखिला लेने की कतार में खड़े थे। एक छात्र ऐसा भी था जिससे कहा गया कि नंबर कम है, दूसरी जगह प्रयास करिए। उसी साल एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोला था। वहां पर भी योग्यता की जांच में उस स्टूडेंट को सफलता नहीं मिली। एडमिशन न मिलने पर उसने एक वकील के यहां पांच रुपये महीने का ट्यूशन शुरू किया ताकि बनारस में रहकर गणित की तैयारी कर अगले साल योग्यता की जांच में सफल हो सके। लेकिन पांच रुपये में महीने का खर्च नहीं चलता था। पिता के निधन के कारण ढाई रुपये घर देना पड़ता था। महीने के आखिरी दिन उधारी पर कटते थे। एक बार उसे उधार नहीं मिला। दो पैसे जेब में थे। एक पैसे का चना खाकर पहला दिन और दूसरे पैसे से दूसरा दिन कटा। तीसरे दिन मजबूरी में उसने गणित की चक्रवर्ती की कुंजी बेचने का निश्चय किया।

Subrata Dhar

कुंजी का मूल्य दो रुपये था। दुकानदार आधे दाम पर तैयार हुआ। मजबूरी में एक रुपये लेकर जैसे ही वह नौजवान चला, दुकान पर खड़े एक आदमी ने कहा, 'कहां पढ़ते हो?' जवाब पाकर उस आदमी ने फिर कहा, 'मैं चुनार के एक विद्यालय में हेडमास्टर हूं। मुझे 18 रुपये महीने के वेतन पर मैट्रिक पास लड़के की जरूरत है।' युवक ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस काम से कमाई और पढ़ाई का रास्ता मिल गया। इस नौजवान का नाम धनपत राय था, जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। उनके लिखे साहित्य को एडमिशन न देने वाले कॉलेजों में भी पढ़ाया गया। हुनर जरूरी है, कम नंबर आने पर छात्रों को झेंपना नहीं चाहिए।

संकलन : हरिप्रसाद राय

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों स्तरों की सामरिक साझेदारी इन देशों के रिश्तों को मज़बूती दे रही है

भारत-जापान की दोस्ती और गहरी होगी

रंजीत कुमार

जापान उन चुनिंदा बड़ी ताकतों में है, जिनके साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। इसके तहत तीसरे दौर की वार्ता में जापान की विदेश मंत्री कमीकावा योको और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने 20 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर भारत से सामरिक साझेदारी को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक व तकनीकी ताकत का इस तरह दुनिया की पांचवीं बड़ी आर्थिक ताकत के साथ खड़े होना काफी अहमियत रखता है।

दुनिया को संदेश | दोनों देशों का साथ दिखना इसलिए भी अहम है कि दोनों चीन की विस्तारवादी नीतियों से समान रूप से परेशान हैं और उससे मुकाबला करने के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी, आज जितनी भारत को जापान की जरूरत है, उतनी ही जापान को भारत की।

सबसे गहरे सामरिक साझेदार | भारत इस तरह की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी करता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और ब्राजील के साथ भी अधिकारी स्तर की 2+2 वार्ता शुरू की गई है। 2+2 वार्ता इस बात का संकेत मानी जाती है कि ये देश भारत के सबसे गहरे सामरिक साझेदार हैं।

डिफेंस सेक्टर में सहयोग | चूंकि राजनयिक रिश्तों की मजबूती के लिए दो देशों के बीच रक्षा सहयोग जरूरी माना जाता है और इसके मद्देनजर जापान अपनी पारंपरिक रक्षा नीति में बदलाव लाने लगा है, इसलिए विदेश व रक्षा मंत्रियों की इन संयुक्त बैठकों की अहमियत बढ़ जाती है। जापान की मदद से भारत अगली पीढ़ी के रक्षा उपकरणों का विकास और निर्माण कर सकता है। इसके अलावा मौजूदा विश्व सामरिक माहौल में अपने हितों की रक्षा के लिए जापान अपनी सेना को नए हथियारों से लैस करना चाहता है। वह इन हथियारों का भारत में साझा उत्पादन कर सकता है। यही नहीं, वह भारत से भी रक्षा साजोसामान का आयात कर सकता है।

क्वाड की साझा सदस्यता | भारत के साथ 2+2 वार्ता में भाग लेने वाले देशों में तीन देश - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान - QUAD के भी सदस्य हैं। इन देशों के साथ भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर (QUAD) पर वार्ताएं कर चीन को अप्रत्यक्ष संदेश देता है कि उसके विस्तारवादी मंसूबों को पूरा नहीं होने देने के लिए क्षेत्र की बड़ी ताकतें साथ चल रही हैं।

चीन की नाइन डैश रेखा | चूंकि ये देश हिंद प्रशांत इलाके में चीन की विस्तारवादी नीतियों और दादागीरी से चिंतित हैं इसलिए जब भी भारत के रक्षा व विदेश मंत्रियों की इन देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठकें होती हैं तो दोनों पक्षों के बीच चर्चा का एक अहम विषय यह होता है कि हिंद प्रशांत के महासागरीय इलाके को समुद्री और हवाई यातायात के लिए खुला रखना कितना जरूरी है। चीन ने एक काल्पनिक नाइन डैश रेखा खींची है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्र तटीय इलाके से होकर ही गुजरती है। इस रेखा के अंदर पड़ने वाले दक्षिण चीन सागर के इलाकों को चीन अपना बताता है।

ये दोस्ती
- भारत-जापान QUAD के मेंबर
- दोनों में 2+2 बातचीत होती है
- चीन को रोकने का है इरादा

साउथ चाइना सी पर कंट्रोल | चीन को यदि खुली छूट मिल गई तो दक्षिण चीन सागर के इलाके से होकर गुजरने वाले दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों और विमानों को उससे अनुमति लेनी होगी। वह इनके गुजरने पर टैक्स भी लगा सकता है। भारत का आधा से अधिक समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर के जरिए ही होता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि इस व्यापार को निर्बाध तरीके से जारी रखने के लिए वह हिंद प्रशांत की सभी ताकतों के साथ मिल कर रहे।

ग्लोबल साउथ का नेता | भारत के साथ 2+2 वार्ता का औचित्य बताते हुए जापानी राजनयिक कहते हैं कि वर्तमान सुरक्षा माहौल में भारत के साथ सहयोग गहरा करना काफी अहम है। जापान भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का नेता मानता है। जापान और भारत इलाकाई यथास्थिति को ताकत के बल पर बदलने का तीव्र विरोध करते हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर करते हुए नियमों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने को परस्पर प्रतिबद्ध हैं।

आर्थिक मोर्चे पर मजबूती | चीन अपने प्रतिद्वंद्वी देशों को सामरिक के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी परेशान कर सकता है। इससे बचने के लिए भी भारत का अपने सामरिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी है। इनमें जापान सबसे अहम कड़ी है।

क्रिटिकल मिनरल्स | भारत और जापान को मिलकर चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता तोड़नी होगी। जापान भारत को चीनी सप्लाई चेन के विकल्प के तौर पर देख रहा है। इसीलिए आधुनिक औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स (दुर्लभ खनिजों) के साझा उत्पादन के लिए भी भारत को तकनीकी मदद देने को तत्पर है। भारत को इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

(लेखक सामरिक मामलों के जानकार हैं)

गांवों को संवार रहा उन्नत भारत अभियान

वीरेंद्र कुमार विजय

शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम 'उन्नत भारत अभियान' राष्ट्रीय सेवा-शिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण विकास प्रक्रिया को बेहतर करना। यह अभियान साल 2014 से चल रहा है। तब से यह लगातार शिक्षण संस्थानों और गांवों के बीच के अंतर को कम करने, ग्रामीण परिवेश के लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह अभियान ग्रामीण परिवेश के छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान कर रहा है। साथ ही, प्रैक्टिकल एजुकेशन और टेक्नॉलजी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है।

सेवा और शिक्षा | आने वाली पीढ़ी के समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में उन्नत भारत अभियान सहयोग कर रहा है। उच्च शिक्षा में पिछले कुछ बरसों में सेवा-शिक्षा छात्रों को आकर्षित कर रही है। इसमें स्नातक और उससे ऊपर के छात्रों को सामुदायिक सेवा और सामाजिक कर्तव्यों से परिचित कराना प्रमुख रूप से शामिल है।

ग्रामीण भारत का विकास | उन्नत भारत अभियान स्थायी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ सामुदायिक भागीदारी विकसित करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक मुद्दों का क्षेत्रीय अध्ययन और बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढना, साथ ही नवीन अकादमिक ज्ञान से समाज को परिचित कराना है। यह संबंधित समुदाय के लोगों को अपनी समस्याओं और नवीन प्रयोगों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

ग्रामीण भारत पर ध्यान | यह अभियान ग्रामीण भारत के विकास पर भी ध्यान देता है। यह स्थायी खेती, पानी के प्रबंधन, गांवों में ऊर्जा, कारीगरी उद्योग और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है।

बेहद विस्तृत नेटवर्क | इस अभियान के नेटवर्क में 3,696 संस्थान शामिल हैं। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 584 जिलों के तहत 17,405 गांव इससे जुड़े हैं। इसका हिस्सा बने स्टूडेंट्स और टीचर्स को विभिन्न मुद्दों पर बात करने और अन्य गतिविधियों के लिए चुने हुए गांवों में भेजा जाता है। छात्रों ने अब तक 6,000 से अधिक गांवों में 6 लाख से अधिक घरों में सर्वे किया है।

सामाजिक सरोकार | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए नया कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य रिसर्च स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना और अनुभव के जरिए सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। AICTE ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 100 घंटे की ग्रामीण इंटर्नशिप योजना लागू की है।

कॉमन रूम

शिक्षकों का विकास | उन्नत भारत अभियान ने शिक्षकों की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। 600 से भी ज्यादा वेबिनार और कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों को जनजातीय विकास और शिक्षा नीति जैसी जरूरी बातों के बारे में बताया गया है। इस अभियान के लिए CSIR, विज्ञान भारती, ट्राइफेड समेत 15 से अधिक संगठनों ने साथ दिया। कोविड काल में 'उन्नत भारत ग्राम आरोग्य शृंखला' शुरू की गई थी। 14 राज्यों में 27 प्रॉजेक्ट को वित्तीय मदद दी गई।

ग्रामीण सशक्तीकरण | हजारों संस्थानों और लाखों छात्रों वाले नेटवर्क के साथ उन्नत भारत अभियान अनुभवात्मक शिक्षा, नैतिक वृद्धि और सतत विकास को लगातार बढ़ावा दे रहा है। सहभागी दृष्टिकोण और टेक्नॉलजी को अपनाकर छात्रों और ग्रामीणों को मुश्किलों का समाधान तलाशने के काबिल बनाया जा रहा है। IIT दिल्ली कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।

सकारात्मक बदलाव | उन्नत भारत अभियान ग्रामीण शिक्षा, नवाचार और सशक्तीकरण के अपने मिशन के लिए समर्पित है। भविष्य में यह अभियान शैक्षणिक संस्थानों में नई चीजों को बढ़ावा देगा। साथ ही, विज्ञान और टेक्नॉलजी का उपयोग करके समाज और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

(लेखक IIT Delhi में प्रफेसर और उन्नत भारत अभियान के नैशनल कोऑर्डिनेटर हैं)

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

DMK-BJP को लेकर चर्चा

तमिलनाडु में एक आयोजन के बाद सियासी चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। चेन्नै में DMK संस्थापक एम करुणानिधि का शताब्दी समारोह था। इसमें केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी मौजूद थे। कार्यक्रम में

राजनाथ ने न सिर्फ करुणानिधि और स्टालिन की तारीफ की, बल्कि बदले में स्टालिन ने भी राजनाथ और आयोजन की बहुत प्रशंसा की। स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि राजनाथ सिंह ने करुणानिधि के बारे में जितनी बातें कहीं, उतनी तो कई बार DMK के नेता भी नहीं कर पाते हैं। यह आयोजन केंद्र सरकार की ओर से किया गया था। इसके बाद DMK और BJP के बीच सियासी संबंधों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कुछ DMK नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए। AIADMK ने इसे BJP-DMK के बीच गुप्त डील बताया। मामला बढ़ने के बाद स्टालिन को बयान देना पड़ा कि चूंकि आयोजन केंद्र सरकार की ओर से था, ऐसे में कौन आएगा और कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार उनके पास नहीं था। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस-DMK का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम ने दक्षिण के इस राज्य में नई सियासी चर्चा तो छेड़ ही दी है।

कश्मीर में कांग्रेस का प्लान

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में वहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा? नैशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। कांग्रेस की कश्मीर इकाई अकेले दम पर चुनाव लड़ने के पक्ष में थी। स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि अपने बलबूते पूरे राज्य में मजबूती से उभरने का यह अब तक का सबसे शानदार मौका है।

हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। ऐसे में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर पहुंचे तो गठबंधन की घोषणा हो गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल ने कहा कि उनका सम्मान रखा जाएगा। राज्य इकाई के नेताओं के आत्मविश्वास जताने के बावजूद कांग्रेस अगर गठबंधन के लिए तैयार हुई, तो इसकी वजह है कि अभी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता BJP को कमजोर करना है। इसके साथ ही राहुल गांधी के करीबी नेताओं का कहना है कि पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती, जिससे BJP को फायदा पहुंचे। इस रणनीति के तहत ही वह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल से समझौता करने को तैयार है।

लैटरल एंट्री पर ग़लती

लैटरल एंट्री को लेकर निकले विज्ञापन से सरकार की किरकिरी हुई। 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस पर विपक्षी दलों के हमलावर रुख और तेज होती सियासत के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब अंदरखाने चर्चा है कि आखिर इतने पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले हर स्तर पर मंथन क्यों नहीं हुआ? सरकार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर में हड़बड़ी में विज्ञापन कैसे निकला। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जब पता लगाया, तो मालूम हुआ कि कई स्तर पर इस बारे में जरूरी चर्चा नहीं हुई। लंबित पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ विज्ञापन जारी कर दिए गए। सरकार के अंदर राय है कि इतने पदों पर एक साथ नियुक्ति के विज्ञापन के कारण अधिक विवाद हुआ। अगर कम पदों के लिए ऐसा होता, तो शायद विवाद कम होता। यानी कुल मिलाकर गलती विज्ञापन की निकल आई।

चंपई पर BJP में उलझन

झारखंड में पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर पिछले कुछ दिन काफी उलझन भरे रहे। उनका JMM छोड़ना तय था, लेकिन अगले कदम के बारे में स्पष्टता नहीं थी। दरअसल, चंपई सोरेन को लेकर BJP दो तरह के विचार

में थी। एक वर्ग उन्हें तुरंत पार्टी में शामिल कर राज्यसभा सीट देने के पक्ष में था। वहीं, दूसरा वर्ग नहीं चाहता था कि उन्हें पार्टी में लिया जाए। इसके पीछे तर्क था कि उनके आने से लाभ नहीं होगा। हां, चंपई सोरेन अगर अपनी पार्टी बनाते हैं, तो उन्हें जो वोट मिलेगा वह JMM में सेंध हो सकता है। आखिर में यही हुआ। BJP में शामिल होने के बजाय चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। हालांकि अब यहां भी पेच है। सवाल यह है कि क्या उनका BJP से गठबंधन होगा? इसे लेकर पार्टी में दो तरह के विचार बन रहे हैं। BJP नेतृत्व को लगता है कि गठबंधन हुआ तो चंपई की पार्टी को सीटें देनी होंगी। इस बार BJP राज्य में अकेले दम पर अधिकतम सीटें लड़ना चाहती है। पार्टी का यह भी गणित है कि चंपई सोरेन अगर स्वतंत्र होकर, बिना गठबंधन चुनावी मैदान में रहते हैं तो इसका अधिक लाभ BJP को मिलेगा। चुनाव के बाद चंपई सोरेन के साथ कुछ समझौता हो सकता है। कुल मिलाकर चंपई सोरेन ने BJP का समीकरण बदल दिया।

नीतीश-लालू की जय

अभी बिहार में एक मंत्री की किताब चर्चा में है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को महानायक बताया गया है।

इस किताब के लेखक, नीतीश के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे ऐसा सियासी संदेश गया कि अब वह मंत्री, नीतीश कुमार से अधिक BJP के करीब जा रहे हैं। लेकिन इस किताब ने ऐसी सारी चर्चाओं को खत्म कर दिया। वैसे दिलचस्प बात यह है कि किताब में लालू प्रसाद यादव की भी तारीफ की गई है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ रिश्ते बनें मजबूत

22 अगस्त का संपादकीय 'रिश्तों में संतुलन' पढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और कीव की यात्रा बेहद खास है। पिछले 45 वर्षों में पोलैंड जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में पोलैंड की मदद को भुलाया नहीं जा सकता। रूस-यूक्रेन युद्ध में जहां कुछ देशों ने मतलब साधने की कोशिश की, वहीं भारत ने हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की। कई मौकों पर पीएम ने स्पष्ट किया है कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। इस यात्रा से दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे।

पैथर तोमर, किशन गंज

■ चुनौतियों भरा सफर

यह पत्र 21 अगस्त के संपादकीय 'असुरक्षित औरतें' के संबंध में है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट में दी गई बातें हैरान करती हैं। पहले तो राज्य सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को 5 वर्ष तक दबा कर रखा गया। RTI के जरिए इसे बाहर लाने की लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से ही युवा अपना करियर तलाशते रहे हैं, लेकिन अपनी सफलता के लिए उन्हें कई मुश्किल चुनौतियों से गुजरना होता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, ईमेल से

■ चांद के आंगन में

भारत ने पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 उतारकर अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक सफलता पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' मनाने की घोषणा की है। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। मिशन की शुरुआत डॉ. विक्रम साराभाई ने की थी और ISRO के वर्तमान चेयरमैन डॉ. एस. सोमनाथ के नेतृत्व में यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हमें अपने लक्ष्य को पाने और शीर्ष तक पहुंचने के लिए इस सफर को जारी रखना है।

सदा बिहारी साहू, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

चंपई सोरेन बोले, नई पार्टी बनाऊंगा, दोस्त मिलने पर साथ जाऊंगा - खबर

- दोस्त मिले होते तो नई पार्टी बनाने की नौबत ही नहीं आती।

सीमा रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

ईश्वर को सिर्फ़ पाप नहीं, हमारे पुण्य भी चाहिए

आनंदमूर्ति गुरुमां

दिल में समर्पण का भाव आते ही भक्त जान जाता है कि अब तीर्थ करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं रह गई। अब मेरा दिल ही तीर्थ हो चुका है। जब अविद्या और अज्ञान मन से दूर हो गए तो बाहर जाकर किस गंगा में डुबकी लगाऊं? जो ज्ञान की गंगा दिल में बह रही है, इसी में सुस्नात होकर पवित्र हो गया हूं। कबीर साहिब का वचन है, 'कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्यो हरि फिरे कहत कबीर कबीर।' मन की यह निर्मलता तभी आती है, जब हम संपूर्णता से समर्पण कर पाते हैं। याद रहे, समर्पण करते समय ईश्वर को सिर्फ अपने पाप ही चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। समर्पण पूर्णरूप से तभी होता है, जब हम अपने पुण्य भी चढ़ाते हैं। अपने पाप-पुण्य, गुण-अवगुण, सब कुछ चढ़ाकर निर्भार, बोझरहित हो जाएं। फिर जो हो सो हो।

'दीया जले अगम का बिन बाती बिन तेल'। अगम की दिव्य सूरत अब मेरे दिल में ही जगमगा रही है और अब उस आनंदकंद के आनंद का अमृत मेरे मन के कोने-कोने में बरस रहा है। वेद की ऋचाएं गाती हैं कि प्रभु मेरे ही मन के मूल में हैं। परमचेतन, आनंदघन मेरे ही भीतर विराजमान है। लेकिन जब आनंदस्वरूप परमात्मा मेरे ही भीतर मौजूद है, तो मेरा मन तरसता क्यों है? मेरा मन दुखी क्यों है? मेरा मन अशांत क्यों है? मुझको तो आनंद से झूमते रहना चाहिए। मेरा गीत तो कभी बंद ही नहीं होना चाहिए। हम ऐसे शहंशाह हैं, जो भिखारी का जीवन जी रहे हैं। हम रोज उठकर गाते तो जरूर हैं कि 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव', कुछ रिश्ते भी गिना देते हैं कि तुम ही मेरी मां हो, पिता हो, मेरे बंधु हो, सखा हो। हे परमात्मा! मेरे सभी रिश्ते तुम्हारे ही साथ हैं। फिर मैं एक मामूली-सा जीव भर कैसे हो सकता हूं? मैं फिर दीन-हीन, कंगाल कैसे हो सकता हूं? हे प्रभु! तुम हमारे सर्वस्व हो। मैं तुझ अनंतकोटि ब्रह्मांड के नायक, कर्ता, नियंता ईश्वर की संतान हूं।

संतान अपने पिता की उपलब्धियों पर मान करती है। फिर हमारा जो परमपिता है, उस परमात्मा की उपलब्धियों और शक्तियों के आगे तो कोई भी नहीं टिकता। जिस इंसान को यह बात समझ आ जाए, उसके जीवन में फिर एक अजीब-सी बेपरवाही आ जाती है। इसी को तो 'मलंग' कहते हैं। मलंग को किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। वह अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ ही सब प्यार-प्रेम कर लेता है। अगर पैदल चलना पड़े तो मलंग पैदल चलकर खुश है। पैदल भी चलता है, तो राजा बनकर। फिर अगर किसी ने अपनी बढ़िया-सी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसमें भी शान से बैठता है।

सच यह है कि संसार के साथ आप उठते हो, बैठते हो, मौज-मस्ती करते हो तो आपको खुशी होती है। अगर संसार में खुशी है, तो परमात्मा है परमानंदरूप। जब कोई उसके प्रेम में रंग जाता है, तो जीवन मलंग हो जाता है। जब जीवन मलंग हो जाए, तो फिर हर हाल में, हर रूप में, हर स्वरूप में, खुशी में, गमी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर चीज में उसी के रंग को देखता है। जीवन के इन सतरंगों को देख-देख कर जीवन को उन रंगों से भरपूर भर लेता है। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब भीतर प्रेम का रंग चढ़ जाए।

338 करोड़ डालर का व्यापार हुआ था भारत-यूक्रेन के बीच, वर्ष 2021-22 के दौरान, परंतु रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में निरंतर गिरावट आती गई।

मोदी की यूक्रेन यात्रा

स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 से 23 अगस्त के दौरान पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं। इस क्रम में आज उनके यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह यात्रा रूस-यूक्रेन संघर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण तो है ही, सोवियत संघ से अलग होकर एक देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा होगी। पीएम मोदी की यह यात्रा इस लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा के निहितार्थ और भारत-रूस संबंधों पर इसके संभावित असर को भी समझना चाहिए

डा. मदन मोहन गुप्त
शोधार्थी, सेंटर फार रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, जेएनयू

बुधवार को पोलैंड की राजधानी वारसा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पीआइबी

बदलते राष्ट्रीय हितों एवं क्षेत्रीय संघर्षों के बीच विश्व के तमाम देशों ने समयानुसार अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। ऐसे में संघर्ष-समाधान हेतु भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक और पारंपरिक नीतियों, यथा वार्ता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राथमिकता देना, आक्रामक देशों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदर्भ में भारत ने एक बार फिर से अपनी 'पारंपरिक एवं स्वतंत्र विदेश नीति' का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड की यात्रा संपन्न करके यूक्रेन की राजनीतिक यात्रा पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड यात्रा की है। उल्लेखनीय कि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, जबकि यूक्रेन, नाटो का सदस्य बनने हेतु अग्रसर है।

लगभग डेढ़ महीने पहले 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। तब से ही यह निश्चित हो गया था कि अगले कुछ दिनों में वह यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में दोनों ही देशों ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि इस यात्रा की योजना अचानक तैयार नहीं हुई है। फरवरी 2022 रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन यात्रा के लिए आग्रह करते रहे हैं। इस साल मार्च में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को मोदी की यूक्रेन यात्रा के लिए निमंत्रण दिया था। हाल ही में इटली में आयोजित जी-7 सम्मेलन में बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की भेंट हुई। जिसमें जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि यूक्रेन जाने से पहले मोदी ने मास्को यात्रा करके न केवल यूक्रेन, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया था। मोदी की रूस यात्रा को अमेरिका और पश्चिम ने 'अनपेक्षित' बताया था, जबकि जेलेंस्की ने तो खुलेआम निराशा जाहिर की थी। ऐसे में इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि नई दिल्ली को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और विदेश नीति की प्रासंगिकता हेतु यूक्रेन यात्रा आवश्यक हो गई थी।

वैश्विक संवेदना की उम्मीद : इस यात्रा से यह बात एकदम स्पष्ट है कि जेलेंस्की, प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध स्थलों का दौरा जरूर कराएंगे। क्योंकि जेलेंस्की अब तक दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को युद्ध स्थलों तक ले जाते रहे हैं, चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो हों या ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक हों। युद्ध स्थलों तक राष्ट्राध्यक्षों को ले जाने के पीछे जेलेंस्की की अब तक यही कोशिश रही है कि दुनिया इस बात को समझे कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर 'क्षेत्रीय-भय' और मानवीय संकट पैदा किया है। जिससे वैश्विक संवेदना और सहयोग यूक्रेन को प्राप्त हो और रूस को आक्रमणकारी राज्य घोषित कर विश्व समुदाय से अलग-थलग किया जा सके। लेकिन यहां इस बात को समझना जरूरी है कि भारत ने खुले मंच से कभी भी रूस की आलोचना नहीं की है और न ही उसके विरुद्ध लाए गए किसी भी प्रस्ताव का समर्थन किया है।

हां इस बात को नई दिल्ली ने बार-बार दोहराया है कि दोनों देशों को तुरंत संघर्ष रोक देना चाहिए और शांति हेतु प्रयास करना चाहिए। हालांकि भारत के इस स्टैंड से यूक्रेन और नाटो देश खुश नहीं रहे हैं। वह हमेशा चाहते रहे कि भारत खुलकर उनका साथ दे और रूस पर उनके द्वारा लगाए गए तमाम तरह के प्रतिबंधों पर सहमति दे। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय और नागरिक हितों को ध्यान में रखकर रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। जिसको लेकर यूक्रेन ने भारी रोष प्रकट किया और रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को 'यूक्रेनी लोगों के खून की कीमत का सौदा' कहा। हालांकि समय के साथ उनको समझ आया कि भारत के बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। जिसको लेकर नाटो देशों ने भी कई बार भारत से मध्यस्थता का आग्रह किया। ऐसे में संघर्ष के लगभग ढाई साल बाद नरेन्द्र मोदी की इस यूक्रेन यात्रा से नाटो देशों की भी अपेक्षाएं अधिक होंगी।

भारत की रणनीति : पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है। और अब जबकि यूरोप के बड़े क्षेत्रफल वाला देश यूक्रेन, नाटो का सदस्य बनने की ओर अग्रसर है, तो भारत अधिक समय तक दूरी नहीं बनाए रख सकता है। क्योंकि यूक्रेन से दूरी का अर्थ है नाटो देशों से दूरी। दूसरे, भारत के सीमा क्षेत्र और आर्थिक मोर्चे पर चीन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में दोनों स्तर पर यूरोप का सहयोग भारत को प्राप्त होगा, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र एशिया में अपने हितों को चीन नहीं, बल्कि भारत के करीब पाते हैं।

दूसरी तरफ यूक्रेन-संघर्ष के बाद से ही रूस और चीन के बीच सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और निकट भविष्य में दोनों के बीच और भी बेहतर संबंधों की उम्मीद है। यहां गौर करने वाली बात है कि यूरोपीय प्रतिबंधों के खिलाफ भारत और चीन दोनों ही रूस को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के मद्देनजर आवश्यकता इस बात की है कि भारत, रूस-चीन मित्रता का विकल्प तलाशें। ऐसे में यूरोप से और भी प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए यूक्रेन यात्रा एक बेहतर कड़ी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ, दो साल से अधिक समय से चल रहे रूस के साथ संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि थोड़े बहुत नुकसान के अलावा रूस, यूक्रेन का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।

ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत-यूक्रेन संबंध, भारत और यूरोपीय देशों के मध्य संबंधों की तरह ही नए आयाम स्थापित करेगा।

व्यापारिक संबंध : भारत उन देशों में शामिल है जिसने 1991 में सोवियत संघ से अलग होते ही यूक्रेन को सबसे पहले मान्यता दी। यूक्रेन ने भी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया। कूटनीतिक संबंधों के अलावा दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर प्रगति की है। यूक्रेन संघर्ष से पहले एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत, यूक्रेन का सबसे बड़ा भागीदार देश था। भारत, मेडिकल वस्तुएं, फर्टिलाइजर्स, तिलहन और अन्य खाद्यान्न का प्रमुख आयातक था। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, भारत-यूक्रेन के बीच कुल 338 करोड़ डालर का व्यापार हुआ था। जिसमें भारत ने यूक्रेन को 47 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया था, जबकि 291 डालर मूल्य का आयात किया था। लेकिन फरवरी 2022 के बाद से इसमें निरंतर गिरावट देखी गई है। संघर्ष की वजह से यूक्रेनी कृषक बरबाद हो गए और अन्य नागरिक व मजदूर पलायन कर गए। जिससे एशिया और यूरोप के देशों में खाद्यान्न समस्या देखने को मिली। जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार संबंधों पर विशेष चर्चा की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कीव में भारतीय डायसपोरा और छात्रों से भी संवाद करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने भारतीय छात्र जाते हैं। इन छात्रों की संख्या लगभग बीस हजार है। लेकिन रूस आक्रमण के समय छात्रों को वापस लाना पड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता, डायसपोरा और छात्र हितों पर जेलेंस्की से चर्चा होगी।

रूस के लिए नरेन्द्र मोदी की यात्रा के मायने

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की विदेश नीति के लिए जाना जाता है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में भी इस बात को दोहराया गया। स्वाभाविक है कि मोदी की हालिया रूस यात्रा के दौरान जिस प्रकार की प्रतिक्रिया यूक्रेन और नाटो देशों ने व्यक्त की थी, उस तरह की प्रतिक्रिया रूस की नहीं होगी। लेकिन इस यात्रा से मास्को बहुत सहज हो, इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रारंभ होने के बाद से ही भारत रूस के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन रूस से शांति बनाए रखने की अपील भी करता रहा है। रूस ने भी भारत की इस संतुलित नीति की कई बार तारीफ की है। लेकिन अब जब मोदी की कीव यात्रा नियोजित है, तो पूरी संभावना है कि रूस भी भारत के साथ संबंधों का विकल्प तलाश सकता है। हालांकि कुछ विद्वान भारत को रूस के साथ संबंधों के लिहाज से इस यात्रा को महत्व नहीं देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में इस यात्रा से रूस-भारत संबंधों में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। भारत हमेशा से ही इस बात पर कायम रहा है कि जहां कहीं भी संघर्ष होगा, संघर्ष से पीड़ित लोग होंगे, उनकी सहायता करना भारत का कर्तव्य है। पीड़ितों की रक्षा और सहयोग भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता है।

रूस-यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत, यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए खाद्यान्न सामग्री, मेडिकल उपकरण एवं अन्य राहत एवं बचाव सामग्री भेजता रहा है। भारत ने युद्ध पीड़ितों के पक्ष में वैश्विक मंचों से भी आह्वान किया है, जिसको लेकर रूस ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा मात्र से भारत-रूस संबंधों पर कोई विशेष असर हो, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। रूस ने भी कई मंचों पर इस बात को दोहराया है कि भारत, रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करवाने में सक्षम है।

वैश्विक राजनीति के नजरिए से यह यात्रा भले ही द्विपक्षीय संबंधों के निमित्त हो रही है, लेकिन इसका महत्व व्यापक और सकारात्मक होगा। भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति वैश्विक समुदाय के लिए उदाहरण है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का रूस के तुरंत बाद यूक्रेन की यात्रा पर जाना, संघर्ष समाधान हेतु भारत की रुचि को प्रदर्शित करता है। साथ ही, वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत की नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

(डा. मदन मोहन गुप्त)

खरी-खरी

यहां और वहां के दुष्कर्म में फर्क

डा. हरीश कुमार सिंह

देश में एक ही तरह की शर्मनाक घटना या दुर्घटना लगभग रोज हो रही है। कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में। इसे आप दुष्कर्म, बलात्कार, अमानवीयता कह सकते हैं। यह क्रूर घटना बच्चियों एवं युवा महिलाओं के साथ हो रही है। ताजी घटना में एक युवा महिला डाक्टर को पूरब के एक ममतामयी राज्य में ड्यूटी के दौरान दुष्कर्म कर बेहरमी से मार डाला गया। फिर कुछ दिन बाद एक प्रदेश में एक सनातनी विद्यालय में स्कूली बच्चियों से गलत हरकत की गई। मजे की बात यह है कि दोनों प्रकरणों में प्रशासन ने जिसकी सरकार है, उसका साथ दिया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों कांडों में बड़ी मुश्किल से ही लिखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शर्मनाक कांड को दोनों ही स्थानों पर दबाने की योजना थी। एक जगह उनकी सरकार की बदनामी थी तो दूसरी जगह विद्यालय सत्ताधारी दल की ही शाखा का होने से यहां भी सरकार पर संकट आन पड़ा था।

पूरब के बलात्कार पर जो राजनीतिक दल मुंह में दही जमाए बैठे थे, वे महाप्रदेश की दुष्कर्म की घटना के विरोध में आसमान उठाए थे। महाप्रदेश के स्कूल के कांड को जो दबाना चाह रहे थे वो पूरब के बलात्कार की रपट नहीं लिखने पर न्यायालय की शरण में थे। देश की जनता यह नहीं समझ पा रही थी कि दोनों घटनाएं हैं तो एक जैसी ही, पर राजनीतिक दल, दोनों घटनाओं पर अलग अलग स्टैंड कैसे ले सकते हैं। ये तेरा दुष्कर्म, ये मेरा दुष्कर्म है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन औसतन सौ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। कहा जा सकता है कि इन घटनाओं के जरिये बतौर समाज हमारा ही दुष्कर्म हो रहा है। दुष्कर्म करने वाले भी सभी वर्ग के हैं, सभी दलों के महानुभाव हैं। मगर कोई राजनीतिक दल हो या देश की आम जनता, वह एक दुष्कर्म के समर्थन में खड़ी होती है तो दूसरे दुष्कर्म पर चुप्पी मार जाती है। दुष्कर्म कहीं भी हो, उसका विरोध एक जैसा ही होना चाहिए, परंतु हम कभी नहीं सुधरेंगे और दुष्कर्म, दुष्कर्म में भी फर्क करेंगे और अपने अपने तर्क गढ़कर उन्हें स्वीकार या खारिज करने की कोशिश करेंगे।

पोस्ट

गत दिनों संसद में टीएमसी के एक सांसद कह रहे थे कि देश में ममता माडल लागू करिए। हां तो यह है उनका माडल, जहां डाक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने पड़ रहे हैं।
बालियान@Baliyan_x

डाक्टरों से 36 घंटे लगातार शिफ्ट में काम कराना अनुचित है। कभी-कभी इमरजेंसी में ज्यादा काम लिया जा सकता है, परंतु ऐसा रूटीन में कराना अमानवीय है। डाक्टर थकान में गलत निर्णय भी ले सकते हैं।
आरके विज@ipsvijrk

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से 47 से अधिक देशों के प्रमुखों ने यूक्रेन की यात्रा की है, जबकि 40 से अधिक देशों के प्रमुखों ने रूस की। इनमें कुछ ही राष्ट्र प्रमुख ऐसे हैं जिन्होंने रूस-यूक्रेन, दोनों की यात्रा की। इनमें प्रमुख हैं- आस्ट्रिया, इंडोनेशिया और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

एडीआर के अनुसार वर्तमान 16 सांसदों और 135 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? ऐसे लोगों को निर्वाचित निकायों में प्रवेश से वंचित किया जाना चाहिए।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस-अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करने में मदद मिलेगी?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या विधानसभा चुनाव बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मिलती सुप्रिम कोर्ट से रोज-रोज फटकार,
दीदी कर जाती हजम ले करके चटखार।
ले करके चटखार दिखे हरदम बेशर्मी,
थू-थू करता देश देख उनकी हठधर्मी।
लानत सुन चहुंओर कान पर जूं ना हिलती,
गर्मी चढ़े दिमाग उन्हें जब सत्ता मिलती।
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

क्यों बदल रहे चम्पाई, क्या है असलियत!

चम्पाई सोरेन। फाइल

इस सप्ताह के आरंभ में झारखंड के एक राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान खींचा। यह अनायास था या पूर्व नियोजित, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अपने दल के खिलाफ बगावत के स्वर बुलंद किए। चम्पाई पहली बार इस वर्ष के शुरुआती महीनों में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद नए सीएम के तौर पर उनका नाम सामने आया था। वह लगभग पांच माह तक सीएम रहे। इस दौरान उनके किसी भी बात की शुरुआत और समापन हेमंत सोरेन के गुणगान से होती थी। वह गर्व से अपनी सरकार को हेमंत-पार्ट टू भी कहते थे।

हेमंत सोरेन जब जमानत पर रिहा होकर आए तो चम्पाई को कुर्सी छोड़नी पड़ी और हेमंत ने फिर से जब सत्ता संभाली तो चम्पाई सोरेन उनकी कैबिनेट में मंत्री भी बने। चम्पाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने उनकी घेराबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन चम्पाई के हटते ही पार्टी नेताओं का उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। इससे राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा बलवती होने लगी कि कहीं न कहीं कुछ पक रहा है। हालांकि चम्पाई के फिर से हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होने के बाद यह लगने लगा था कि भाजपा की दाल नहीं गल रही है, लेकिन 18 अगस्त को उस वक्त खदबदाहट बढ़ी, जब यह सूचना आई कि चम्पाई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली की उड़ान पर हैं। यहां तक कहा गया कि उनके साथ सत्तारूढ़ झामुमो के छह विधायक भी हैं। स्वाभाविक रूप से मीडिया ने इसे तेजी से लपका। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने के पहले कैमरे तैनात हो गए थे। दिल्ली पहुंचने पर चम्पाई ने तमाम अटकलों को नकारते हुए कहा कि वे जहां थे, वहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके साथ कोई विधायक भी नहीं था। जिन विधायकों के नाम आ रहे थे, उन्होंने आनन-फानन में अपना स्पष्टीकरण देना आरंभ किया।

बाद में 18 अगस्त को ही शाम में जब चम्पाई सोरेन का लिखित बयान सामने आया तो स्पष्ट हो गया कि हरे रंग (झामुमो के झंडे का यही रंग है) में रंगे चम्पाई अब रंग बदलने को आतुर हैं। उन्होंने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया, जो उनके सामने थे। भावुकता मिश्रित उनके बयान में तीन विकल्प बताए गए। इनमें पहला राजनीतिक संन्यास लेने, दूसरा अपना दल बनाने और तीसरा नए दोस्त के साथ चलने का था। चर्चा उड़ी कि दिल्ली में भाजपा के वरीय नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उनके दो दिवसीय प्रवास में आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी वापसी भी उसी रास्ते से हुई, जिधर से उन्होंने दिल्ली की राह पकड़ी थी। वह कोलकाता आए और वहां से सड़क मार्ग से अपने गृहक्षेत्र सरायकेला के लिए निकले। झारखंड में एंट्री के साथ ही मीडियाकर्मियों से जब उनका सामना हुआ तो उन्होंने सधे अंदाज में कहा कि राजनीतिक संन्यास लेने का उनका पहला विकल्प समाप्त हो गया। अब वे दूसरे और तीसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे। चम्पाई ने अपने गृहक्षेत्र पहुंचकर दूसरे और तीसरे विकल्प की ओर कदम बढ़ाना आरंभ किया। अब वह अपनी नई पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं।

हालांकि भाजपा के नेताओं का आफ द रिकार्ड कहना है कि वह भाजपा में ही शामिल होंगे, लेकिन चम्पाई अभी इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं। चम्पाई सोरेन अभी भी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद पर बने हुए हैं। उनके विरुद्ध पार्टी की ओर से भी कार्रवाई की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। झामुमो से कोई खुलकर चम्पाई के खिलाफ बोल भी नहीं रहा है। इससे अलग कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चम्पाई सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए उनके बगावत की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।

राजनीतिक गलियारे में भी यह सवाल तैर रहा है कि चम्पाई सोरेन को आखिरकार अलग रास्ता चुनना था तो उन्होंने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल होने की सहमति क्यों दी? उनके विरुद्ध लग रहे आरोपों में एक गंभीर आरोप यह भी है कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान वे भाजपा से सांठगांठ करने में लगे थे। उन्होंने पुलिस व्यवस्था में बदलाव वाले उस नए कानून के पक्ष में विज्ञापन जारी कराए, जिसका आइएनडीआइए विरोध कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि चम्पाई सोरेन अपने साथ-साथ अपने परिवार का राजनीतिक विस्तार करना चाहते हैं और बेटे के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सीट चाहते हैं। पुत्रमोह में झामुमो से हरी झंडी नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना नया रास्ता चुना।

फिलहाल चम्पाई खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने में लगे हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता उनकी प्रशंसा में जुटे हैं तो इसकी वजह आगामी विधानसभा चुनाव में आगे निकलने की होड़ है। चम्पाई सोरेन की नई राजनीतिक कवायद ने यह भी तय कर दिया है कि उनके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बची। चुनाव में यह तय होगा कि उनका नया रंग क्या असर दिखाता है?

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

अंतरिक्ष में खनन पर चिंतन

पृथ्वी पर लंबे समय से संसाधनों का दोहन जारी है, जिनके निकट भविष्य में समाप्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में विज्ञानी अब अंतरिक्ष में संसाधनों की तलाश में जुटे हैं

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेलीपरफार्मेंस से संबद्ध

प्रतीकात्मक

मानव सभ्यता के इतिहास में दर्ज इस तथ्य के ऐतिहासिक पहलू खोजे जाएं कि आखिर इंसान ने सबसे ज्यादा संघर्ष, शोध, अन्वेषण और निवेश किस काम में किया, तो जवाब मिलेगा कि यह सब कुछ संसाधनों की तलाश में किया गया। जैसे यूरोप के लोग मसालों की खोज में दुनिया के विभिन्न देशों में गए। अमेरिका के लोग सोना, तेल, लकड़ी और नई जमीनों की खोज में यहां-वहां भटके। यूरोप और अमेरिका के देशों ने संसाधनों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इतनी प्रगति की है कि उनमें से ज्यादातर की गिनती विकसित देशों में होती है। हालांकि अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब इंसान अंतरिक्ष में शोध और खनन की दिशा में प्रयासरत है। भारतीय स्पेस एजेंसी-इसरो के विज्ञानी भी अब अपने भावी अंतरिक्ष और चंद्र मिशनों की सहायता से पृथ्वी से दूर पिंडों पर खनन की संभावना तलाशने में जुट गए हैं। कह सकते हैं कि यदि भारत विकसित देशों की कतार में पहुंचना चाहता है, तो उसे संसाधनों की खोज के ऐसे ही नए ठिकानों की खोज करनी होगी।

ऐसे घटेगा अंतरिक्ष से दोहन का खर्च : आज भले ही अंतरिक्ष में संसाधनों की खोज और खनन का काम खर्चीला और बेहद महंगा लगता हो, लेकिन संभव है कि आगे चलकर कम खर्च में ऐसा करना संभव हो जाए। इसका एक उद्देश्य और है। वह यह है कि यदि कभी हमारी पृथ्वी के सामने संसाधनों के अभाव का संकट खड़ा होने लगे तो उन संसाधनों को अंतरिक्ष से बटोर लाया जाए। खास तौर से जिस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने सारे स्पेस मिशनों को बेहद किफायती बनाकर उन्हें संचालित करता है, उसमें ऐसी संभावनाएं आकार लेती दिखाई देती हैं। हाल ही में, इसरो की एक इकाई-इस्ट्रैक के निदेशक बीएन रामकृष्ण ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि इसरो का अगला उद्देश्य भावी चंद्रयानों को चंद्र-सतह पर ज्यादा समय के लिए सक्रिय रखना है, ताकि उससे चंद्रमा पर पानी के अलावा अन्य खनिजों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। इसके लिए ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिसकी मदद से चंद्रयान अधिक समय तक चंद्रमा पर टिक सकेंगे। इसरो के विज्ञानियों के अनुसार, अब उनका उद्देश्य अंतरिक्ष से सोना, प्लेटिनम और अन्य महंगे खनिजों की खोज और खनन (माइनिंग) की संभावनाओं का पता लगाना है। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काइपर (कुइपर) बेल्ट में खनन की कोशिशें शुरू करना है, ताकि वहां से सोना, प्लेटिनम आदि अन्य महंगी धातुओं की माइनिंग कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने का प्रबंध किया जा सके। काइपर बेल्ट उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है जो नेप्च्यून के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।

पृथ्वी के संसाधनों के समाप्त होने की आशंका : बेशक, धरती की कोख में अकूत खनिज संपदा है। इसकी तह में उतरकर इंसान ने उसे हासिल भी किया। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह संपदा अब घटने लगी है। पृथ्वी के संसाधनों की भरपाई कहां से और कैसे होगी, इसके विकल्प और उपाय खोजे जा रहे हैं। इन विकल्पों की चर्चा के तहत ही इंसान के निशाने पर अब अंतरिक्ष है। लेकिन चंद्रमा और क्षुद्रग्रहों समेत अन्य अंतरिक्षीय पिंडों पर खनन की जरूरत क्या है, इसके लिए जानना जरूरी है कि अगले 50-100 वर्षों में पृथ्वी पर मौजूद सोना, चांदी, लेड, जिंक, कापर, टिन आदि सभी धातुओं और खनिजों का पूरी तरह दोहन कर लिया जाएगा। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले जिस लीथियम के विशाल भंडारों की जो खोज हाल के वर्षों में हुई है, वे भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इसरो समेत विश्व की अन्य सरकारी व निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि क्या अंतरिक्षयानों और टेलीस्कोपों की मदद से चंद्रमा, बृहस्पति, काइपर बेल्ट के अलावा ऐसे क्षुद्रग्रहों की तलाश की जा सकती है, जिनमें वांछित संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों।

करीब एक दशक पहले कैलिफोर्निया (अमेरिका) स्थित खगोल विज्ञानी मोना ए. डेल्टिस्काय ने जानकारी दी थी कि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के वायुमंडल में हीरों का अकूत भंडार मौजूद है। दावा किया गया था कि इन ग्रहों के वायुमंडल में द्रवीभूत हाइड्रोजन और हीलियम के कुंडों में हीरों की विशाल मात्रा मौजूद है। विज्ञानियों के अनुसार इस अंबार को डायमंड-वर्षा कहना ज्यादा उचित होगा। विज्ञानी पिछले 40-50 वर्षों से यह दावा भी करते रहे हैं कि यूरेनस और नेप्च्यून जैसे ग्रहों के केंद्र में भी हीरों की विशालकाय मात्रा मौजूद है, परंतु संभवतः वहां ये हीरे द्रव रूप में हो सकते हैं। बहरहाल, इसरो के नए इरादों से विज्ञान जगत की उस संभावना को और बल मिला है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर कम पड़ने वाले संसाधनों की भरपाई अंतरिक्ष से खनन के जरिए मिलने वाले संसाधनों से की जा सकती है।

****

दैनिक जागरण
जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया

अलग-अलग स्कूली बोर्ड

देश के सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार-विमर्श करने जा रहा है, उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में अभी साठ से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उनमें कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या ही बनती हैं। एक तो विभिन्न स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है और दूसरे, उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग-अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरणस्वरूप मेघालय में कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55-56 प्रतिशत रहता है तो मध्य प्रदेश में 60-62 प्रतिशत और केरल एवं तेलंगाना में 90 प्रतिशत से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग-अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड एक माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं तो कुछ यही काम डेढ़-दो माह में करते हैं। अलग-अलग स्कूली बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और वहां उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है तो परीक्षा आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है।

समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूली बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नताएं हैं। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूली बोर्डों के स्तर पर भी एकरूपता का अभाव है। इसका कोई औचित्य नहीं। चूंकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि उनमें कोई साम्य न नजर आए। यह साम्य इसलिए होना चाहिए, क्योंकि इससे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में एकरूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई है। यह इसलिए भी होनी चाहिए, ताकि सभी स्कूली छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब-करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है।

सख्ती आवश्यक

पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिये हथियार और ड्रग्स की हो रही तस्करी एवं उसके दुष्प्रभावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी उचित ही है। अदालत ने ठीक ही कहा है कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं उसे युवाओं में बेचा जा रहा है और इससे एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसी प्रकार की तस्करी से जुड़े एक अपराधी के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह कहा है कि इस तरह के अपराधियों से सख्ती से निपटना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें इस प्रकार के अपराधियों पर तस्करी के ही कई केस दर्ज हैं। ऐसे अपराधी अक्सर जमानत पर छूट जाते हैं और फिर से तस्करी के कार्य में लग जाते हैं। यही नहीं, सीमा पार के तस्करों से मिलीभगत कर ये तस्करी के नए-नए तौर-तरीके भी अपनाते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। इस बात की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ये अपने मंतव्य में कई बार सफल भी हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के हर शहर, हर गांव में नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं। प्रदेश को नशे के दलदल से निकालने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि ऐसे अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसा जाए। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में कानून को और सख्त बनाए, ताकि ऐसे अपराधियों को जल्दी जमानत न मिल सके। सख्ती और कड़े दंड के प्रविधान से ही ऐसे अपराधियों को हतोत्साहित कर युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है।

प्रदेश को नशे के दलदल से निकालने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध सख्ती से शिकंजा कसा जाए

शांति का संदेशवाहक भारत

श्रीराम चौलिया

रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में सही अवसर आने पर और विशेष रूप से जब दोनों पक्ष चाहें, तब भारत शांति का निर्माता बन सकता है

वर्तमान वैश्विक भूराजनीति के केंद्रबिंदु यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे समय यूक्रेन पहुंचे हैं, जब 2022 से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध अनेक शक्तियों के हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया है। मूलतः यह संघर्ष रूस की ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा, उसके असुरक्षा भाव और यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता से सरोकार रखता है। यूरोप के देशों और अमेरिका ने इस युद्ध में जिस प्रकार यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक सहायता की है, उससे यह टकराव वैश्विक स्थिरता और शक्ति संतुलन की समस्या बन गया है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में उभरती विश्व शक्ति भारत की भूमिका को लेकर काफी अपेक्षाएं हैं। यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस की खुले तौर पर निंदा करने और रूस के संग अपने सैन्य और ऊर्जा व्यापार को घटाने हेतु पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर तीव्र दबाव रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाया। इसी के साथ भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ संग अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना जारी रखा और यूक्रेन को मानवीय सहायता देना तथा उसके नेताओं के साथ नियमित बैठकें और बातचीत का सिलसिला कायम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दोहरी नीति को समझाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत दशकों से सभी देशों से समान दूरी बनाने में लगा हुआ था, पर अब वह सभी देशों से समान निकटता बनाने की राह पर है। यानी गुटनिरपेक्षता की पुरानी जंजीर तोड़कर आज भारत बहुपक्षीयता के पथ पर चल रहा है, जो कि उभरती महाशक्ति के लक्षण हैं। इसी बहुपक्षीयता का संकेत मोदी के यूक्रेन दौरे से मिल रहा है। ध्यान रहे कि उन्होंने हाल में रूस की यात्रा भी की है।

गत दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में रूस-यूक्रेन युद्ध पर अनेक पक्षतापूर्ण प्रस्ताव लाए गए और उन पर अधिकतर बार भारत ने तटस्थ रहने का चयन किया। जुलाई 2024 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस एकतरफा प्रस्ताव का समर्थन करने से मना कर दिया था, जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया था। गौरतलब है कि भारत के अलावा 59 अन्य देश थे, जिन्होंने तटस्थ रहना पसंद किया था। जून 2024 में स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति शिखर वार्ता की विज्ञप्ति पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और अपने रुख को समझाते हुए कहा था, "केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों।' आलोचकों ने इसके आधार पर भारत पर ताने कसे कि वह वस्तुतः रूस के पक्ष में है और केवल दिखावे के लिए अपने आप को निष्पक्ष दर्शा रहा है, लेकिन जिस जटिल मोड़ पर यह युद्ध आ खड़ा हुआ है, धीरे-धीरे भारत के रुख में ही तर्कसंगतता और बुद्धिमानी साबित हो रही है।

अवधेश राजपूत

बहुपक्षीयता एक रचनात्मक अवस्था है और भारत इसके जरिये बंटे हुए विश्व के सभी पक्षों के साथ आपसी हित साध रहा है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक किरदार निभाने की स्थिति में आ गया है। जैसे-जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध गतिरोध में फंसता गया, वैसे-वैसे पश्चिमी शक्तियों ने बार-बार मोदी से आग्रह किया कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मित्रता का प्रयोग करके उन्हें इसके लिए मनाएं कि वह यूक्रेन में आक्रमण बंद कर दें और बातचीत से कोई हल निकालें। लंबी लड़ाई लड़ते-लड़ते थकान स्वाभाविक है। आज अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश इस दलदल से निकासी का रास्ता खोज रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस खोज में मार्गदर्शक बन सकता है?

बहुत पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दो टूक कहा था कि "यह युग युद्ध का नहीं है।" कुछ माह पहले मास्को में भारत-रूस शिखर बैठक के समय जब यूक्रेन में रूसी हमलों से अनेक बेगुनाह मारे गए तो मोदी ने पुतिन से साफ कहा, "बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती और संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं पाया जा सकता।" भारत का किरदार केवल बातों तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि इस युद्ध के 'विभिन्न पहलुओं पर दूसरों ने संदेश भेजने के लिए हमारा उपयोग किया है।" भारत ने काला सागर अनाज गलियारा बनाने के लिए तुर्किए और रूस के बीच 'कुछ दृष्टिकोण और चिंताओं को पाटने" में योगदान दिया और 2022 में इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी काम किया था। इस वर्ष भारत ने रूस और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को संदेश भेजकर संवेदनशील जापोरीजिया बिजली संयंत्र की सुरक्षा के बारे में यूक्रेन की चिंताओं के संबंध में भी सकारात्मक योगदान दिया।

भारतीय कूटनीति ने ऐसे छोटे-छोटे उपक्रमों को बढ़ावा दिया है, जो जीवन बचा सकने में सहायक होने के साथ बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में इसी प्रकार दीर्घकालिक शांति के लिए ठोस आधार तैयार किया जा सकता है। प्रभावित विकासशील देशों, जिनकी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गंभीर रूप से बाधित हुई है, के अधिकारों की हिमायत करते हुए भारत ने दुनिया की बहुसंख्यक आबादी के प्रवक्ता की भूमिका भी निभाई है। रही बात सीधे दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की तो इसमें अन्य देशों द्वारा कई पहल की जा चुकी हैं, जो असफल रही हैं। तुर्किए, सऊदी अरब, ब्राजील, चीन, अफ्रीकी देशों के समूह और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने विभिन्न किस्मों के शांति प्रस्ताव, सम्मेलन और युद्धविराम के विचार सामने रखे, लेकिन बात बनी नहीं। वास्तव में जब तक रूस और यूक्रेन स्वयं राजी नहीं होते और जब तक उन्हें युद्धभूमि में डटे रहने में ही अपना भला नजर आता है, तब तक मध्यस्थता व्यर्थ है। भारत सही अवसर पर शांति निर्माता हो सकता है। तब तक शांति के निमित्त और संदेशवाहक बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। रूस-यूक्रेन मामले में राष्ट्रीय हितों पर आधारित मोदी सरकार की कूटनीति संतुलित एवं उचित है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

बरसात और बाढ़ से बढ़ता नुकसान

अनिल प्रकाश जोशी

अब देश में सबसे बड़ी आवश्यकता बेहतर आधारभूत ढांचे का विकास करने वाली नीति की है

इन दिनों केरल में वायनाड के बाद त्रिपुरा के अनेक हिस्से भारी बरसात और बाढ़ से त्रस्त हैं। सच तो यह है कि देश के साथ दुनिया के अनेक हिस्सों में अतिवृष्टि जनित घटनाएं हो रही हैं। ये प्रकृति के बदलते स्वरूप की ओर इशारा कर रही हैं। तीव्र वर्षा के पीछे वह प्रचंड गर्मी ही मुख्य कारण है, जिसने इस बार पृथ्वी को भट्ठी बना दिया है। इस कारण हुए भारी वाष्पोत्सर्जन को किसी न किसी रूप में पानी के रूप में गिरना ही था। इस बार तीव्र वर्षा ने मात्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर या फिर उत्तराखंड में ही कहर नहीं बरपाया, बल्कि केरल के वायनाड से लेकर असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा आदि में अपना असर दिखाया है। स्पष्ट रूप से यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की देन है। जब भी अधिक बारिश होगी तो हमारा मौजूदा आधारभूत ढांचा टिक नहीं सकेगा। ऐसे में अगर भविष्य में ढांचागत विकास को लेकर गंभीरता न बरती गई हो तो नुकसान और बढ़ेगा। हम पर्यावरण के अनुरूप आधारभूत ढांचे के विकास की समझ से अभी भी बहुत दूर हैं। हमारे ढांचागत विकास में इस पहलू की कमी शुरुआत से ही रही है। अब सबसे बड़ी जरूरत एक बेहतर आधारभूत ढांचे के विकास की नीति की है, जिससे नई परिस्थितियों के अनुसार विकास किया जा सके। पिछले एक दशक में बाढ़ या तेज बारिश से सबसे अधिक नुकसान आधारभूत ढांचे को ही हुआ है।

अब अतिवृष्टि से माल के साथ जान का भी नुकसान हो रहा है। इस बार की बारिश ने पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव डाला है। देश के आधे से ज्यादा क्षेत्र इसकी सीधी चपेट में आए हैं। वायनाड में तेज बारिश के चलते हुए भूस्खलन में ही मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई। कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। बिहार और पंजाब ने भी बारिश के गहरे दुष्प्रभाव झेले हैं। उत्तराखंड में लोगों ने जान गंवाई तो हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल में तो एक गांव पूरी तरह खत्म हो गया। अब त्रिपुरा में तबाही हो रही है। बारिश और बाढ़ के चलते हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती-बारी संकट में आ गई है। अभी आर्थिक नुकसान का आकलन सामने नहीं आया है, पर वह अधिक ही होगा। कितनी जानें गईं और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, इसका सटीक आंकड़ा मानसून के अंतिम चरण में ही पता चलेगा। यदि इस बार मानसून लंबा खिंचा तो नुकसान बढ़ने की आशंका है। इसका दोष अनियंत्रित विकास कार्यों को दिया जा रहा है। इसके अलावा वनों की कटान और प्रकृति से छेड़छाड़ भी इसके बड़े कारणों में माने जा रहे हैं। इस पहलू को हमें बेहतर तरीके से समझना होगा।

अगरतला में भारी बारिश के बाद का दृश्य। एएनआइ

हम अपनी सुख-सुविधाओं के लिए पृथ्वी से सीमा से अधिक संसाधन ले रहे हैं। इसके कारण पृथ्वी के तापक्रम में कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। इससे समुद्रों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। चूंकि समुद्र पृथ्वी का बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए इनके तपने से अल नीनो जैसे प्रभाव पैदा हो रहे हैं, जिसके ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। तूफान और अतिवृष्टि का कारण अल नीनो ही है। प्रचंड गर्मी और उसके बाद बाढ़ का सिलसिला सारी दुनिया की समस्या बन गई है। पहले इन आपदाओं की मार गांवों पर ही पड़ती थी, पर इस बार इसने शहरी क्षेत्रों को भी लपेट लिया है। हमारे शहरों में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण पानी के रास्तों का रुकना रहा है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम बदतर है, क्योंकि कभी कल्पना नहीं की गई थी कि कम समय में इतना अधिक पानी बरसेगा। एक दशक पहले शहरों में वर्षा उतनी नहीं होती थी, जितनी अन्य जगह। इसका बड़ा कारण यह था कि शहरों में बढ़ते तापक्रम के कारण एक ऐसा दबाव बन जाता था, जिससे वर्षा निम्न स्तर पर होती थी, लेकिन कुछ समय से बदलती जलवायु ने यह बता दिया है कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। सीधा संदेश यही है कि एक सीमा से अधिक छेड़छाड़ प्रकृति को स्वीकार नहीं है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ हुई है और ऐसा करते समय उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि हम बाढ़ के डर से विकास से मुंह नहीं मोड़ सकते। मानवजाति के उत्थान के लिए यह अपरिहार्य है। यह बात पूरे हिमालय परिक्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत तक के लिए मान्य है, लेकिन इस विकास की एक सीमा तय कर प्रकृति से छेड़छाड़ को रोकना होगा। यह काम सभी देशों को एक साथ करना होगा, क्योंकि एक देश के सतर्क हो जाने से संकट टलने वाला नहीं है।

प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हुए जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज हम किसी भी मौसम का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। बारिश हमारे लिए आसमानी आफत की तरह हो चुकी है। पहले यह पहाड़ों तक सीमित थी, पर अब पूरे देश में इसका व्यापक प्रभाव दिखता है। अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। अल नीनो के बाद ला नीना अपना असर दिखाएगा, जो शीतकालीन परिस्थितियों को और गंभीर करेगा। गर्मी का तो हमने असर देख ही लिया है। जिस मौसम को हम बसंत के रूप में जानते थे, वह भी अब बसंती नहीं रहा। प्रकृति के बदलते रुख ने हमारी सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है। अब इसके बाद भी अगर हमारी समझ में नहीं आता तो फिर हम यह मानकर चलें कि आने वाला समय और अधिक दुष्कर होने वाला है। इससे पहले जब पृथ्वी से जीवन खत्म हुआ था, तब कारण ज्वालामुखी या भूचाल जैसी घटनाएं थीं, लेकिन इस बार पृथ्वी को संकट में डालने का कारण स्वयं मनुष्य बन रहा है। वह प्रकृत की अनदेखी करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहंकार का आवरण

मैं और केवल मैं की भावना ही अहंकार है। जब मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तब उसके मानस पटल पर अहंकार की ग्रंथि जन्म लेती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे प्रभावित होकर मनुष्य स्वयं को सर्वोत्तम, सर्वज्ञ तथा सर्वोपरि मानने लगता है। वह अपने को ही संपूर्ण मानने लगता है। अपने समकक्ष वह अपने से योग्य और उत्कृष्ट व्यक्तियों को भी तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार एवं अस्वीकृति के कारण योग्य व्यक्तियों से दूर भागता है। यह अहंकार उसकी व्यक्तिगत उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। वह एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है।

अहंकार एक दुर्गुण तथा मनोरोग है। अहं की दलदल में धंसा मनुष्य सदैव असंतुष्ट, अशांत एवं तनाव ग्रस्त रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां जकड़ लेती हैं। अहंकार के इस आवरण में पोषित होने वाला मनुष्य सद्गुणों को ग्रहण करने से सदैव वंचित ही रहता है जिससे वह नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ पाता।

अहंकारी व्यक्ति सदैव दूसरों को हर क्षेत्र में अपने से न्यून समझता है, जिसका प्रभाव उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की दुनिया स्वयं से ही शुरू होती है और स्वयं पर ही खत्म हो जाती है। अहंकार का यह आवरण मनुष्य को निराशा तथा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। अहंकार से प्रभावित होकर वह नवीन ज्ञान और उन्नति तथा सृजनता के मार्ग को स्वयं ही बंद कर लेता है। अहंकार के तीव्र प्रवाह में भ्रमित होकर मनुष्य यह भूल जाता है कि इस असीमित एवं अपरिमित ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व शून्य के समान है। अहंकार का यह आवरण मनुष्य की विवेक शक्ति को भी नष्ट कर देता है जिससे मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

मानव सभ्यता का भविष्य है अंतरिक्ष

रंजना मिश्रा

हमारी उत्पत्ति, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना और ब्रह्मांड की संरचना जैसे सवालों के जवाब अंतरिक्ष में छिपे हैं

भारत के लिए 23 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चंद्रयान-3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की भी याद दिलाता है। यह भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का एक विशेष दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि उत्सुकता और लगन से हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अंतरिक्ष मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में समझ बढ़ाना और मानवता के लिए नए ज्ञान का सृजन करना है।

अंतरिक्ष अनुसंधान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और नए ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। हमारी उत्पत्ति, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना और ब्रह्मांड की संरचना जैसे बुनियादी सवालों के जवाब अंतरिक्ष में छिपे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान ने कई महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया है, जैसे कि सेटेलाइट टेक्नोलाजी, राकेट प्रौद्योगिकी, और कंप्यूटर टेक्नोलाजी। ये तकनीकें हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों, जैसे कि मोबाइल फोन, जीपीएस और इंटरनेट के लिए आधार हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश से नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष अनुसंधान हमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वैश्विक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, फसलों की निगरानी करने और आपदा राहत कार्यों में किया जाता है। भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्ती स्थापित करने की संभावना है। यह मानवता के लिए एक नया अध्याय होगा और पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।

भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसरो ने कई सफल मिशन लांच किए हैं। चंद्रयान, मंगलयान और हाल ही में सूर्ययान जैसे मिशन ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और भी अधिक रोमांचक होने वाला है। मंगल ग्रह पर मानव मिशन, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारी संभावनाएं हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान न केवल विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र है, बल्कि यह मानव सभ्यता का भविष्य भी है। इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम सभी को मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने और मानव सभ्यता के विकास में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

न्याय में देरी का सवाल

'सरकारों के साथ समाज भी सुधरे' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने बिल्कुल उचित लिखा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए प्रमुख रूप से वह मानसिकता जिम्मेदार है जिसमें लड़कियों एवं महिलाओं को कमतर और दीन-हीन मानने की परंपरा रही है। चाहे लड़कियों में कितनी ही काबिलियत क्यों न हो, तमाम परीक्षाओं में भले ही वे अव्वल स्थान लाती हों, इसके बावजूद पुरुषों के आगे उन्हें सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती ही है। हालांकि इस सबके पीछे जो मुख्य कारण जिम्मेदार है, वह है न्याय में अक्सर विलंब होना। इसके कारण असामाजिक तत्वों को नसीहत नहीं मिल पाती है। दूसरी बात भी गौर करने लायक है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले किया था कि सजा की खबर को भी प्रमुखता मिले। मगर सजाससमय मिले तब तो ऐसा हो। लिहाजा जरूरत है, दुष्कर्म की समस्त घटनाओं की प्रकृति पर शोध हो कि ऐसा करने वालों की शिक्षा-दीक्षा, आय वर्ग, संस्कृति क्या है? उनमें सुधार के प्रयास किस स्तर पर हो सकते हैं? शासन-प्रशासन का ऐसी घटनाओं से निपटने में तत्परता दिखाने में बाधा कहां है? ऐसे अधिकांश मामलों में शासन-प्रशासन का ही ढीला रवैया सामने आता है। फिर दुहाई कानून के शासन की दी जाती है। लिहाजा सुधार की अपेक्षा एकांगी नहीं हो सकती।

mukeshkr.m7542@gmail.com

निरर्थक आंदोलन

21 अगस्त को बहुत से विपक्षी दलों ने एससी-एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद किया। इसका अधिकांश राज्यों में बहुत कम असर रहा। यह भारत बंद उन राजनीतिक दलों द्वारा किया गया, जो संविधान और लोकतंत्र बचाने के बड़े-बड़े दावे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल राज्यों को सुझाव दिए थे, आदेश नहीं दिए थे। फिर भारत बंद का क्या औचित्य रह जाता है, वह भी हिंसात्मक और अराजक ढंग से। यह सस्ती वोटबैंक की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के केवल सुझावों को लेकर अराजक आंदोलन संविधान और लोकतंत्र बचाने का कार्य है। वह भी तब जब केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी थी कि एससी-एसटी आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं करेगी अर्थात सब पहले की तरह चलता रहेगा। यह भारत बंद बहुत ही खतरनाक शुरुआत है। भविष्य में जिस वर्ग या समुदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट का उनके हित साधने वाला निर्णय नहीं आएगा, तो वह अराजक आंदोलन पर उतर सकते हैं। आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमले किए, जबरन दुकानें बंद करवाईं, सड़कों पर टायर जलाए। संक्षेप में ऐसे निरर्थक आंदोलन देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं।

सीपी बंसल, दिल्ली

बेटियां हों सुरक्षित

हमारे समाज में स्त्री की छवियां अनेक हैं, लेकिन अक्सर हम एक स्त्री को पुरुष की ही नजर से देखते हैं। यह कार्य जाने अंजाने में होता है, लेकिन होता अवश्य है। एक पुरुष की अलग-अलग स्त्रियों के लिए अलग-अलग विचार, हमारे यहां स्त्रियों के साथ होने वाले अनेकों अपराधों का यह सामान्य सा कारण है। जिसमें बदलाव लाना हम नहीं चाहते, क्योंकि बदलाव तो स्त्री में और देश के कानूनों में होता है। समाज के सोच और पुरुष के लालन-पालन में नहीं। देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। 50 प्रतिशत दुष्कर्म के मामलों में आरोपी पहचान वाले होते हैं। महिलाएं न तो घर और न बाहर सुरक्षित हैं। यह स्थिति सिर्फ अपने देश में ही नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार होती हैं। किसी के घर में आग लगी है, यह कह कर मेरे घर के जल जाने की तकलीफ कम नहीं हो जाती है। मेरे घर, मेरे राज्य, मेरे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यह विचार मन में आने पर क्या एक स्त्री की कोख में पलने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना में आप एक लड़की होने की गुहार ईश्वर से कर पाएंगे?

राखी सरोज, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024

लेटरल इंट्री
वापसी की घोषणा

सरकार ने नौकरशाही में 'लेटरल इंट्री' की वापसी की घोषणा कर दी। सरकार ने सिविल सेवाओं में लेटरल इंट्री की पहल वापस लेने का निर्णय किया है। यह निर्णय उसके कुछ राजनीतिक सहयोगियों की आपत्तियों के कारण हुआ। विपक्षी दलों ने इसे एससी, एसटी व ओबीसी के अधिकारों का हनन कहा था। हालांकि, इस वापसी से सरकार की नौकरशाही में निजी क्षेत्र से नई प्रतिभा को प्रवेश दिलाने की इच्छा को थोड़ा धक्का लग सकता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में विशेष कौशल तथा दृष्टिकोण शामिल करना था। एक अवधारणा के रूप में 'लेटरल इंट्री' की शुरुआत सिविल सेवाओं में आवश्यक समकालीन प्रशासन तथा परंपरागत विशेषज्ञता के बीच खाई पाटने के लिए की गई थी। वित्त, तकनीक तथा सामाजिक विज्ञानों जैसे अनेक क्षेत्रों से पेशेवरों को वरिष्ठ स्तरों पर नौकरशाही में प्रवेश की अनुमति दे कर सरकार सार्वजनिक प्रशासन की प्रभावशीलता और क्षमता बढ़ाना चाहती थी। इस पहल को ऐसी व्यवस्था में नए विचारों और खोजों को प्रवेश कराने की इच्छा के रूप में देखा जा रहा था जिसकी आलोचना अक्सर सुस्त, जड़ तथा समकालीन यथार्थ से कटे रहने के कारण होती है। लेकिन इसे विपक्ष तथा कुछ भाजपा सहयोगियों द्वारा पसंद नहीं किया गया।

आलोचकों का तर्क है कि लेटरल इंट्री से भारतीय सिविल सेवाओं के मूल सिद्धान्तों को नुकसान पहुंच सकता है जिसमें ऐतिहासिक रूप से तटस्थता, निरंतरता तथा देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझना शामिल है। हालांकि, लेटरल इंट्री के माध्यम से भर्तियां कांग्रेस सरकारों में भी होती रही हैं और उनमें आरक्षण का भी

कोई प्राविधान नहीं था, पर संभवतः इस बार इनकी संख्या अधिक थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने 2005 में लेटरल इंट्री की सिफारिश की थी। इस संस्तुति के पहले भी प्रोफेसर व अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त सचिव बनाया गया था तथा बाद में 'आधार' अवधारणा के जनक नंदन नीलकेणी को नौकरशाही में स्थान मिला था। इसके साथ ही कांग्रेस सरकारों में लेटरल इंट्री के माध्यम से अनेक भर्तियां की गई थीं। कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री का कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि अब राहुल गांधी व विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' इसका विरोध कर रहा था। यह राजनीतिक व चुनावी लाभ के लिए सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के प्रयास के सिवा और कुछ नहीं है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया है कि कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री से भर्तियां मनमाने व अपारदर्शी ढंग से होती थीं, जबकि इस बार सरकार ने इसके लिए खुला विज्ञापन जारी किया था। भाजपा नेताओं ने यह भी याद दिलाया है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति नौकरशाही के निर्णय निर्देशित करती थी, लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठे। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार ने आरक्षित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना भी शामिल है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 'लेटरल इंट्री' पर निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वापस लिया गया है जो इसमें एससी, एसटी व ओबीसी को समुचित आरक्षण देना चाहते हैं। इस प्रकार भाजपा ने सही समय पर सही कदम उठा कर विपक्ष के हाथों से एक हथियार छीन लिया है जिसके बहाने वह देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने का सपना देख रही थी।

कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर में चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक प्रकार से यह चुनाव जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में विधानसभा चुनाव 90 विधायक चुनने के लिए होंगे। ये चुनाव अगस्त, 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा उसे दो संघशासित क्षेत्रों में बांटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव कराने में विलंब को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल में सर्वोच्च न्यायालय का दिशानिर्देश महत्वपूर्ण रहा जिसके चलते अब राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश ने चुनाव का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का बिंदु रहा है। भारत और पाकिस्तान, दोनों पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते रहे हैं, हालांकि दोनों देशों का इसके एक-एक हिस्से पर शासन रहा है। पाकिस्तान ने लंबे समय से कश्मीर मुद्दे के 'अंतरराष्ट्रीयकरण' का प्रयास किया है। कश्मीर मुद्दा लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उठाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाया है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने पर भी विवाद रहा है। राज्य को विभाजित करने के निर्णय से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा, अपराध संहिता तथा संवैधानिक प्रक्रियायें समाप्त हो गई। इसके कारण कश्मीरियों को सरकारी नौकरियों के अवसर भी घटे क्योंकि अब कश्मीर के बाहर के लोग भी इनमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने के बाद चुनौतियों के बावजूद राज्य में अनेक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं, भले ही कुछ लोगों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहलों ने राज्य में विकास को गति दी है। जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों द्वारा निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ी है जिससे जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इससे राज्य के निवासियों में आशा की किरण पैदा हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, राज्य में आतंकवादी व अलगाववादी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ने के कारण हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है।

सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या जहां 2019 में 80 थी, वह 2023 में घट कर 33 रह गई। इसी प्रकार सिविलियन मौतों की संख्या भी 2019 में 44 से घट कर 2023 में 12 रह गई। राज्य में इसके पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य में बदलते परिवेश के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ा और इस सकारात्मक परिघटना ने विधानसभा चुनाव का रास्ता खोल दिया। कश्मीर में हालिया संसदीय चुनाव में 58.46 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो 2019 में आम चुनाव से 30 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य के दो भागों में विभाजन के बाद 'परिसीमन' भी पूरा किया। 2022 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 87 से बढ़ कर 114 हो गई है, जिसमें पाक-अधिकृत कश्मीर-पीओके की 24 सीटें भी शामिल हैं।

सीटों में इस वृद्धि के कारण शक्ति संतुलन बदला है और यह आगामी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा का दावा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा कश्मीर में इसके बाद लागू की गई उसकी नीतियों के कारण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हालिया लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विजय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस-एनसी व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-पीडीपी भी पुनर्जीवित हुई हैं। इस चुनाव में उनकी सदस्य संख्या बढ़ी है तथा वे लंबे समय से लंबित मुद्दों को सामने लाने में सफल हुई हैं। हालांकि, कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और एनसी अपने द्वारा लड़ी तीन सीटों में से दो पर विजय प्राप्त करने में सफल रही, पर तीसरी सीट पर भी उसने मजबूत चुनौती पेश की थी।

क्षेत्र में आतंकवाद के इतिहास तथा चुनावों में धांधली के आरोपों के बावजूद हाल में हुए चुनाव मोटेतौर से स्वच्छ एव निष्पक्ष माने जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव केन्द्र सरकार के प्रयासों की परीक्षा होगी जो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संघ के साथ जोड़ना चाहती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अनुच्छेद 370 की वापसी के साथ शुरू हुई है जो इस राज्य को विशेष दर्जा देती थी। यह निर्वाचन आयोग की भी परीक्षा होगी कि वह बिना किसी हिंसा के चुनाव कराने में सफल हो। राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिनमें अभियान की रणनीतियां बनाना, गठबंधन के प्रयास तथा उम्मीदवारों का चयन शामिल हैं। चुनाव की योजना बनाने के लिए पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कान्फ्रेंस अपनी बैठकें कर चुकी हैं।

राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसमें अभियान की रणनीति बनाने के साथ ही संभावित गठबंधनों पर गौर करना व विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना शामिल हैं। पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तथा नेशनल कान्फ्रेस लगातार पार्टी के स्तर पर बैठकें कर चुनाव की रणनीति और योजना बना रहीं हैं। यदि विधानसभा चुनाव निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार होते हैं तो घाटी में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में ध्रुवीकरण तथा अलगाववादी विमर्श भी देखने को मिला था। आशंका है कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही इन परिघटनाओं को बल मिल सकता है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी और अन्य ने चुनावी बयानबाजी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की चुनाव कराने की घोषणा का समर्थन करने वाली अन्य पार्टियों ने भी चुनावी प्रचार शुरू करने की पहल कर दी है। इनमें कांग्रेस, भाजपा, माकपा तथा पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी-डीपीएपी भी शामिल हैं।

2014 में जम्मू कश्मीर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री घोषित करने के पहले राज्य में 49 दिन तक राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा था। 2018 में भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का निर्णय किया जिसके चलते राज्य में एक बार फिर राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा। इसके बाद नवंबर, 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई और दिसंबर, 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद से राज्य में राज्यपाल शासन चल रहा है। सरकार को यह तय करना है कि वह कश्मीर घाटी में अलगाववाद की कुछ घटनाओं से निपटने के लिए हस्तक्षेप करना चाहती है अथवा वह चुनाव के पहले राज्य में कोई पुनर्गठन योजना लागू करेगी। हालिया संसदीय चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। इसके अंतर्गत नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि कांग्रेस ने जम्मू और उधमपुर में चुनाव लड़ा।

'इंडिया' गठबंधन की साझीदार होने के बावजूद पीडीपी को इस गठजोड़ में शमिल नहीं किया गया और उसने नेशनल कान्फ्रेंस के खिलाफ कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस और एनसी साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के अनुसार, पीडीपी से गठबंधन कठिन होगा क्योंकि संसदीय चुनाव में वे एक-दूसरे के खिलाफ थे। यदि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहें तो उनको एकजुट होकर 'इंडिया' से गठजोड़ करना चाहिए। कश्मीर विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे एक दशक बाद राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

> “ डिजिटल लर्निंग के साथ-साथ शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का यह बजट आवंटन एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में मदद करेगा। ”

रीतू श्रीवास्तव
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024-25 के बजट को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, अनुसंधान और नवाचार को पहले की तरह प्राथमिकता देते हुए, सविकसित भारत के लिए बजट भारत की साख को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उठाए गए ये व्यापक और ठोस उपाय हैं जो सभी हितधारकों-छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के लिए फायदेमंद होंगे। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट आवंटन 30 प्रतिशत बढ़ाकर 1.48 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें स्कूलों में 265 मिलियन छात्र, उच्च शिक्षा में 43 मिलियन और कौशल संस्थानों में 10 मिलियन से अधिक शिक्षार्थी नामांकित हैं। 2024-25 के लिए 73,498 करोड़ रुपये का बजट आवंटन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए अब तक का सबसे अधिक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे स्वायत्त निकायों को भी अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है। समग्र शिक्षा, पोषण और पीएम-श्री जैसी प्रमुख योजनाओं को 3,250 करोड़ रुपये मिले हैं। बजट में कौशल और प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं के लिए कौशल विकास और इंटर्नशिप के अवसर, और पूरे क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। सरकार ने 25000 छात्रों को सालाना 1.5 लाख से 7.5 लाख तक की 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की है और उच्च घरेलू शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर साल एक

लाख छात्रों को 3% की वार्षिक ब्याज छूट के साथ 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया है। इस कदम से निश्चित रूप से घरेलू संस्थानों में नामांकन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही छात्रों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कौशल विकास क्षेत्र के लिए कई पहलों की रूपरेखा भी बताई।

इनमें उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन शामिल है। सरकार द्वारा 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर एक स्वागत योग्य कदम है, इससे युवाओं को जुड़ाव मिलेगा और रोजगार और व्यावहारिक कौशल में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) योजना में 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में कुल 3525.15 करोड़ रुपये (7.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएससी को भारी आवंटन मिला है, जो पिछले बजट की तुलना में काफी अधिक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-लर्निंग, शोध एवं नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र और कुछ विशिष्ट संस्थानों जैसे क्षेत्रों को अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। डिजिटल ई-लर्निंग के तहत सरकार वर्चुअल लर्निंग की क्षमता का दोहन करने और पोर्टेबिलिटी और लचीले अध्ययन विकल्पों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जोड़ने की योजना बना रही है।

'आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन' योजना में 2024-25 में 480 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह 2023-24 के आवंटन से 80 करोड़ रुपये अधिक है। शोध एवं नवाचार के लिए बढ़ा हुआ बजट विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित है। स्कूल स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नए शैक्षणिक ढांचे की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण खंड को इसका उचित हिस्सा मिला है। 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना' योजना को बजट में 255 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) जिसे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के नाम से जाना जाता था, के लिए बजट 1814.94 करोड़ रुपये रखा गया है। उत्कृष्ट संस्थानों के लिए 1800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 'बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार ईएपी (मेरिटे)' योजना में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह पिछले साल के बजट से 100% अधिक है।

एनईपी 2020 का कहना है कि नीति का उद्देश्य भारत में 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने शिक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी पैकेज तैयार किया है ताकि यह विकासोन्मुख, समावेशी और प्रगतिशील हो। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका कार्यान्वयन है। शिक्षा मंत्री द्वारा बताए गए अनुसार शिक्षा के लिए बजट की विशेषताएँ 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

आप की बात

हिंदुओं पर अत्याचार

इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के वजूद में आ जाने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। दास ने दावा किया कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर हर दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश में काम कर रहे सभी 25 लाख हिंदुओं को उनकी नौकरियों से हटाना है। यह सब कुछ नई सरकार के सपोर्ट और एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। यह सब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत तथा उनके गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफी मांगने के बाद हो रहा है। स्पष्ट है कि यह बांग्लादेश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और अंततः देश छोड़ कर जाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से राजनयिक स्तर पर सीधे बात कर इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का आग्रह करना चाहिए। इसके लिए भारत को आवश्यकता होने पर बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव डालने, भारत में उसकी परिसंपत्तियां जब्त करने, उसके साथ व्यापार व अन्य संबंध तोड़ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में व अन्य मंचों पर मुद्दा उठाने पर विचार करना पड़ सकता है।

-**सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

आरक्षणः जटिल समस्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उप-विभाजन को लेकर दिए फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान एक प्रकार से अपनों का अपनों के उत्थान के विरुद्ध अभियान है। आखिर भारत बंद का आह्वान करने वाली ये कैसी लीडरशिप है जो कहती है कि गरीब, पिछड़े और अक्षम वहीं रहें और जो ऊपर उठ गए हैं या सक्षम बन गए हैं उन्हें ही पीढ़ी दर पीढ़ी शीर्ष पर चढ़ाते जाएं। ऐसे में कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भला क्या करे? बरसों से चल रही स्वार्थ की राजनीति ने आरक्षण नीति को इतना उलझाकर रख दिया है कि उसे सुधारना तो दूर उसमें गरीब व अक्षम लोगों के हित में फैसले लेना भी असंभव सा हो गया है। ऐसे में राजनेता, कानूनविद और समाजसेवी तीनों को मिलकर आरक्षण जैसी जटिल समस्या का दीर्घकालीन समाधान ढूंढें ताकि हर छोटी-छोटी बात पर लोग सड़क पर न आने पाएं। बाबा साहब की फोटो लेकर आंदोलन के नाम पर हिंसक उपद्रव करने वालों को स्वयं अंबेडकर के शब्द याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत में संविधान लागू होने के बाद अब आंदोलन, धरना, हड़ताल, आदि असंवैधानिक गतिविधियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्या आरक्षण समर्थक समाज में संवाद का कोई रास्ता खोजेंगे?

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें एससी-एसटी, यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्ग बना सकती हैं। इसके विरोध में समूचा विपक्ष खड़ा हो गया। सरकार ने भी राजनीतिक मजबूरियों के कारण इसे परोक्ष रूप से यथावत रखने का आश्वासन दे दिया है। गंभीरता से गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई विसंगति नहीं है और यह संविधान की भावना के अनुकूल सर्वाधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मगर वोटों की राजनीति और भीड़तंत्र ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए भारत बंद का आह्वान कर दिया। क्या आजादी के बाद से आरक्षण का लाभ ले चुकी एससी-एसटी की क्रीमी लेयर यह नहीं चाहती कि उनके अन्य गरीब बंधु-बांधवों को भी उन्हीं की तरह आगे आने का मौका मिले? ऐसे में आरक्षण की सीमा बढ़ाने व जातीय गणना कराने की मांग करने वाले नेताओं की नीयत पर भी सवाल उठता है कि क्या वे देश में एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा कर अपने निहित राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए देश को कमजोर करना चाहते हैं? यह स्थिति निश्चित रूप से चिन्ताजनक है।

- **विभूति बुपक्या**, खाचरोद

एक राष्ट्र एक चुनाव

प्रधानमंत्री मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे से विपक्षी दलों के नेता भी सहमत होने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे का समर्थन करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है और इस पर अपनी सहमति दी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के लिए एक राष्ट्र चुनाव का नारा लागू करने की बात दोहराते हुए सभी दलों से इस पर सहमति देने की बात कही थी। हालांकि, शरद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव घोषणा को देखते हुए प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाया। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सभी राजनीतिक दलों की सहमति और अनेक संविधान संशोधनों के बाद लागू हो सकती है। अतः शरद पवार के व्यंग्य या मजाक का कोई तुक नहीं है। देश की वर्तमान विभाजित राजनीति तथा भाजपा-विरोधी दलों के अधिकांश नेताओं की येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने की लालसा के कारण फिलहाल ऐसी अवधारणा के फलीभूत होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अच्छे विचारों को बार-बार दुहराना भी लाभदायक है।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 161

मुद्रास्फीति प्रबंधन

इस समय लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर इसके असर को लेकर एक दिलचस्प और जीवंत बहस चल रही है। हालांकि यह विषय नया नहीं है और मुद्रास्फीति को लक्षित करने की लचीली व्यवस्था को अपनाए जाने के समय से ही यह बहस का विषय रही है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में की गई टिप्पणियों ने एक तरह से इसे नए सिरे से उभार दिया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारत में मुद्रास्फीति को लक्षित करने के ढांचे में इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि मुद्रास्फीति को बिना खाद्य कीमतों के लक्ष्य बनाया जाए। वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि उच्च खाद्य कीमतें अक्सर आपूर्ति क्षेत्र की दिक्कतों की वजह से होती हैं, न कि मांग क्षेत्र की। अल्पावधि को ध्यान में रखने वाले नीतिगत उपाय अतिरिक्त समेकित मांग से उत्पन्न होने वाले मूल्य दबाव को सीमित करने के लिए होते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने पिछले मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्यों और बाद में सार्वजनिक चर्चाओं में केंद्रीय बैंक की स्थिति स्पष्ट कर दी। पहली बात, रिजर्व बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के चार फीसदी का लक्ष्य दिया गया है और खाद्य कीमतें इसमें 46 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं इसलिए उनकी अनदेखी संभव नहीं। दूसरा ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति दर आम पारिवारिक मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को प्रभावित करती है जिसका वास्तविक मुद्रास्फीति संबंधी नतीजों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक के ताजा मासिक बुलेटिन में एक विश्लेषणात्मक अध्याय भी इस विषय पर है। डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्र एवं अन्य के शोध आलेख में हालांकि केंद्रीय बैंक का आधिकारिक नजरिया नहीं है लेकिन यह बताता है कि आखिर क्यों केंद्रीय बैंक समग्र मुद्रास्फीति प्रबंधन में खाद्य पदार्थों की अनदेखी नहीं कर सकता है।

जून 2020 से जून 2024 के बीच औसत खाद्य मुद्रास्फीति इससे पहले के चार सालों के 2.9 फीसदी के स्तर से काफी अधिक थी। इस इजाफे को मोटे तौर पर एक ही समय में लगे कई झटकों, जलवायु संबंधी घटनाओं और मॉनसून के वितरण से जोड़कर देखा गया। इसके परिणामस्वरूप विचारार्थ अवधि में से करीब 57 फीसदी महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर छह फीसदी से अधिक रही। सब्जियों की कीमतों में इजाफे को आमतौर पर अस्थायी माना जाता है। बहरहाल, करीब 45 फीसदी महीनों के दौरान इनमें दो अंकों की वृद्धि देखी गई। अनाज तथा अन्य उत्पादों में 53 फीसदी महीनों के दौरान छह फीसदी से अधिक महंगाई देखी गई। स्पष्ट है कि खाद्य मुद्रास्फीति बीते कुछ सालों से गंभीर चुनौती बनी हुई है। यह बात भी रेखांकित करने योग्य है कि निर्यात प्रतिबंध समेत सरकार के कई उपायों के बीच निरंतर ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति देखने को मिली।

आलेख में यह भी दर्शाया गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति का मुद्रास्फीति के अनुमानों पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव होता है जबकि मौद्रिक नीति का नकारात्मक। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति अनुमानों में अनिश्चितता आ सकती है जिससे समग्र मुद्रास्फीति प्रबंधन जटिल हो सकता है। यह भी पाया गया कि खाद्य मुद्रास्फीति विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कच्चे माल की लागत तथा उत्पादन पर असर डालती है। यह भी कहा गया कि खाद्य कीमतों ने बीते कुछ सालों में कोर मुद्रास्फीति दर पर ऊपरी दबाव कायम किया है जिसे मौद्रिक नीति ने दूर किया। ऐसे में रिजर्व बैंक समग्र मुद्रास्फीति निष्कर्षों में खाद्य कीमतों के दबाव को नकार नहीं सकता। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वर्ष में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर 4.5 फीसदी रहेगी। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसके 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति की दर आने वाले महीनों में कमी आएगी। बहरहाल, रिजर्व बैंक के लिए बेहतर यही है कि वह सतर्क रहे।

चीन के निवेश से भारत को नहीं होगा लाभ

विनिर्माण क्षेत्र में चीन को निवेश करने दिया जाता है तो कारोबार की बढ़ी लागत और भूराजनीतिक अवसरों को सीमित करने वाले कारक हमें उस निवेश का लाभ नहीं मिलने देंगे। बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

हाल में आई आर्थिक समीक्षा में सुझाव है कि विनिर्माण को गति देने, निर्यात बढ़ाने, चीन से आयात कम करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत को चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का स्वागत करना चाहिए। मान लीजिए कि भारत ऐसा निवेश आने देता है तो क्या विनिर्माण, निर्यात, आयात और मूल्य श्रृंखला को वास्तव में लाभ होगा?

विनिर्माण: पहले काल्पनिक किरदार श्रीमान यांग के सहारे विनिर्माण में चीन के निवेश का असर समझते हैं। मान लेते हैं कि यांग सोलर मॉड्यूल बनाने वाली एक बड़ी चीनी कंपनी के सीईओ हैं।

यांग भारत में सोलर मॉड्यूल बनाना चाहते हैं और उत्पादन के हर चरण पर चीन और भारत में आ रही लागत की तुलना करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया क्वार्ट्ज खनिज हासिल करने और उसे प्रोसेस करके अत्यधिक शुद्धता वाली पॉलिसिलिकन सिल्लियां बनाने से शुरू होती है। सिल्लियों को बाद में पॉलिसिलिकन वेफर्स में बदला जाता है। वेफर्स को रासायनिक प्रक्रिया और लेसर से गुजारा जाता है और चांदी का इस्तेमाल कर सोलर सेल बनाई जाती हैं। इन्हीं सोलर सेल को असेंबल कर अंत में सोलर मॉड्यूल बना दिया जाता है।

यांग का विश्लेषण दर्शाता है कि भारत में क्वार्ट्ज खनिज जैसे कच्चे माल से उत्पादन करना चीन में उत्पादन की तुलना में करीब 40 फीसदी महंगा पड़ेगा। आयातित पॉलिसिलिकन वेफर्स का उपयोग करने पर यह अंतर घटकर 25 फीसदी रह जाता है और चीन से आयातित सोलर सेल इस्तेमाल करने पर केवल 3 फीसदी हो जाता है।

भारत में दिलचस्पी के बावजूद यांग देखते हैं कि कच्चे माल की मदद से सोलर मॉड्यूल तैयार करना महंगा पड़ता है। अगर भारत रियायती कीमत पर जमीन देने और पूंजी मुहैया कराने जैसी मदद करे तो वह वेफर वाले चरण से शुरू करना चाहेंगे। अन्यथा वह दूसरी कंपनियों की तरह सोलर सेल आयात कर सोलर मॉड्यूल बना सकते हैं। यह भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र जैसा ही है जो आयातित सब असेंबली पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बैटरी उद्योग भी ऐसा ही है जो आयातित लीथियम सेल पर निर्भर है। दोनों मामलों में ज्यादातर विनिर्माण विदेश में हो रहा है और 85 फीसदी से अधिक घटक आयात किए जा रहे हैं।

भारत और चीन के बीच लागत में भारी अंतर इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहां कच्चे माल की उत्पादन लागत अधिक है और चीन अपनी कंपनियों को सब्सिडी देता है। उदाहरण के लिए भारत में कारोबार के लिए पूंजी की लागत 9-10 फीसदी है जबकि चीन में 4-5 फीसदी। औद्योगिक बिजली भारत में 0.08 से 0.10 डॉलर प्रति किलोवॉट पड़ती है जबकि चीन में यह 0.06 से 0.08 डॉलर प्रति किलोवॉट रहती है।

भारत हमेशा से कपड़ा और वस्त्र, चमड़ा तथा जूते-चप्पल में मजबूत रहा है और इनमें आम तौर पर स्थानीय कच्चे माल का ही इस्तेमाल किया जाता है। किंतु बढ़ती उत्पादन लागत और पेचीदा नियमों के कारण हम बांग्लादेश और वियतनाम से पिछड़ रहे हैं। भारत में कच्चे माल से कई चीजों का निर्माण भी काम का नहीं रहा क्योंकि चीन की सरकार वहां होने वाले उत्पादन को बहुत मदद देती है। उदाहरण के लिए चीन की सोलर कंपनियों को निःशुल्क जमीन, बिजली, बिना ब्याज का ऋण और उत्पादन लागत के 35 से 65 फीसदी के बराबर सब्सिडी मिलती है। भारत में कंपनियों को वैसी मदद नहीं मिलती, इसलिए यहां उत्पादन महंगा पड़ता है। उत्पादन लागत में कमी किए बगैर और नियमों को सहज किए बगैर चीन समेत विदेशी निवेश से होने वाला निर्माण सतही होगा जो आयात पर निर्भर होगा।

निर्यात: 2024 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया की रणनीति पर चलते हुए चीन का एफडीआई विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करेगा और अमेरिका तथा यूरोप को निर्यात बढ़ाएगा। परंतु यह आसान नहीं होगा।

इस वर्ष जून में अमेरिका ने कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में बनने वाले चीनी कंपनियों के सोलर पैनल पर 250 फीसदी तक आयात शुल्क लगा दिया। मार्च में डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह चीन के वाहन उद्योग को निशाना बनाएंगे जो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका को कार निर्यात करना चाहता है। भारत के लिए स्थिति अलग क्यों होगी?

आयात: विचार यह है कि चीन अपने उत्पाद भारत में बनाता है तो चीन से हमारा आयात कम हो जाएगा। यह मुश्किल नजर आता है क्योंकि भारत का 30 फीसदी औद्योगिक आयात चीन से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मशीनरी, रसायन, प्लास्टिक और वाहन शामिल हैं। मोबाइल और स्मार्टफोन जैसे क्षेत्रों में देश में उत्पादन बढ़ाने के बाद भी चीन से भारत का आयात बढ़ा है। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बैटरी के मामले में निर्भरता अधिक है। चीन जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन शुरू करेगा, उनमें आयात घट सकता है मगर दूसरे हजारों उत्पादों का आयात बढ़ सकता है। चीन की कंपनियों द्वारा भारत में बनाए जा रहे सामान में भी आयात बढ़ सकता है क्योंकि लागत कम रखने के लिए ये कंपनियां कच्चा माल अपने देश से मंगाना पसंद करेंगी।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला: आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते होने और एक दशक से भी अधिक समय से पूरे क्षेत्र में 90 फीसदी से अधिक औद्योगिक उत्पादों के व्यापार पर शुल्क शून्य करने के बाद भी भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अहम हिस्सा नहीं बन पाया। इसमें सुधार के लिए भारत को कारोबार की लागत कम करनी होगी और बंदरगाहों पर तथा सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी तेज करनी होगी।

पड़ोसियों के अनुभव: कई आसियान देशों का चीन से आयात बढ़ रहा है और अपने यहां चीनी कंपनियों की मौजूदगी के प्रतिकूल असर भी उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए जब चीन की ईवी कंपनियों ने थाईलैंड में उत्पादन आरंभ किया तो स्थानीय वाहन कलपुर्जों की मांग 40 फीसदी तक कम हो गई और वहां के कई पुर्जा निर्माताओं को काम समेटना पड़ा। भारत में भी हालात इससे अलग नहीं होंगे क्योंकि हमारी ईवी नीति भी वैसी ही है।

भूराजनीतिक रणनीति में बदलाव: हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे और अमेरिका तथा अन्य साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के कार्यक्रम में भारत की हिस्सेदारी का मकसद चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना है। चीन से एफडीआई पर जोर चीन के बाहर विनिर्माण ठिकाने बनाने के इन प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा।

एफडीआई विनिर्माण में मददगार नहीं साबित हुआ है। वित्त वर्ष 24 में केवल 41 अरब डॉलर का नया एफडीआई आया, दो सकल घरेलू उत्पाद के 1 फीसदी से भी कम रहा। मार्च 2000 से 20 फीसदी से भी कम एफडीआई विनिर्माण में गया और ज्यादातर असेंबलिंग के काम में चला गया। इससे पता चलता है कि लागत अधिक होने और नियम-कायदे पेचीदा होने की वजह से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश कभी पूरी रफ्तार से नहीं आया। सुरक्षा के पहलू की अनदेखी कर चीन से एफडीआई आने भी दें तो हालात नहीं बदलेंगे, जबकि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में सबसे अहम पैमाना सुरक्षा ही होती है।

हमें पहले चरण से लेकर बंदरगाह पर सामान की रवानगी तक हर चरण पर कारोबारी लागत कम करनी होगी और बुनियादी ढांचे तथा कारोबारी सुगमता में सुधार करना होगा।

इन बदलावों के बिना विदेशी निवेश सीमित रहेगा और उससे गहन विनिर्माण के बजाय केवल असेंबलिंग का काम होगा, जिससे अहम चीजों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जो निवेश आएगा वह चीनी वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत में चीनी ब्रांडों की पैठ बढ़ाएगा।

सबसे बढ़कर भारत को चीन के संबंध में स्पष्ट और स्थिर नीति की आवश्यकता है, जो उसके साथ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार के मसलों पर मध्यम से लंबी अवधि की नीति तैयार करे।

(लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं)

प्रसारण विधेयक पर दोबारा विचार अनिवार्य

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024 को फिलहाल रोकने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। हम जानते हैं कि टेलीविजन प्रसारण पिछले कुछ वर्षों से धीरे-धीरे कम हो रहा है। वर्ष 2019 के 20 करोड़ घरों (96 करोड़ लोगों) से अब यह संख्या घटकर 17.6 करोड़ घरों (84.5 करोड़ लोगों) तक सिमट गई है। फिक्की-ईवाई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबार को विज्ञापन से होने वाली कमाई 69,600 करोड़ रुपये रह गई, जो 2019 के 78,700 करोड़ रुपये से कम है।

टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में पिछले कुछ वर्ष विलय और अधिग्रहण के रहे हैं। डिज्नी ने स्टार इंडिया का अधिग्रहण किया और रिलायंस ने वायकॉम 18 में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी तथा बाद में इसका विलय डिज्नी में कर दिया। टेलीविजन जैसे-जैसे परिपक्व होगा वह 10 से 12.5 करोड़ घरों (48 से 60 करोड़ दर्शकों) में सिमटकर रह जाएगा। इनमें आधे से ज्यादा सरकारी डीडी फ्रीडिश वाले होंगे। ध्यान रहे कि ये बातें सामान्य टेलीविजन प्रसारण की हो रही हैं। हालांकि उसके अलावा भी मुफ्त टेलीविजन, स्मार्ट टीवी और स्ट्रीमिंग में काफी वृद्धि हो रही है।

भारतीय टेलीविजन की शुरुआत 1980-90 के दशक में बुनियाद, अंताक्षरी, बनेगी अपनी बात, सांस जैसे शानदार शो से हुई थी। फिर भी रेडियो के बाद सबसे बड़ा मीडिया होने के बावजूद न तो यह रेडियो जैसी रचनात्मक ऊंचाई हासिल कर सका और न ही उसकी तरह 1 अरब लोगों तक पहुंच सका। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है मगर ब्राजील जैसे समान बाजारों से यह राजस्व, प्रति इकाई कमाई और मुनाफे में छोटा ही रहा।

इसके कई कारण है और इनमें से सबसे बड़ा कारण कीमतों का नियमन है। यह 2004 में तब शुरू हुआ, जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रसारण नियामक नियुक्त किया गया। कीमतों, रेटिंग और कारोबारियों एवं प्रसारकों के बीच समझौतों तक को नियंत्रित करने की इस अथक कोशिश के कारण ही देश के टेलीविजन उद्योग को उसका एचबीओ, सोप्रानोस या गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं मिल पाया। टेलीविजन पर स्टार वन जैसी अलग और प्रीमियम कार्यक्रम पेश करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं।

हमारे देश में ज्यादातर टीवी चैनल एक ही तरह के धारावाहिक बनाते हैं, जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा दर्शक जुटाना और विज्ञापन हासिल करना है। वर्ष 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। वर्ष 2016 में स्ट्रीमिंग सेवाओं के आने और 2018 में जोर पकड़ने के बाद भी ट्राई बताता रहा कि टीवी चैनलों को अपनी सेवाओं की कीमत कितनी रखनी है। यह सब उस बाजार में हो रहा है, जहां वीडियो एक दूसरे से होड़ कर रही तीन तकनीकों (केबल, सैटेलाइट, इंटरनेट) के जरिये तमाम उपकरणों (टीवी, फोन, लैपटॉप) पर देखा जा सकता है और ऑनलाइन वीडियो मुफ्त से लेकर हाइब्रिड तथा प्रीमियम तक कीमतों में उपलब्ध हैं।

कल्पना कीजिए कि टीवी चैनलों पर लागू सख्त नियम ओटीटी, सोशल मीडिया और ऑनलाइन खबरों पर भी लगा दिए जाएं। नए टीवी कानून को इसी के बरअक्स देखा जाना चाहिए। काफी समय से केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम, 1995 ही टीवी चैनलों से जुड़े नियम तय करता था, जिसमें नीतियां और उपग्रह से प्रसारण, अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग, इक्विटी सीमा, विदेशी निवेश आदि से जुड़े दिशानिर्देश शामिल हैं।

आखिरी बड़ा बदलाव 2011 में हुआ, जब डिजिटलीकरण के लिए केबल कानून में संशोधन किया गया। इसलिए वीडियो देखने के नए तरीकों के हिसाब से कानून बनना चाहिए।

प्रसारण विधेयक का पहला मसौदा नवंबर 2023 में आया। इस पर प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस साल जुलाई में मंत्रालय ने इस विधेयक के दूसरे मसौदे पर सुझाव मांगे। इस पर होहल्ला मच गया। मंत्रालय ने इस हफ्ते ऐलान किया कि 15 अक्टूबर तक लोगों से एक बार फिर परामर्श किया जाएगा।

इस कानून में तीन बड़ी समस्याएं हैं। पहली, सरकार कोशिश कर रही है कि ओटीटी जैसे ऑनलाइन वीडियो को भी टीवी चैनलों के कायदों में बांधा जाए। लेकिन वकील, मीडिया कंपनियों और दूसरे लोगों की दलील है कि दोनों अलग-अलग हैं। टीवी पर हम तय समय पर ही शो देख सकते हैं, लेकिन ओटीटी पर जब चाहें शो देखे जा सकते हैं। इंगलैंड, सिंगापुर और जर्मनी जैसे कई विकसित देशों में ओटीटी को प्रसारण की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। दोनों के लिए कायदे अलग-अलग हैं। डिजिटलीकरण में बहुत आगे जा चुके दक्षिण कोरिया में तो ओटीटी दूरसंचार कानून के दायरे में आते हैं।

दूसरी बात, यह कानून थोड़ा तानाशाही वाला है। इसमें सजा और माफी पर ज्यादा जोर दिया गया है मगर यह नहीं बताया गया है कि असल में विधेयक चाहता क्या है। पहली बार पढ़ने पर ही समझ आ जाता है कि सरकार ऑनलाइन देखी और पढ़ी जाने वाली हर सामग्री पर पूरा नियंत्रण चाहती है। इंगलैंड में उद्योग की रकम से चलने वाली संस्था ऑफकॉम अच्छा काम कर रही है। वहां एक नियामक ने एक बार मुझसे कहा किसी भी नए नियम या नीति या दिशानिर्देश पर विचार करते समय यह जरूर देखा जाता है कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान। लेकिन भारत में इस नए कानून के बारे में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

तीसरी बात, पुराना केबल अधिनियम समझने में आसान था, लेकिन नए कानून को समझने में घंटों लग गए। ऑनलाइन वीडियो ने हमें तरह-तरह के कार्यक्रम देखने का मौका दिया है और भारत के रचनात्मक मानस की कल्पना को भी इससे उड़ान मिल गई है। यही वजह है कि हम एमी पुरस्कार जीतने वाले 'दिल्ली क्राइम' जैसे शो और 'द फैमिली मैन', 'पाताल लोक' या 'रॉकेट बॉयज' जैसे बेहतरीन शो देख पा रहे हैं। खबरों में ऐसे लोगों की आवाज को जगह मिली है, जो मुख्यधारा की खबरों से पहले गायब रहते थे। यूट्यूब, रील्स, व्हाट्सऐप और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों ने सभी को सामग्री तैयार करने और साझा करने का मौका दिया है।

ऐसे में वीडियो देखने के नए तरीकों को पुराने जमाने के और अदूरदर्शी नियम में बांधना गलत है क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर पानी फिर सकता है। इससे विविधता कम होगी और तेजी से बढ़ रहे कारोबार को नुकसान पहुंचेगा।

मीडिया पार्टनर्स एशिया के मुताबिक ऑनलाइन वीडियो ने विज्ञापन और भुगतान सेवाओं से वर्ष 2023 में लगभग 30,000 करोड़ रुपये कमाए। वर्ष 2028 तक यह आंकड़ा बढ़कर 57,400 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। वृद्धि की यह उम्मीद कीमत या दूसरे नियंत्रणों के बगैर स्वतंत्र बाजार से लगाई गई है क्योंकि नियंत्रण या पाबंदी विकल्पों पर चोट कर सकते हैं और कारोबारी सुगमता भी कम कर सकते हैं। किंतु नया कानून मौजूदा स्वरूप में पारित हुआ तो ये दोनों पाबंदियां आ जाएंगी।

उद्योग एक बार फिर प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहा है और मंत्रालय को ऐसे में खुद से पूछना चाहिए कि क्या वह ऑनलाइन वीडियो की गति भी टीवी जैसी ही करना चाहता है। अगर नहीं तो इस कानून पर फिर विचार करने की जरूरत है।

आपका पक्ष

अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम

इसरो ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलता उतारकर देश का मान बढ़ाया था। इस दिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस जगह को शिवशक्ति का नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने नए सिरे से काम किया और चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा। इसके बाद इसरो ने 2 सितंबर, 2023 को पहले सूर्ययान आदित्य-एल1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और यह भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण राकेट पीएस-एलवी-सी57 के साथ अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था। उचित नेतृत्व और मेहनत-लगन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। हमारे देश में हर क्षेत्र, चाहे वह विज्ञान का हो या चिकित्सा का अनमोल हीरे हैं, लेकिन इनमें से बहुत तो अपनी

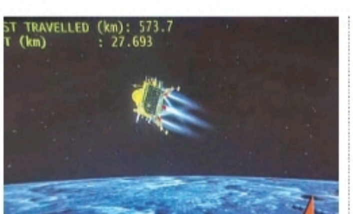

वर्ष 2023 में चंद्रयान की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है

खराब आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे होनहारों के सपने भी टूट जाते हैं। सरकार को इसरो की शानदार सफलता पर खुशी मनाने के साथ इस पर गंभीर होना चाहिए कि भारत के वैज्ञानिक दुनियाभर के देशों के वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। अगर सरकार विज्ञान की पढ़ाई को देश में दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाए तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। सरकार को चाहिए कि वह विज्ञान की पढ़ाई की तरफ गंभीरता दिखाए और जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उनकी हर संभव मदद करे, ताकि विज्ञान की पढ़ाई करने वालों की संख्या बढ़े और पढ़ाई के बाद उन्हें विदेशों का रुख न करना पड़े।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सफाई कर्मियों के पुनर्वास एवं सुरक्षा पर गंभीरता से कार्य हो

हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि 2014 के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 453 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई सारे नियमों की मौजूदगी हमारे कानून में है। इसके बावजूद सफाई कर्मचारियों की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यहां बिना किसी सुरक्षा के ही उन्हें सीवर में उतरना पड़ता है। हर साल कई सफाई कर्मचारियों की गंदे नालों से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मन की बात' में इस विषय पर गहन चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 6 के अनुसार सीवर सफाई के लिए किसी भी प्रकार का ठेका अमान्य है। किसी भी व्यक्ति को किसी मजबूरी में अगर नाले में उतारा जाता है, तो उन्हें तमाम सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो व्यक्ति काम कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम जमीनी हकीकत देखें, तो स्थिति बिल्कुल उलट है। हर बार कर्मचारियों की मौत के पीछे एक ही कारण होता है, पर्याप्त उपकरणों का नहीं होना। अतः सरकार को इनके पुनर्वास व सुरक्षा के लिए ठोस योजना लानी चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रामेश्वरम में गुरुवार को भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल 'नए पंबन ब्रिज' पर एक मालगाड़ी चला कर इसका परीक्षण किया गया।

चिंतन

भारत से अलकायदा की जड़ें हमेशा के लिए मिटानी होंगी

अल-कायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी सुन्नी इस्लामवादी संगठन है। इसका खौफनाक चेहरा बार-बार सामने आता रहा है। इस आतंकी संगठन का गठन 1988 में ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्लाह आज़म, और अफगानिस्तान पर सोवियतों के आक्रमण के विरोध करने वाले कुछ अरब स्वयंसेवकों ने किया था, लेकिन जल्द ही यह आतंकी संगठन बन गया। अमेरिका में 26\11 के हमले के बाद इसे पूरी दुनिया में दहशत के नाम से पहचाना गया। गठन के दौरान संगठन के ज्यादातर सदस्य अरबों से बने थे, लेकिन बाद में इसमें अन्य जातीय समूहों के लोग भी शामिल हुए। अल-कायदा का इरादा मुस्लिम देशों में सभी विदेशी और धर्मनिरपेक्ष प्रभावों को हिंसक रूप से हटाने का है। अल-कायदा ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के नागरिक, आर्थिक और सैन्य लक्ष्यों पर हमले किए। संगठन ने धीरे-धीरे पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। अल-कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अल-कायदा चीफ अयमान अल-जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। तब अल-जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। अब इसकी अगुआई ओसामा महमूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। यूएस-अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। बताया जाता है कि इंडियन सब-कॉन्टिनेंट में अल-कायदा के 200 लड़ाके मौजूद हैं। जो रह-रहकर भारत में दहशत फैलाने का षड्यंत्र रचते हैं और हमारे सुरक्षा बल उसे नाकाम कर देते हैं। वीरवार को भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा के एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसका नेतृत्व रांची का इश्तियाक नाम का डाक्टर कर रहा था। उसकी देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी। आतंकवादी मॉड्यूल के सदस्यों को अलग-अलग जगहों पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। छापेमारी में कई तरह के हथियार, गोला-बारूद और आतंकी गतिविधियों से जुड़ी किताबें बरामद हुई हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते समय हिरासत में लिया गया। झारखंड और उत्तर प्रदेश से आठ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ये लोग देश में आतंकी हमलों की तैयारी में थे। अब सुरक्षा एजेंसियां पूरे संगठन की जड़ें खंगालने में लगी हैं। यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता है कि एक बार फिर अलकायदा का नेटवर्क हमला करने से पहले ही दबोचा गया। ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो। बीते दस सालों में यह आतंकी संगठन कई बार ऐसा प्रयास कर चुका है कि किसी तरह भारत पर हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें हर बार विफल कर दिया। दिल्ली में 2015 में तीन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था। दिल्ली पुलिस ने बाद में संगठन के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए साधुवाद की पात्र है, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। इन संगठनों का आमूल-चूल सफाया करना होगा।

बुनियादी ढांचे में लम्बा रास्ता बाकी

विकास

डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी

आजादी के 78 सालों में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से 'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर बढ़ चुका है फिर भी हम आज विश्व बैंक के बुनियादी ढांचा स्कोर में दुनिया में 47वें स्थान पर है। भारत में रेलवे वर्तमान में सबसे बड़ा नियोक्ता है, हालांकि ट्रेनों में आरक्षित सीट पाने के लिए अब भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज हम कृषि मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए 2030 तक बुनियादी ढांचे में 4.51 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की जरूरत है। इसलिए आधारभूत ढांचे पर खर्चा जीडीपी का वर्तमान 4% से बढ़ाकर 10% तक करना होगा।

बुनियादी ढांचा देश की प्रगति की कुंजी है जो उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण होता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बुनियादी ढांचा बहुत ख़राब था। हालांकि, वर्ष 1850 में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक थी। आजादी के 78 वर्षों के बाद, भारतीय आधारभूत ढांचे ने कई मोड़ लेते हुए एक लंबा सफर तय किया है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च, 1950 को राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया।

1948 के औद्योगिक नीति संकल्प ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन एवं संचार पर व्यय 1300 करोड़ रुपये था। यह हर योजना के कुल व्यय का 26% था। तीन पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के आधारभूत ढांचे की नींव रखी। योजना में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के जलविद्युत बांधों- भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और नागार्जुन सागर का प्रावधान किया गया था। अकाल की पृष्ठभूमि को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि थी और भारत की सूखी भूमि की सिंचाई हेतु दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी।

सड़क नेटवर्क : सड़क नेटवर्क परंपरागत रूप से देश के परिवहन बुनियादी ढांचे की रीढ़ रहा है। भारतीय सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1951 में 0.399 मिलियन किमी से बढ़कर आज 6.37 मिलियन किलोमीटर से अधिक हो गई है, जोकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 2021 से राजमार्ग निर्माण की गति 37 किमी/प्रतिदिन तक पहुंच गई है। भारतमाला परियोजना, मोदी सरकार का एक नया प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें 34,800 किमी सड़कें बनाई जाएंगी।

रेलवे : आजादी के बाद भारत को रेल नेटवर्क विरासत में मिला परन्तु भारत आज जहां है वहां पहुंचने के लिए मीलों की यात्रा करनी पड़ी है। भारत को पहली ट्रेन 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच मिली। भारत में स्वदेशी भाप लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1985 के बाद, भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों का युग था। 1947 में 25,170 रूट किमी ब्रॉड गेज (बीजी) रेल नेटवर्क आज 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है।

नागरिक उड्डयन : 1912 में कराची और दिल्ली के बीच पहला घरेलू हवाई मार्ग इंपीरियल एयरवेज, यूके के सहयोग से खोला गया था। भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 'विज़न 2040' रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत में 190-200 कामकाजी हवाई अड्डे होंगे।

बिजली व परमाणु ऊर्जा: भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश ने 1947 में 1,362 मेगावाट से 2023 में, भारत ने 1,968 टेरावाट-घंटे से अधिक बिजली का उत्पादन किया। सरकार ने 2019 तक सभी 18,452 गांवों का विद्युतीकरण किया है, जबकि 1950 में केवल 3,061 गांवों का विद्युतीकरण

किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साहसिक कदम लेते हुए पोखरण में पहला भूमिगत परिक्षण स्माइलिंग बुद्धा (पोखरण-1) 18 मई 1974 को किया था। बाद में अटल जी के नेतृत्व में देश ने 11 और 13 मई 1998 को पांच और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार: देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति लाने के लिए राजीव गांधी को व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। राजीव जी की नीतियों ने दूरसंचार और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया। बाद में 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व में, नई दूरसंचार नीति की घोषणा हुई और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया।

डिजिटल ढांचा : भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से लगभग 56% ग्रामीण भारत से आएंगे। जनधन खाता, जो मोबाइल नंबरों को आधार कार्ड और बैंक खातों से जोड़ता है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और सरकारी योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गया है।

बंदरगाह : विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन तक पहुंच गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन) और सिंगापुर (1.0 दिन) से बेहतर है।

अंतरिक्ष अनुसंधान : इसरो की स्थापना 15 अगस्त, 1969 को हुई थी। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बदौलत अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरे कदम उठाए हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशनों ने ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान दिया है। चंद्रयान-1, मंगल कक्षित्र मिशन, एस्ट्रोसैट और चंद्रयान-2 आदि इसी का उदाहरण हैं।

प्रमुख चुनौतियां और आगे का रास्ता

भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन का अनुमान है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ होता है। आजादी के 78 साल में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से 'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर बढ़ चुका है। फिर भी हम आज विश्व बैंक के बुनियादी ढांचा स्कोर में दुनिया में 47वें स्थान पर है। वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 140 देशों में से भारत का स्थान 70वां है। भारत में रेलवे वर्तमान में सबसे बड़ा नियोक्ता है, हालांकि ट्रेनों में आरक्षित सीट पाने के लिए अब भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बड़ी विडंबना है कि अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर हो जाने के पांच दशक बाद भी देश की दो तिहाई आबादी, सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त अनाज पर निर्भर है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को हकीकत में बदलने के लिए 2030 तक देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 4.51 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की जरूरत है। इसलिए आधारभूत ढांचा पर खर्चा जीडीपी का वर्तमान 4% से बढ़ाकर 10% तक करना होगा।

(लेखक अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जेएनयू के एसो. प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

जयंती

कृष्ण प्रताप सिंह

राधागोबिन्द कर : दुर्गति से कैसे बचे विरासत?

आज, एक महिला चिकित्सक से हैवानियत के मामले को लेकर चर्चित कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज के संस्थापक डॉ. राधागोबिंद कर की जयंती पर यह सोचना किसी त्रास से गुजरने से कम नहीं है कि आज वे हमारे बीच होते तो अपने द्वारा बेहद पवित्र इरादे से स्थापित इस कालेज की ऐसी दुर्गति देखकर कितने व्यथित होते। बहरहाल, यह जानना दिलचस्प है कि 23 अगस्त, 1852 को हावड़ा के रामराजतला स्टेशन के पास पैदा हुए कर को चिकित्सा सुविधाओं को आम लोगों तक ले जाने की प्रेरणा विरासत में मिली थी। उनके पिता दुर्गादास कर ने भी डाक्टर के रूप में अविभाजित भारत के ढाका में आम लोगों के लिए मिडफोर्ड अस्पताल की स्थापना में नींव की ईंट की भूमिका निभाई थी।

उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में राधागोबिंद ने 1880 में कलकत्ता स्थित बंगाल मेडिकल कालेज (जिसे बाद में कलकत्ता मेडिकल कालेज कहा जाने लगा) से डाक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो थियेटर के प्रति अपने आकर्षण से विमुख नहीं हो पाये, जिसके चलते उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बाद में उन्होंने दत्त-चित्त होकर उसे पूरा किया। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उन दिनों इस डिग्री का इतना जलवा था कि उनके प्रायः सारे मित्रों व शुभचिंतकों ने इसे पा लेने के बाद उनके भारत लौटने की उम्मीद छोड़ दी। उनका मानना था कि अब राधागोबिन्द मोटी कमाई के लिए विदेश में ही बस जाएंगे। लेकिन कर उन्हें गलत सिद्ध करते हुए स्वदेश लौटे और बंगाल के बहुविध विपन्न बीमारों की सेवा में लग गए। उन्होंने उन अभावग्रस्त धुर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दीं, जहां दूसरे डाक्टर जाने तक से घबराते थे। बंगला में डाक्टरी की पढ़ाई संभव बनाने के लिए उन्होंने बंगला में चिकित्सा शिक्षा की किताबें तो लिखीं ही, कलकत्ता में एक स्कूल आफ मेडिसिन की स्थापना की भी सोच डाली। धन की कमी उनके इस सपने के आड़े आने लगी तो अपनी कई पुश्तैनी सम्पत्तियां बेच दीं और जनसहयोग भी जुटाया। उनका बड़प्पन कि इतने पापड़ बेलकर उन्होंने उक्त स्कूल खोला तो उससे अपना नाम नहीं जोड़ा। हालांकि कलकत्ता स्कूल ऑफ मेडिसिन से आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक की यात्रा में कई बार उसके नाम बदले और कई नामचीन शख्सियतों से जुड़े।

इस दौरान यह कालेज कर के पथ प्रदर्शन में एशिया के पहले गैरसरकारी मेडिकल कॉलेज के रूप में न सिर्फ बंगाल बल्कि देशभर में हेल्थकेयर के क्षेत्र में प्रकाश स्तम्भ बना, लेकिन कर का नाम इसे देश को आजादी मिलने के बाद 1948 में 12 मई को मिला, जब वे इस दुनिया में नहीं थे। अनंतर, पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई, 1958 को इस कॉलेज को अपने अधीन करके पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध कर लिया। गौरतलब है कि इस कॉलेज का पहला मेडिकल कोर्स तीन साल का था और इसमें बंगला भाषा में चिकित्सा शिक्षा दी जाती थी। गौरतलब है कि यह मेडिकल कालेज राधागोबिंद कर की देश को इकलौती देन नहीं है और उन्हें सिर्फ इसी के लिए दूरदर्शी व परोपकारी नहीं माना जाता। जानकार बताते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में प्लेग की महामारी कोलकाता की सांसें रोकने पर उतर आई तो वे खुद एक बैग में जरूरी दवाएं और उपकरण लिए साइकिल पर विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूम कर उन मरीजों का उपचार किया करते थे, जिनके पास डाक्टर की फीस चुकाने और दवाएं खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे ऐसे मरीजों को बिना फीस लिए देखते और यह जताने पर कि वे दवाएं खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें दवाएं खरीदने के लिए पैसे भी देते। सेवा के इस काम में वे न दिन देखते न रात बल्कि लोगों को उन एहतियातों के बारे में भी बताते जिन्हें बरतकर प्लेग के कहर को कम किया जा सकता था। एक दिन उनकी तरह कलकत्तावासियों को प्लेग से निजात दिलाने में लगी आयरिश भगिनी निवेदिता से भेंट हुई तो दोनों मिलकर एक से ग्यारह हो गये और उनके सेवा कार्यों में समन्वय कलकत्तावासियों के बहुत काम आया। कर ने विदेशों से मंगाई जाने वाली महंगी दवाओं के सस्ते देसी विकल्पों के विकास के लिए भी जी-जान लगाई। अकारण नहीं कि आगे चलकर उन्हें 'बंगाली केमिस्ट' की संज्ञा दी गई और उनका उन्नीसवीं शताब्दी के चिकित्सा विज्ञान व चिकित्सा शिक्षा के उन्नायकों व अग्रदूतों में शुमार किया जाने लगा। 1918 में 19 दिसंबर को उनका निधन हुआ तो उनके पास एक घर को छोड़कर कोई निजी सम्पत्ति नहीं थी। वह घर भी वे अपने द्वारा स्थापित इस कालेज के नाम वसीयत कर गये थे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सत्य में ऐसी शक्ति जो आपको सौ झूठ से बचाए

संकलित

दर्शन

संसार में सत्य को सबसे सुंदर कहा गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी संघर्ष करने के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रखना चाहिए। एक सत्य ही तो है, जो मनुष्य को सौ झूठ बोलने से बचा लेता है। सत्य की ऐसी महत्ता-महिमा होते हुए भी संप्रति संसार में असत्य का बोलबाला बढ़ा है। हालांकि, असत्य का आश्रय लेने वालों को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि अंत में विजय सत्य के खेमे का ही वरण करती है। वास्तव में जहां सत्य है, वहीं धर्म है और जहां धर्म वहीं विजय है। यदि हमारी जीवन रूपी इमारत सत्य रूपी नींव पर खड़ी होगी तभी हम उसे निरंतर ऊंचाई प्रदान करते हुए उसकी प्रकृति को संरक्षित रख पाएंगे। सत्य के महत्व पर बुद्ध ने कहा कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। इसलिए असत्य का परित्याग ही श्रेयस्कर है। मनीषी कहते हैं कि 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हों वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्णरूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते।गांधी जी जैसे महामानव सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची बताते हैं। उसे अपनी नीति का अहम अवयव मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठावान हैं।

रावण की वजह से बना बैद्यनाथ मंदिर

संकलित

प्रेरणा

त्रेता युग की घटना है। रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण ने हिमालय क्षेत्र में शिवलिंग बनाकर कठोर तप किया था। इस तप से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से कहा कि मैं आपका ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता हूं। शिव जी ने रावण की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे, शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद तुम ये शिवलिंग आगे नहीं ले जा पाओगे। रावण ने शिव जी का बात मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में रावण ने गलती से एक जगह शिवलिंग रख दिया। थोड़ी देर बाद वह शिवलिंग फिर से उठाने लगा, लेकिन शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रावन शिवलिंग को उठा नहीं सका। अंत में हिम्मत हारकर रावण वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सभी देवी-देवता, ऋषि-मुनि और अन्य लोग इस शिवलिंग के पास पहुंचे और शिव पूजा की। सभी की पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। सभी भक्तों ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं निवास करें, ताकि भक्त आसानी से दर्शन-पूजन कर सके और उनका कल्याण हो सके। भक्तों की बात सुनकर शिव जी इसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। बाद ये ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत भूमि कब तक होती रहेगी कलंकित

भारत, जो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहां कंजक पूजा होती है, जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, जहां लगभग प्रतिदिन नैतिकता और इनसानियत की राह दिखाते हुए पर्व और त्योहार मनाए जाते है, वहां छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अनैतिक काम छेड़छाड़, रेप जैसे मामले होना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। समय-समय पर ऐसे मामले सुर्खियां बनते हैं। देश अभी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से हुए रेप और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग कर ही रहा है कि इसी बीच देश की सभ्यता और कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यह मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर से है। यहां दो बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत हुई। सवाल यह है कि भारत भूमि कब तक कलंकित होती रहेगी। - राजेश शर्मा, भिलाई

करंट अफेयर

बाइडन की आवाज की नकल करने वाली कंपनी देगी जुर्माना

कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की आवाज की नकल करते हुए न्यू हैम्पशायर के मतदाताओं को भ्रामक कॉल करने वाली कंपनी ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर जुर्माना भरने पर सहमति व्यक्त की है। 'रोबोकॉल' करने वाली कंपनी 'लिंगो टेलीकॉम' ने जुर्माना भरने संबंधी समझौते पर सहमति जताई और इसी के साथ संघीय संचार आयोग (एफसीसी) के प्रवर्तन संबंधी मामले का निपटारा हो गया। आयोग ने पहले 20 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना मांगा था। कई लोग का मानना है कि यह मामला मतदाताओं और लोकतंत्र को प्रभावित करने की एआई की क्षमता से जुड़ी चिंता को दर्शाता है। इस बीच, ये कॉल करने की योजना बनाने वाले राजनीतिक सलाहकार स्टीव क्रेमर अब भी आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन पर 60 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाए जाने का एफसीसी का प्रस्ताव है। ये फोन संदेश 21 जनवरी को न्यू हैम्पशायर के हजारों मतदाताओं को भेजे गए थे। इनमें बाइडन की आवाज की नकल करके गलत संदेश दिया गया था कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के तहत प्राइमरी चुनाव में मतदान करने से मतदाता नवंबर के आम चुनाव में मतदान करने से वंचित हो जाएंगे।

ऑफ बीट

कब्ज से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है

मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में हाल ही में किए गए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में कब्ज और सामान्य आबादी में दिल के दौरे, स्ट्रोक और हार्ट फेल होने के बढ़ते जोखिम के बीच संबंध पाया गया है। शोधकर्ताओं ने यूके बायोबैंक के डेटा का विश्लेषण किया, जो यूनाइटेड किंगडम में लगभग पांच लाख लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का एक डेटाबेस है। शोधकर्ताओं ने कब्ज के 23,000 से अधिक मामलों की पहचान की और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए दवाओं के प्रभाव का हिसाब लगाया, जिससे कब्ज हो सकता है। कब्ज से पीड़ित लोगों (मेडिकल रिकॉर्ड या प्रश्नावली के माध्यम से पहचाने गए) में बिना कब्ज वाले लोगों की तुलना में दिल का दौरा, स्ट्रोक या हार्ट फेल होने की संभावना दोगुनी थी। शोधकर्ताओं ने उच्च रक्तचाप और कब्ज के बीच एक मजबूत संबंध पाया। उच्च रक्तचाप से पीड़ित जिन व्यक्तियों को कब्ज की भी शिकायत थी, उनमें केवल उच्च रक्तचाप वाले लोगों की तुलना में हृदय संबंधी किसी बड़ी घटना का जोखिम 34% अधिक था। अध्ययन में केवल यूरोपीय वंश के लोगों के डेटा को देखा गया। हालाँकि, यह मानने का अच्छा कारण है कि कब्ज और दिल के दौरे के बीच का संबंध अन्य आबादी पर भी लागू होता है।

ट्रेंड

त्रिपुरा को हरसंभव मदद

त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा एनडीआरएफ की टीमों को राज्य में भेज रहा है। हरसंभव सहायता करेंगे।

-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सबसे बड़ा लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर के साथ मेरा खून का रिश्ता है। वहां के लोगों के दिलों में जो दुःख-दर्द है, उसे मिटा कर उन्हें उनका राज्य का दर्जा और प्रतिनिधित्व वापस दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

प्रतिभा का क्षण

जब दीप्ति शर्मा ने द हंड्रेड फाइनल में वह मैच जिताऊ छक्का लगाया, तो यह अत्यंत प्रतिभा का क्षण था। 200 से अधिक रन बनाने और केवल एक बार आउट होने के कारण वह टूर्नामेंट की धड़कन थी।

- मिताली राज, पूर्व कप्तान, क्रिकेट टीम

संसद टीवी पर बहुत कुछ

संसद टीवी पर अर्थपूर्ण वृत्तचित्र और मुद्दे देखने के लिए बहुत कुछ है, जो आपको ज्ञान देते है और मनोरंजन भी करते है। मुझे दिनभर की खबरें देखने के बाद घर पर संसद टीवी देखकर अपना खाली समय बिताना अच्छा लगता है।

-सुभाष घई, फिल्म निर्देशक

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 23 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

शिक्षा मंदिर में शैतान

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में निजी स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण की घटना वाकई स्तब्धकारी है। घटना के बाद हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और स्कूल में तोड़-फोड़ की। आंदोलन के चलते लोकल ट्रेनों की आवाजाही घंटों बाधित रही। सरकार ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात की है। हफ्ते भर पहले तीन व चार साल की दो बच्चियों का सफाईकर्मी अक्षय शिंदे ने यौन शोषण किया। बच्चियों के माता-पिता ने संदेह होने पर पूछताछ की। चिकित्सक द्वारा की गई जांच में असल घटना का खुलासा होने के बावजूद पुलिस ने मामले को पॉस्को में दर्ज करने पर आना-कानी की। गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी

किया। आरोपी को गिरफ्तार कर, प्रधानाचार्य, शिक्षिका व एक सहयोगी को बहरहाल निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही के लिए पुलिस के तीन अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। हैरत है, इतनी छोटी बच्चियों के इर्द-गिर्द पुरुष सहायक क्यों रखे जाते हैं, जबकि नादान बच्चों के साथ स्कूली परिसर में होने वाली यौन शोषण की घटनाएं लगातार दोहराई जा रही हैं। इसके लिए स्कूल प्रशासन दोषी है। जिस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप व हत्या के मामले में सुनवाई कर रही थी; ठीक उसी वक्त मासूमों पर बरपे कहर का खुलासा हुआ। हालांकि देश में यौन हिन्सा का शिकार होने वाले बच्चों को लेकर सख्त कानून हैं, परंतु कानून अपराध के बाद काम करना शुरू करता है। इस तरह की हैवानियत से मासूमों को बचाने का जिम्मा समाज के हर शख्स का है। सरकारी आंकड़े बताते हैं, प्रतिघंटा तीन बच्चों का रेप होता है तथा पांच का यौन शोषण हो रहा होता है। ये बच्चे दरअसल इतने मासूम हैं कि इन्हें गुड टच-बैड टच जैसी बात भी नहीं समझ में आती है, मगर इस तरह की हैवानियत से बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों को सख्ती से निभानी होगी। सहायक, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी व अन्य स्टाफ में सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति हो। मासूम पीड़ितों की जेहनी कैफियत को समझना आसान नहीं है, जिसको वे ता-उम्र झेलते हैं। स्कूल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मासूमों को इस घिनौने अपराध से बचाने में असफल सभी लोगों को सजा जरूर दी जाए, ताकि आइंदा वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करने की हिम्मत न कर सकें।

मोदी की विदेश यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मध्य यूरोप के पार्लैंड और यूक्रेन की यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है। करीब 45 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पार्लैंड गया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू (1955) और इंदिरा गांधी (1967) और मोरारजी देसाई (1979) ने यहां की यात्रा की थी। इसका अर्थ है कि भारत और पोलैंड के बीच दशकों पुराना संबंध है। भारत और पोलैंड के रिश्तों का महत्त्व इसलिए भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह और कोल्हापुर के शाही परिवार ने विस्थापित 6000 पोलिश महिलाओं और बच्चों को अपने यहां आश्रय दिया था। लेकिन दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की युद्धग्रस्त यूक्रेन की यात्रा

पर लगी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में मोदी की रूस यात्रा से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की भृकुटी तनी हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था कि 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेता सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिल रहा है।' वस्तुतः यह दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का संदर्भ और उद्देश्य अमीर देशों की लड़ाई से प्रभावित होने वाले गरीब देशों (ग्लोबल साउथ) की आवाज को बुलंद करना है। मोदी ने बुधवार को पोलैंड की राजधानी वारसा में भी अपना चर्चित वाक्य दोहराया कि यह युग युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद का है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति का मूल मंतव्य है कि सभी देशों के साथ समान रूप से रिश्ते कायम किए जाएं। हालांकि विदेश नीति के जानकारों के एक वर्ग का विश्वास है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका तटस्थ है। लेकिन लोगों को याद होगा कि मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का एक अर्थ यह भी समझ में आ रहा है कि शायद नई दिल्ली दोनों देशों के साथ हितों को देखते हुए रूस और यूक्रेन के साथ अलग-अलग संबंध बनाए। मोदी ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की उम्मीद जताई है। आज मोदी यूक्रेन में होंगे। आगे देखना होगा कि मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के क्या नतीजे सामने आते हैं।

चिंता/भूपेन्द्र गुप्ता

सिफर हो रहा मानव विकास

अस्पताल में अपने पुत्र के इलाज के लिए गए मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि बेटे के बेड के सामने ही दो बच्चे अपने पिताजी का भी इलाज आयुष्मान कार्ड से करा रहे थे और परेशान थे। इसी परेशानी में जब मित्र ने उनसे बातचीत शुरू की और पूछा कि बेटा कहां तक पढ़ाई की है?तो उन्होंने बताया कि वे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। पूछने पर उसने कहा कि उसके कई मित्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, इतना पैसा तो मजदूरी करके भी कमाया जा सकता है फिर पढ़ने की क्या जरूरत है?

यह धारणा कितने प्रतिशत बच्चों में घर कर चुकी है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश के कॉलेज में लाखों खाली पड़ी सीटें संकेत जरूर देती हैं कि यह सोच और यह धारणा धीरे-धीरे समाज में पैर पसार रही है। पैसा ही विकास का मापदंड बन गया है अगर आप पेट भर पा रहे हैं तो आप सफल हैं। संतोष का यह स्तर किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय किसी खाई की तरफ भी ले जा सकता है। शिक्षा समझ और रोजगार पैदा कर सकती है; इन दोनों चीजों पर शासकीय नीतियों ने भरोसा कम कर दिया है। अब उदर पोषण ही भरण-पोषण बन रहा है।

देश की सल्तनत में भी यह विचार निरंतर घर करता जा रहा है कि भौतिक विकास ही दर्शनीय विकास है और विकास के नाम पर अगर हमें लोकप्रियता अर्जित करना है तो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं, भवन और सड़कों का विकास ही विकास के प्रयासों का वास्तविक प्रदर्शन हो सकता है। यही कारण है कि अस्पतालों के नाम पर भवन बन रहे हैं, लेकिन डाक्टर नहीं हैं। डेढ़-दो हजार करोड़ के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं किंतु पढ़ाने वाले दो दर्जन प्रोफेसर भी नहीं हैं। उपचार के लिए 1500 डाक्टरों की भी भर्ती नहीं हो पा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 4 हजार डाक्टर तैयार होते हैं। कॉलेज खोले जा रहे हैं किंतु अतिथियों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। इंजीनियरिंग कालेजों में हजारों सीट खाली हैं। मानव विकास को उपेक्षित करके भौतिक विकास केवल भ्रष्टाचार का ही मॉडल बन सकता है। वह स्थाई और सर्वस्पर्शी विकास नहीं बन सकता न ही ऐसा विकास मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। सरकार के अंदर बैठे हुए योजनाकार भी लगभग इसी धारणा के बंधक प्रतीत होते हैं।

अनमोल वचन

दूसरों को दण्ड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है

-भगवान महावीर स्वामी

भाजपा की राह में कई रोड़े

हरियाणा

नवल किशोर कुमार

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है। इसी के साथ केंद्र में सत्तासीन भाजपा के लिए लोक सभा चुनाव में 32 सीटें पिछड़ने के बाद पहला मौका है जब वह जनता के बीच जाएगी। दोनों राज्यों में उसके लिए परिस्थितियां सम नहीं हैं। एक तरफ जम्मू-कश्मीर में धारा-370 और पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने के कारण आक्रोश है तो दूसरी तरफ हरियाणा, जहां उसकी सरकार है, वहां भी सत्ता विरोधी लहर है। हालांकि इसी लहर को भांपते हुए भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है।

अमूमन भाजपा हरियाणा में जाटों को अन्य जातियों से अलग-थलग करके ही सत्ता प्राप्त करती रही है। या यह कहना भी अतिरेक नहीं कि भाजपा ने हरियाणा में जाटों से उनका राजनीतिक वर्चस्व छीना। वहीं कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में जाट, दलित और मुसलमान रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए चुनाव में विजय दिलाने वाला समीकरण रहा भी है। इसे समझिए कि हरियाणा में जाटों की आबादी कुल आबादी का लगभग 27 फीसद, दलितों की 20.1 फीसद और मुसलमानों की 7 फीसद है। इस लिहाज से देखें हरियाणा की कुल आबादी के पचास प्रतिशत से अधिक आबादी को कांग्रेस अपना समीकरण तय करती है, लेकिन भाजपा ने उसके इस समीकरण को गैर-मुस्लिम और गैर-जाट राजनीति के जरिए तोड़ा और सूबे में सत्तासीन हुई। इसे इस आलोक में देखें कि भाजपा में सवर्ण हिंदू करीब 11 फीसद और गैर-जाट ओबीसी 35 फीसद हैं।

भाजपा को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दलित जातियों को अपने पाले में लाने की आवश्यकता होती है। इस बार भी भाजपा की कोशिश यही होगी कि वह गैर-जाट ओबीसी को महत्त्व दे, जिसका एक उदाहरण वह पहले ही नायब सिंह सैनी को संकटमोचक मुख्यमंत्री बनाकर दे चुकी है। दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने गत 1 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण करने के फैसले को लागू करने का फैसला किया। जाहिर तौर पर इसका असर होगा और यह मुमकिन है कि गैर-जाटव दलित जातियों के बीच भाजपा का असर बढ़े। इसके अलावा उसके निशाने पर मुसलमान होंगे। वह इस चुनावी जंग को भी हिंदू बनाम मुस्लिम के आधार पर लड़ने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जाटों को भी लुभाने की उसकी पूरी कोशिश होगी। अब कांग्रेस की बात करें तो उसके लिए सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि सत्ता विरोधी लहर का सामना जो उसे पूर्व में करना पड़ा था, वह इस बार नहीं होगा। दूसरी

बात यह कि जाटों को भी यह अहसास हो गया होगा कि केवल कांग्रेस ही उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बिठा सकती है। इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना आदि का सवाल उठाकर ओबीसी जातियों के बीच भी अपनी पैठ को गहरा किया है। मुसलमानों के लिए तो इस बार कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

वैसे यदि मुद्दों की बात करें तो खट्टर के खट्टे अनुभव भाजपा पहले ही चख चुकी है। खासकर किसानों को एमएसपी का लाभ देने व तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के साथ खट्टर सरकार ने किस तरह का व्यवहार किया था, यह पूरी दुनिया ने देखा। यह पहली बार हुआ कि आंदोलनरत किसानों को रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी गईं, सड़कों पर कील ठोंकवा दिए गए। लाठीचार्ज की घटनाओं में सैकड़ों किसान जख्मी भी हुए थे। भाजपा के लिए एक और चुनौती महिला पहलवानों की भी है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक आदि खिलाड़ियों के भाजपा के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ चलाए गए आंदोलन और उनका दमन करने की भाजपा की कोशिशों ने उसे महिलाओं के बीच अलोकप्रिय बनाया है। किसानों और महिला पहलवानों के मुद्दे भाजपा के लिए जटिल मसले हैं। वहीं कांग्रेस के समक्ष यह चुनौती है कि वह अपने दलित वोटरों को अपने पाले में रखे और गैर-जाट ओबीसी को भी तरजीह दे। केवल दीपेंदर सिंह हुड्डा के आसरे छोड़ देने से हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति सफल नहीं होने वाली है। हालांकि हरियाणा की दलित राजनीति में कुमारी शैलजा एक बड़ा नाम हैं और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें यदि सूबे में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप पेश नहीं करेगी तो कम से कम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम स्थान देगी, लेकिन दलितों और जाटों के बीच के अपने सामाजिक संबंध मधुर नहीं रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए दलितों और जाटों, दोनों को एक साथ साधना बड़ी चुनौती होगी।

कुल मिलाकर यह कि हरियाणा की यह जंग भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए लगभग एक जैसी है। कहा जा सकता है कि दोनों मैदान के बीचों-बीच खड़े हैं, लेकिन सारा दारोमदार दलित और ओबीसी जातियों पर है। जो इन दोनों जातियों में जितना अधिक वोट पाएगा, जीत उसी के हाथ लगेगी। इसे हम पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में भाजपा को केवल 40 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पहले 2014 में उसे 47 सीटें मिली थीं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कुल 90 सीटों में से 46 सीटों पर जीत आवश्यक होती है। वर्ष 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर देखी गई थी। यह लहर भी सबसे अधिक दलितों में देखी गई थी, जो मिर्चपुर और भगाणा में हुए उत्पीड़न के बाद पनपी थी। तब कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। कुल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर ओमप्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी।

जाहिर तौर पर यह साफ संकेत था कि जाट कांग्रेस से दूर हुए थे। वहीं 2019 में भाजपा अपने बूते सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं थी। उसे समर्थन के लिए सात निर्दलीय के आसरे रहना पड़ा। इस बार जाट कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हुए और उसे 31 सीटें मिली थीं। दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाकर कुल 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहरहाल, इस बार हरियाणा में चुनाव नए माहौल में लड़ा जा रहा है। बहुत कुछ निर्भर इस बार पर करेगा कि जाट, ओबीसी और दलित किस तरफ अधिक गोलबंद होते हैं, लेकिन जो भी होगा, वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेहद दिलचस्प होगा।

> कुल मिलाकर यह कि हरियाणा की यह जंग भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए लगभग एक जैसी है। कहा जा सकता है कि दोनों मैदान के बीचों-बीच खड़े हैं, लेकिन सारा दारोमदार दलित और ओबीसी जातियों पर है। जो इन दोनों जातियों में जितना अधिक वोट पाएगा, जीत उसी के हाथ लगेगी। इसे हम पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में भाजपा को केवल 40 सीटों पर जीत मिली थी

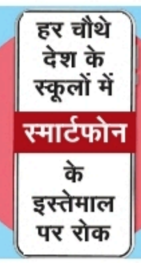

- विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन समेत अन्य तकनीक का कक्षाओं में तभी इस्तेमाल हो जब इससे कुछ सीखा जा सके
- शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व के हर चौथे देश में स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है
- यूनेस्को के तत्वावधान में तैयार ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) की रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल और छात्रों के प्रदर्शन के बीच नकारात्मक संबंध है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

जब राम रहीम और आसाराम जैसे अपराधी पैरोल और इलाज के नाम पर जेल बाहर हों, उ. प्र. सरकार स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस लेने जा रही हो, तब घटना की कड़ी निंदा, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा, कड़े कदम इस सब जुमलेबाजी का औरतों के लिए जमीनी हकीकत के चलते अब कोई मतलब नहीं रहा!

मृणाल पांडे, पत्रकार@MrinalPande1

निगरानी का दायरा बढ़ाना होगा

मंकी पॉक्स **अजय प्रताप तिवारी**

दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की मार से जूझ रही है। इसी बीच मंकी पॉक्स वायरस ने दस्तक दे दिया है। मंकी पॉक्स वायरस इन दिनों दुनिया के लगभग 116 देशों में दहशत मचा रखा है। कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला मंजर है जब दुनिया एक बार फिर से सहमी हुई है। मंकी पॉक्स वायरस के विकराल रूप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है। कई अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स वायरस को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पहले ही घोषित किया जा चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व में कई महामारियों को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा के रूप में घोषित किया जा चुका है, जिसमें से कोविड-19, इबोला वायरस, जीका वायरस तथा पोलियो शामिल है। मंकी पॉक्स का पहला संक्रमण वर्ष 1958 में अनुसंधानकर्ताओं ने बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसे लक्षण दिखाई दिए थे जिसे 'मंकी पॉक्स' नाम दिया गया था। मंकी पॉक्स वायरस का प्रभाव मनुष्यों में 1970 के करीब कांगो के रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे में देखने को मिला था। इसके बाद 11 अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। शुरुआती दौर में मंकी पॉक्स वायरस का कहर अफ्रीकी देशों तक सीमित रहा। अफ्रीकी देशों के बाहर मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला 2003 में अमेरिका में देखा गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस वायरस का प्रभाव कई अन्य देशों में देखने को मिलने शुरू हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में मंकी पॉक्स वायरस का प्रभाव बढ़ा है। इस्राइल में 2018, 2019 में यूके और सिंगापुर में मंकी पॉक्स वायरस का मामले देखने को मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में तक मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या लगभग 16 हजार से ऊपर पहुंच चुकी है तथा 600 के करीब लोगों की जानें जा चुकी है। मंकीपॉक्स वायरस का प्रभाव 2022 में भी देखने को मिला था। तब करीब 116 देशों में 99,176 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 208 व्यक्तियों की मौत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जुलाई 2022 में भी मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। वर्ष 2023 में मंकीपॉक्स से करीब 11हजार लोग प्रभावित थे जबकि 500 लोगों की मौत

हुई थी। मंकीपॉक्स वायरस के प्रभाव को लेकर भारत के संदर्भ में बात करें तो आखिरी मामला मार्च 2024 में केरल राज्य में देखने को मिला था, जबकि 2022 में कुल 30 व्यक्तियों में यह संक्रमण पाया गया था। फिलहाल मार्च 2024 के बाद अभी तक कोई मामला मंकीपॉक्स को लेकर भारत में नहीं दर्ज किया गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मंकीपॉक्स फैल रहा है। मंकीपॉक्स के बढ़ते प्रभाव से मानव समाज पर कई प्रकार के दबाव बढ़ सकते हैं। जब कोई संक्रमण वैश्विक स्तर पर फैलता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था, आयात-निर्यात, पर्यटन एवं उद्योग के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। संक्रमण के चलते लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं तो इसका असर रोजगार, कामगारों और बाजारों पर पड़ता है। कार्यबल में गिरावट आती है जिसका प्रभाव उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, काम का दबाव बढ़ता है। इस बीमारी को लेकर भारत की चिंता जायज है। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क दिख रही है। इस बाबत उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें विदेश यात्रा से भारत वापसी कर रहे यात्रियों पर नजर रखने और स्क्रीनिंग करने की हिदायत दी गई है। संक्रमण के प्रारंभिक उपचार के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार करने की बात भी की जा रही है। वर्तमान संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली में 32 प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली में मंकीपाक्स को ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए छह अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंकीपॉक्स की रोकथाम के लिए सरकार को व्यापक और समन्वित प्रयास करने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और सुदृढ़ करनी चाहिए। सीमा और यातायात नियंत्रण, निगरानी और अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी, संचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कदम उठाकर ही मंकीपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत को घुमंतु और पालतू पशुओं के लिए निगरानी केंद्र स्थापित करना चाहिए तथा समय-समय जांच परीक्षण करते रहना चाहिए ताकि जानवरों में पनप रहे संक्रमण का पता समय रहते लगाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों को मंकीपॉक्स जैसे अन्य विशेष प्रकार के संक्रमण के प्रसार के पैटर्न और कारणों की जांच करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। देश-दुनिया में पनप रहे वायरसों के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना होगा। भारत समेत पूरी दुनिया को सजग रहना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि निकट भविष्य में संक्रमण ही मानव के सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे।

वास्तविक स्वरूप **श्रीराम शर्मा आचार्य**

मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसका संबंध परमात्म तत्त्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर संसार को प्रभावित करने लगती है और लोग उस व्यक्ति को अवतार, ऋषि, योगी आदि के रूप में पूजने और मनन करने लगते हैं। वह दिव्य पुरुष बन जाता है। परमात्म तत्त्व वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सर्वोपरि सत्ता है जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती, इसका नियमन और नियंत्रण करती है और जिससे दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत, असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु-अणु का मूलाधार वह परमात्म तत्त्व ही है। सब कुछ इसी से बनता और उसी चेतन शक्ति से गतिशील होता है। आकार-प्रकार में भिन्न दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी एक उसी तत्त्व का अंश है। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिन्दु भिन्न दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप होता है और समुद्र की सारी विशेषताएं उसमें होती हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन सीमित और असीमित के मिथ्या के भेद के साथ तत्त्वतः एक ही है। जो जीवात्मा है, वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जानना ही आत्म ज्ञान है। जिन-जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उन्होंने अपना अनुभव प्रकट करते हुए उसकी इस प्रकार पुष्टि की है कि हम अपना जीवन परमात्म तत्त्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं अथवा हमारे जीवन का उस परमात्म तत्व से ऐक्य है। हममें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम और हमारा ईश्वर एक सत्य के ही दो नाम और दो रूप हैं। यही ज्ञान अथवा अनुभव आत्मानुभूति आत्म प्रतीति अथवा आत्म ज्ञान के अर्थ में मानी गई है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है। वह सर्वशक्तिमान और जिसको अपने प्रति निर्बलता की प्रतीति होती है वह निर्बल बन जाता है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना है।

रीडर्स मेल

इतिहास को तोड़ें-मरोड़ें नहीं

इतिहास विश्व सबसे बड़ी अदालत होती है और इतिहास का निर्णय हमेशा शक्तिशाली के पक्ष में होता है। किसी देश को मिटाना हो तो उसके इतिहास से वंचित कर दो, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत हजार वर्षों के संघर्षकाल के बाद भी सामर्थ्यवान है क्योंकि हम चिर पुरातन, नित्य नूतन रहे, परंतु वर्तमान में भारत के इतिहास में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शक, हूण, मुगल और अंग्रेज आक्रांतों की तरह ब्राह्मणों को भी असहिष्णु घोषित करने की साजिश रची जा रही है ताकि हिंदू और बौद्ध की मध्य बैर भाव की दीवार खड़ी हो सके। वामपंथी इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विध्वंस कहते हैं। सर्वप्रथम पुष्यमित्र के ब्राह्मण होने का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा बौद्ध धर्म विरोधी हिंसा के उल्लेख 400 से 1700 साल बाद के हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले हूण इस्लाम ने बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया और अनेकों बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करने वाले बख्तियार खिलजी था, जिसने अनेकों पुस्तकालय और मठ मंदिर, बुद्ध विहारों को ध्वस्त किया। अतः हिंदू और बौद्ध का आपसी हिंसा का कोई प्रमाण नहीं। हिंदुओं और बौद्ध धर्मावलंबियों में कभी दुर्भावना और वैमनस्य नहीं रहा।

रोहित मुखिया, ई मेल से

चारित्रिक पतन का जिम्मेदार कौन

तमाम सकारात्मक उन्नति के बावजूद आज देश में चरित्रहीनता इस कदर हावी है कि पाश्विक प्रवृत्तियां पीछे छूट गई है। कोलकाता में ट्रेनी प्रशिक्षु डॉक्टर से गैंगरेप फिर हत्या, तमिलनाडु में छात्राओं के फर्जी एनसीसी कैंप में छेड़छाड़ और यौन शोषण, महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं बताती है कि आज चारित्रिक पतन किस स्तर तक पहुंच गया है? इस तरह की घटनाओं के विरोध में जब जनमानस सड़क पर उतरता है तो हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाएं सामने आती है। आज परिवार से लेकर समाज, स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सैर सपाटे करने वालों के लिए नैतिक शिक्षा और उन्हें संस्कारों की बड़ी जरूरत है जो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल सके। इसके साथ ही कठोर और त्वरित दंड व्यवस्था भी जरूरी है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर, मप्र

महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो

कुशल नौकरशाही से सुशासन आता है और इसी सकारात्मक सोच के चलते मोदी सरकार ने सिविल सेवा में 45 सीधी भर्ती को हरी झंडी दी, लेकिन गठबंधन की सरकार जो है वह ऐसे ही चलती है। जहां कभी कोई घटक दल तो कभी कोई घटक दल टांग खींचता है। इससे पहले अपने दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कानून-जो किसानों और देश दोनों के लिए बेहतर था-उनको दबाव में आकर वापस लिया था। इस निर्णय की वापसी के बाद मोदी सरकार एक कमजोर सरकार के रूप में दिखेगी और विपक्ष और घटक दल दोनों भिन्न भिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री पर ऐसे ही दबाव बनाते रहेंगे। तो अब इससे सबक लेते हुए सरकार को भविष्य में कोई भी संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आपस में और विपक्ष के साथ भी विचार करना चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 9
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी